पूरे हो रहे हैं डॉ. आम्बेडकर के सपने, पर करना बहुत कुछ है

दुनिया जानती है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर का अभूतपूर्व योगदान रहा है इसलिए उन्हें संविधान निर्माता के नाम से पहचाना जाता है। भारतीय संविधान के कारण ही भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। देश के इस लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए आज हमें सजग रहने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के सूत्रधार एवं चिंतक डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा देश व समाज के लिए अनुकरणीय व अग्रणीय रही है। वे एक प्रख्यात मनीषी, समाज सेवक, नायक, विद्वान, दार्शनिक एवं धैर्यवान बौद्धिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना जीवन समग्र भारत के कल्याण की कामना हेतु उत्सर्ग कर दिया था। विशेषकर 80 प्रतिशत उन दलित, सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त लोगों के लिए, जिन्हें शोषण व पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉ. आंबेडकर का जीवन संकल्प रहा। डॉ. आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू में सूबेदार रामजी शकपाल एवं भीमाबाई की चौदहवीं संतान के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता का प्रभाव रहा। डॉ. भीमराव सातारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद प्रिय रहे। यही शिक्षक डॉ आंबेडकर के लिए उन पर सामाजिक अत्याचार और लांछन की तेज धूप में बादल रूपी छांव बन गए थे। डॉ. आंबेडकर की सोच थी कि, 'समाज को श्रेणीविहीन और वर्णविहीन करना होगा क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है, वे दलित समझे जाते थे।' बाबा साहेब ने इसी भेदभाव के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर समाज को जागरूक करने की कोशिश की।वे कहते थे कि, 'छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है।' उन्होंने कहा था, 'हिन्दुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिन्दुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं है, बल्कि ग्रहिष्णु, सहिष्णु व चलिष्णु है। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव आंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर सन् 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया था। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थ नीति का अध्ययन किया और विद्वता हासिल की। चूंकि विदेश में भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। बाबासाहेब अम्बेडकर की विद्वता का प्रमाण यह है कि वे 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया था। बाबासाहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई मात्र 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि यह विश्व का सबसे बडा मतांतरण था। बाबासाहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनेवाले महान बौद्ध भिक्षु "महंत वीर चंद्रमणी" ने उन्हें "इस युग का आधुनिक बुद्ध" कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से "डॉक्टर ऑल सायन्स" नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबासाहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष रहे हैं। डॉ. आंबेडकर ने अमेरिका की एक सेमिनार में 'भारतीय जाति विभाजन' पर अपना मशहूर शोध-पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की खूब प्रशंसा हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वसम्मति से डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर सन् 1949 को डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में (315 अनुच्छेद का) भारतीय संविधान पारित हुआ। डॉ. भीमराव आंबेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए थे। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर सन् 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में सोते समय घर पर ही हो गई। सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉ. आंबेडकर का ध्येय था कि 'सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार प्रतिष्ठा करना', जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे।' डॉ. आंबेडकर ने सावधान किया था कि, '26 जनवरी सन् 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस विरोधाभास को दूर करना होगा।' हालांकि समय के साथ इसमें काफी कमी आई है और हम डॉ. आंबेडकर के सपनों को पूरा करने में लगातार सफल हो रहे हैं।

विपक्ष के चूहों की भागदौड़ और प्रधानमंत्री मोदी

आरती कुमारी

अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीतकर यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वोत्तर भारत में उसका कोई विकल्प नहीं है । इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कराकर भाजपा पर चुनाव जीतने का आरोप लगाने वाले विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर उसने अरुणाचल प्रदेश में 10 सीटों पर भाजपा को निर्विरोध क्यों जीतने दिया? यह ठीक है कि देश में इस समय भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अभी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार अभी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के दायरे से बाहर सोचने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाई है, पर इस सबके उपरांत भी देश का जागरूक मतदाता अपनी दैनिक आवश्यकताओं पर कहीं ना कहीं समझौता करके देश के लिए भी सोच रहा है। यही कारण है कि उसे इस समय बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। बात यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी की करें तो केजरीवाल पर पूरा देश बहुत अधिक आंदोलित नहीं हुआ है। जो थोड़ी बहुत क्षति हो रही थी वह 'आप' के नेता संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद पूरी हो गई है। भाजपा के लिए यह बहुत ही अच्छा रहा कि संजय सिंह को इस समय जेल से जमानत मिल गई, इससे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता कहीं आहत दिखाई दे रहे थे , वे सब संजय सिंह ने अपने बड़बोलेपन से आकर संभाल लिए हैं। इससे जन सामान्य प्रभावित होने से बच गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सारा चुनाव इस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाकर केंद्रित कर दिया है । केजरीवाल की गिरफ्तारी ने चुनाव का विमर्श परिवर्तित कर दिया है। भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष का 'इंडी' गठबंधन आगे बढ़ा था, उसी मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए 'कैश' कर लिया है। पीएम श्री मोदी की यह अनोखी राजनीतिक कार्य प्रणाली है कि वह दूसरे के मुद्दों को अपने लिए भुनाने में हद दर्जे की क्षमता रखते हैं। जिस आक्रामक ढंग से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को धार दी है, उससे विपक्ष घबराकर इस समय बचाव की मुद्रा में आ गया है। प्रधानमंत्री का बार-बार यह कहना कि इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, लोगों के गले उतर रहा है। इस गठबंधन के नेता जब अपने अगल-बगल खड़े नेताओं की ओर देखते हैं तो उन्हें एक दूसरे में से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आने लगती है। जिससे उनके स्वर अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। यह पहली बार हुआ है जब दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया है कि उनकी आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राजनीति में आई थी, आज वह उसी में डूब चुकी है और मेरा इन परिस्थितियों में यहां रहना अब असंभव हो गया है। मंत्री राजकुमार आनन्द के द्वारा लगाये गये इस प्रकार के आरोप से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं । हम देख रहे हैं कि मंत्री के इस्तीफा के बाद विपक्ष के नेताओं के स्वर केजरीवाल को लेकर और भी अधिक मद्धम पड़ गए हैं। विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में वह जितना ही अधिक केजरीवाल का बचाव करेंगे, उतना ही उनके लिए घातक होगा। दूसरी बात जो इस समय भाजपा की जीत को बहुत अधिक सुनिश्चित करती दिखाई दे रही है, वह यह है कि देखने के लिए तो इंडी गठबंधन अस्तित्व में आ गया है, पर विपक्ष के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह गठबंधन अभी से लंबी सांसें लेने लगा है । जिससे पता चलता है कि चुनाव के बाद तो इसे निश्चित रूप से मर जाना है। यद्यपि देश के लोगों ने इसे अभी से मरा हुआ समझ लिया है। केरल में कम्युनिस्ट दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए अभी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए इस समय पूरे देश में अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढना कठिन हो गया है। जबकि उनकी मां सोनिया गांधी पहले ही अपने आप को सुरक्षित रखते हुए राज्यसभा में पहुंच गई हैं। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नकारात्मक संकेत गया है । पार्टी ने जिस प्रकार अपने आप को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी के हाथों मरने दिया है, उससे कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप प्रभावित हुआ है। माना जा सकता है कि यह सब कांग्रेस 'बड़ा दिल' दिखाते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कर रही है, पर सच यह है कि इसका दायरा सिमटता जा रहा है। तेजी से उसके कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो रही है। हम अपने दौर में एक 'बड़े वृक्ष' को गिरते हुए देख रहे हैं। इतिहास के लिए कौतूहल का विषय है कि यह 'बड़ा वृक्ष' गिरते हुए धरती पर थोड़ा सा भी कंपन लाने की क्षमता खो चुका है। जिस समय कांग्रेस का साम्राज्य सिमट रहा है उसी समय एक नई घटना भी घटित हो रही है कि कांग्रेस के मित्र ही उससे मित्रता बनाकर उसकी हत्या करने की तैयारी कर रहे हैं। जिसे कांग्रेस समझकर भी नहीं समझ रही है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संभले और कभी सत्ता में लौटे। इसी प्रकार दिल्ली के लिए केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस कभी सत्ता में लौटे। इसी प्रकार उनकी सोच पंजाब के लिए भी हो सकती है । ऐसे ही अन्य प्रदेशों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। इसी प्रकार की परिस्थितियों के चलते बंगाल को कांग्रेस पूरी तरह खो चुकी है। इस समय विपक्ष किसी भी ऐसे मुद्दे को प्रभावी रूप से नहीं उठा पा रहा है जिससे भाजपा को सत्ता में आने से रोक सके। विपक्ष के सभी नेताओं को अपने-अपने कपड़ों में लगी आग को बुझाने की चिंता है। इनमें से कई ऐसे नेता हैं ,जिनकी ओर आग बढ़ती जा रही है और वह उससे बचकर भागते हुए इधर-उधर छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूहों की इस भागदौड़ को देश की जनता बहुत ही कौतूहल और उपहास भरे अंदाज से देख रही है। सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की ओर एक बार फिर चलते हैं। इस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जिस प्रकार से तैयार किया है, उसमें नरेंद्र मोदी का डर सर्वत्र व्यापता हुआ नजर आता है। जितना ही इस घोषणा पत्र का अध्ययन किया जाएगा, उतना ही इसका मुस्लिम तुष्टिकरण का स्वरूप प्रकट होता चला जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने अपने इतिहास के उस भूत को आज भी जिंदा रहने दिया है, जिसे तुष्टीकरण के नाम से उसने आजादी से पहले और आजादी के बाद आज तक निरंतर जीवित बनाए का काम किया है। मुस्लिम तुष्टिकरण की कांग्रेस की इसी नीति को कांग्रेस से अलग के सेकुलर राजनीतिक दलों ने भी अपनाया है। मुस्लिम तुष्टिकरण का दूसरा अर्थ होता है हिंदू विरोध। हिंदू विरोध का अर्थ होता है इस देश की मौलिक चेतना के साथ विद्रोह करना। मौलिक चेतना के साथ विद्रोह का अर्थ है भारतीयता को नीलाम करना। बस, यही वह चीजें हैं जो कांग्रेस को वर्तमान परिस्थितियों में एक निरंतर सतत जागरूक प्रक्रिया और विचारधारा की पार्टी नहीं बनने दे रही हैं। जितना ही कांग्रेस अपनी परंपरागत तुष्टिकरण की राजनीति को धार देने का काम करेगी, उतना ही मोदी की गारंटी अपना रंग दिखाएगी। जितना ही कांग्रेस अपने आप को भ्रष्टाचारी केजरीवाल जैसे नेताओं के साथ खड़ा करके दिखाएगी , उतना ही भाजपा का कमल खिलेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी दल स्वयं ही भाजपा के प्रचार में सहायक हो रहे हैं।

क्यों घटती जाती तादाद लोकसभा में आजाद उम्मीदवारों की?

आर.के. सिन्हा

बुजुर्ग हिन्दुस्तानियों को याद होगा ही कि एक दौर में वी.के.कृष्ण मेनन, आचार्य कृपलानी, एस.एम. बैनर्जी, मीनू मसानी, लक्ष्मीमल सिंघवी, इंद्रजीत सिंह नामधारी, करणी सिंह, जी. जी. स्वैल जैसे बहुत सारे नेता आजाद उम्मीदवार होते हुए भी लोकसभा का कठिन चुनाव जीत जाते थे। पर अब इन आजाद उम्मीदवारों का आंकड़ा लगातार सिकुड़ता ही चला जा रहा है। अगर 1952 के पहले लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो हमें इन विजयी आजाद उम्मीदवारों की संख्या 36 मिलेगी। तब इनका समूह कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। यानि किसी भी गैर-कांग्रेसी दल से बड़ा था। निवर्तमान लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ तीन रह गई थी। अभी तक मात्र 202 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे हैं। बेशक, लोकसभा का चुनाव अपन बलबूते पर लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की दरकरार रहती है। इसके बावजूद भी अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो इतना तो माना ही जा सकता है कि उसका आम जनता में गहरा प्रभाव है। पहले लोकसभा चुनावों के बाद 1967 के लोकसभा चुनावों में 34 आजाद उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे थे। देश में इमरजेंसी लगने के बाद 1977 में चुनाव हुआ। तब सिर्फ सात आजाद उम्मीदवार सफल रहे। यह संख्या 1980 में मात्र चार रह गई। 1984 और 1989 के लोकसभा चुनावों में क्रमशः 9 और 8 आजाद उम्मीदवार ही निर्दलीय रूप से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कह सकते हैं कि हरेक लोकसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले कुछ न कुछ विजयी रहे हैं। बेशक, ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जुझारू प्रतिबद्धता के साथ कुछ काम तो करते होंगे। वर्ना ये सब लोकसभा में कभी नहीं पहुंच पाते। खासतौर पर तब जबकि चुनावों में धन का इस्तेमाल तो बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप में बहुत बुलंद शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें से कुछ मनीषी भी रहे हैं। कृपलानी जी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधी जी के सबसे उत्साही और विश्वासपात्र शिष्यों में से एक थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी कार्य किया था। लक्ष्मीमल सिंघवी जैसे सरस्वती पुत्र भी सदियों में पैदा होते हैं। वे ख्यातिलब्ध न्यायविद, संविधान विशेषज्ञ, कवि, भाषाविद एवं लेखक थे। वे "धर्मयुग" में विधि संबंधी मामलों में खूब लिखते थे। जब मैं "धर्मयुग" में आवरण कथाएं लिखा करता था। उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। वे 1952 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। चाहे सांसद रहे हों या किसी और संस्था से जुड़ गए हों, लेकिन उन्होंने वेतन के रूप में हमेशा एक रुपया ही लिया था। आप कानपुर में जाकर अब भी एस.एम. बैनर्जी के बारे में पूछ लें । आपको लोग उनके तमाम किस्से सुनाएँगे। वे एक विख्यात मजदूर नेता थे। वे पश्चिम बंगाल से कानपुर में नौकरी करने के लिए आए थे। कानपुर को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया था। कोलकाता से आये मजदूर नेता एस.एम. बैनर्जी ने 1957 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की तो 1962, 1967 और 1971 तक जीत का सेहरा वही पहनते रहे। शायद कानपुर अकेला शहर होगा, जहां चार बार लगातार कोई निर्दलीय सांसद चुना गया हो। आपको विजयी हुए निर्दलीय उम्मीदवारों में इस तरह के कई नाम मिल जाएंगे जो उस लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए, जहाँ से उनका उस क्षेत्र से कोई सीधा संबंध नहीं था। वहां पर जनता से जुड़कर और उनके सुख-दुःख का हिस्सा बनकर वे वहां के हो गए। कृपलानी जी सिंध (अब पाकिस्तान) से आए थे। वे बिहार से सांसद बने। इंदरजीत सिंह नामधारी का परिवार देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से बिहार आकर बस गया था। वे बरसों बिहार के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे। बिहार के विभाजन के बाद वे झारखंड में सक्रिय हो गए। इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पहले विधान सभा अध्यक्ष बने। वे वनांचल राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिसने दक्षिण बिहार के लिए अलग राज्य की मांग की थी। अब डॉ. करणी सिंह की भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि नई पीढ़ी को उनके संबंध में कम जानकारी हो। वे देश के चोटी के निशानेबाज थे। डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज किसी खिलाडी के नाम पर रखा गया राजधानी का पहला स्टेडियम माना जा सकता है। आमतौर पर यह नहीं होता। ड़ॉ. करणी सिंह रेंज का निर्माण 9 वें एशियाई खेलों के निशानेबाजी के मुकाबलों के लिए 1982 में हुआ था। डॉ. करणी सिंह बीकानेर के राज परिवार से थे। वे देश के पहले निशानेबाज थे जिन्हें 1961 में 'अर्जुन पुरस्कार' देकर सम्मानित किया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे राज परिवार से आने के बावजूद आम जनता के सुख-दुख में शामिल होते रहते थे। वे 1952 से 1977 तक लगातार पांच बार सांसद रहे। उन्होंने दो चुनाव में 70 से 71 फीसदी मत प्राप्त किए थे। उनके बाद इस मत प्रतिशत को प्राप्त करने में कोई भी पार्टी प्रत्याशी सफल नहीं हो पाया। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार सांसद रहने का रिकॉर्ड करणी सिंह के नाम है। अब लोकसभा चुनाव का उत्सव देश देख रहा है। सारा देश जानता है कि अब चुनाव लड़ना कितना खर्चीला हो गया है। कैंपेन इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी इंसान आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से पहले कई बार जरूर सोचता होगा। इसके बावजूद तमाम जनता के बीच में काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावी रणभूमि में कूदने से पीछे नहीं रहते। उम्मीद करनी चाहिए कि देश आगामी लोकसभा में पहले से अधिक आजाद उम्मीदवारों को देखेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष राशि–आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। आज ऑफिस के किसी कार्य में सीनियर्स की मदद से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज घर में बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम बितेगा। माता पिता बच्चो को कोई अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। छात्रो को आज ऑनलाईन कुछ नया सीखने को मिलेगा।

वृष राशि–आज आपका दिन अच्छा रहेगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। अपना समय शॉपिंग में बिता सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगो को आज किसी मल्टी नेशनल कम्पनी से कॉल आ सकती है। दांपत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। कॉम्पटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए।

मिथुन राशि– आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कोई नया प्लान बनायेंगे। किसी बुजुर्ग महिला की सेवा का अवसर मिलेगा इसे आप सौभाग्य के रूप में समझे। आज आपके ज्यादातर सोचे हुए कामों पूरे हो जाएंगे। छात्र कोशिश करते रहे, सफलता के योग बने हुये है।

कर्क राशि– आज आपका दिन ठीक रहने वाला है। आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। घर में खुशी का महौल बना रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में उलझे रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स कॉलेज में कुछ नया सीखेंगे और पढ़ाई की तरफ झुकाव बढ़ेगा। रोज की अपेक्षा आज व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा।

सिंह राशि– आज आपका दिन बढिया रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है समाज हित में किये गये कामों की तारीफ़ हो सकती है। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर.. पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है।

कन्या राशि–आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रहीं कड़ी मेहनत आज आपको सफल बना सकती है। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिन्हे आप बखूबी निभाएंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए आस-पास के कई लोग आपको सलाह देगें। जीवनसाथी पर भरोसा बनायें रखें, रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से आप ठीक रहेंगे। पारिवारिक समस्या दूर होगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी।

तुला राशि–आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। आज आपको पुरानी बातें याद आ सकती हैं। आज व्यापारिक मामलों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढने की प्रेरणा आपको मिलेगी।

वृश्चिक राशि– आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। इस राशि की महिलाएं जो घर पर ही कोई बिजनेस करने की सोच रही है उनके लिए आज का दिन अच्छा है। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न करें ,अन्यथा वह काम दोबारा करना पड़ सकता है। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय ईश्वर की आराधना के लिए निकालें मन शांत रहेगा। आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे।

धनु राशि– आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। अगर आप नयी जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर लें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा कुछ नया सीखने को मिलेगा। लवमेट अपने मन की बात शेयर करेंगे। इससे रिश्तों में मधुरता बनेगी। शाम को परिवार के साथ किसी जरूरी मामले पर बात होगी जहां आप खुलकर अपनी राय रखेंगे।

मकर राशि–आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आपको अपनी सोच सकारात्मक बनाये रखने की आवश्यकता है। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित होंगे और ज्यादा समय पढ़ाई में बीतेगा, यह देखकर आपके घर को खुशी होगी। इस राशि के टैक्सटाइल व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बनेगा। मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाए, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा।

कुंभ राशि– आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में कार्यशीलता के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। आज आपके तय किए काम समय से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे होने से प्रसन्नता होगी। दोस्ती में चल रही अनबन को ख़त्म करने के लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आज आपको कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलायेगी। मां दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपके सभी रूके हुए काम बनेंगे।

मीन राशि– आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आज आप धार्मिक कार्यों में रूचि लेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। माता पिता से आशीर्वाद लेने से आपकी सभी परेशानियों का हल मिलेगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। जीवनसाथी के साथ आज आप कहीं घूमने जाएंगे। मां कूष्मांडा के आगें हाथ जोडें, रूकें हुए काम पूरें होंगे।

सूडोकु नवताल- 7035

★★★★☆ मध्यम

9		6		3		4		8
	2				9		7	
4			1	6				2
		8			2		3	
1		4				2		5
	3		5			8		
7				9	5			3
	8		6				4	
6		2		7		5		1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7034 का हल

3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7

शब्द सामर्थ्य -026

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. अभिमान, घमंड, अनुमान 4. बादल, मेघ, जलद (सं) 6. अधिकार वाला, अधिकारी 8. गति, सामंजस्य, समा जाना 10. कारावास, जेल 11. जोर, शक्ति, जान, सांस 12. राजाओं के रहने का भवन 15. मालामाल, अमीर, धनवान 18. नाव खेने का यंत्र 20. 'खन' ध्वनि उत्पन्न होना, पायल आदि का शब्द करना 21. मार डाला हुआ, घायल किया हुआ 22. हमेशा, आवाज 23. आग की लपट, ज्वाला 24. झगड़ा, तकरार 25. हीरा।

ऊपर से नीचे

1. दोषी, अपराधी 3. ताश में नौ अंक वाला पत्ता 4. झंडा, पताका 5. गहरा कीचड़, पंक 7. बूंद, अंश 9. मृत्यु के देवता 13. संसार, दुनिया, जग 14. हुजूर, जनाब, सम्मान सूचक एक शब्द (उ.) 16. सच्चा, धर्मनिष्ठ, ईमानवाला 17. अनूठा, बांका, अनुपम, छैला 18. आश्रय, शरण 19. साधुवाद, प्रशंसा 20. पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत संबंधी अनेक बातें लिखी जाती है, एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग 23. गम, मातम, दुख।

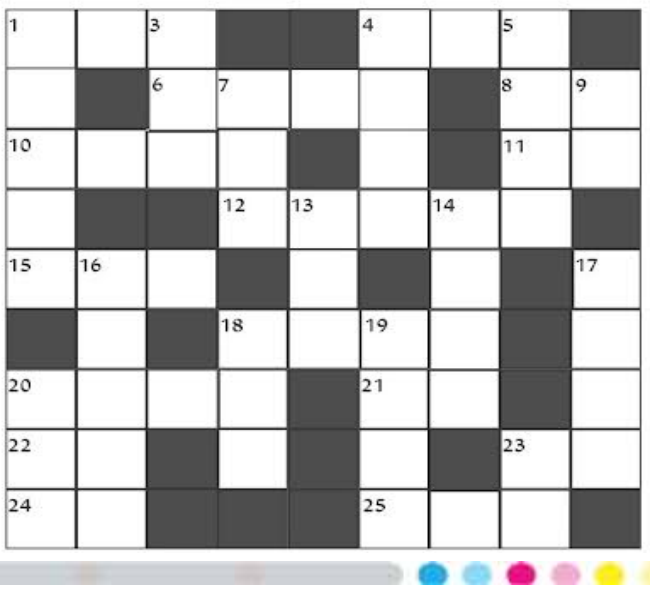

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 025 का हल

स्मृ	ति	■	पा	व	क	■	बे	ल
■	र	ज	नी	च	र	■	■	ट्टू
मु	स्का	न	■	न	म	की	न	■
सा	र	■	स	■	■	ट	ख	ना
फि	■	अ	जा	य	ब	■	रा	जा
र	च	ना	■	था	ल	■	■	य
■	■	धि	■	र्थ	■	स	मा	ज
उ	प	कृ	त	■	आ	वा	ज	■
ल्लू	■	त	■	■	ब	ल	रा	म

भावेश भाई भंडारी से कुछ तो सींखे भ्रष्टाचारी

एक तरफ जहां बड़े-बड़े राजनेता और अधिकारियों के द्वारा अवैध तरीके से धन जमा करने की खबरें रोज सुर्खियां बनती हैं वहीं गुजरात राज्य के साबरकांठा से एक ऐसी खबर आयी है जिसने न सिर्फ सबको चौंका दिया है बल्कि समाज को एक दिशा भी दिखाई है। भ्रष्टाचार से धन कमाने वालों के मुंह पर यह खबर किसी तमाचे से कम नहीं है। साबरकांठा जिले का यह कारोबारी परिवार यूं ही नहीं सुर्खियों में है। हिम्मतनगर के रहने वाले व्यावसायी भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति दान कर सन्यास लेने का फैसला किया है। उनके इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। भावेश भाई को जानने वालों का मानना है कि भंडारी के परिवार का हमेशा से जैन समाज की ओर झुकाव रहा है। अक्सर इनके परिवार की मुलाकात दीक्षार्थियों और गुरुजनों से होती रहती थी। भावेश भाई और उनकी पत्नी ने अपनी एशो-आराम की जिंदगी त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा लेने और सन्यासी जीवन बिताने का फैसला किया है। भावेश बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनका कारोबार साबरकांठा से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। साबरकांठा के हिम्मतनगर में धूमधाम से चार किलोमीटर लंबी एक शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान सन्यास ग्रहण करने जा रहे भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी 200 करोड़ रुपये की संपत्ति दान में दे दी। उन्होंने अचानक कारोबारी से जैन धर्म का दीक्षार्थी बनने का फैसला लिया है। खबर है कि 22 अप्रैल को भावेश भाई और उनकी पत्नी समेत 35 लोग हिम्मतनगर रिवर फ्रंट पर संयमित जीवन जीने का संकल्प लेंगे। सन्यास ग्रहण करने के बाद भावेश भाई और उनकी पत्नी को संयमित दिनचर्या का पालन करना होगा। वे जीवन भर भिक्षा मांगकर गुजारा करेंगे। इतना ही नहीं उनको पंखा, एसी, मोबाइल फोन जैसी सुख-सुविधाएं भी त्यागनी पड़ेगी। वे जहां कहीं भी यात्रा करेंगे उन्हें नंगे पांव चलना होगा। वे गाड़ी का उपयोग नहीं का सकेंगे। भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी से पहले उनके बच्चे (बेटा-बेटी) भी संयमित जीवन जीना शुरू कर चुके हैं। भावेश के 16 साल के बेटे और 19 साल की बेटी दो साल पहले ही जैन समाज की दीक्षा ले चुके हैं। अपने बच्चों से प्रेरित होकर ही भावेश भाई और उनकी पत्नी ने दीक्षा लेने का फैसला किया है। ऐसे लोग पुरे समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। हालांकि उनके मार्ग पर चलना तो कठिन है। सबके लिया यह संभव भी नहीं है, लेकिन हम अपना जीवन ईमानदारी और निष्ठा से जीयें । पैसे के लिए गलत तरीके न अपनाएं, इतना तो हर कोई कर सकता है। उम्मीद है इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी।

क्यों घटती जाती तादाद लोकसभा में आजाद उम्मीदवारों की?

इंदर सिंह नामधारी

जेबी कृपलानी

मीनू मसानी

बीके कृष्ण मेनन

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

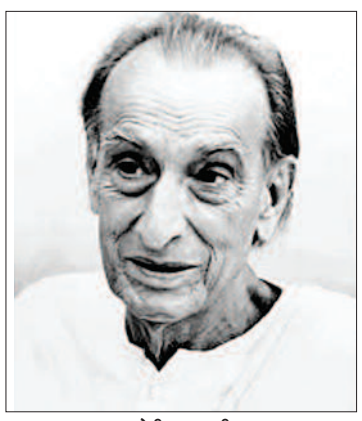

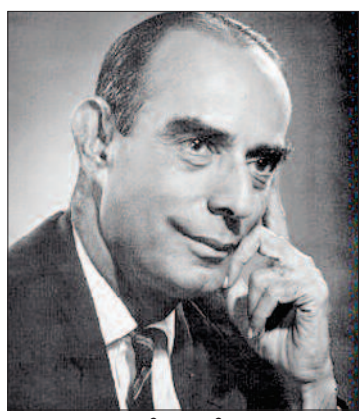

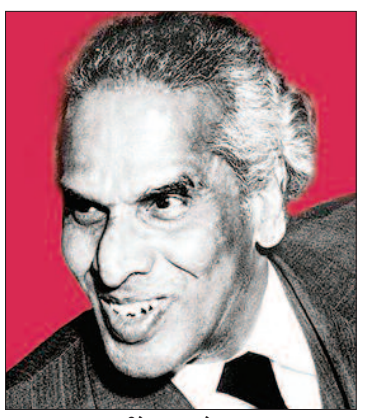

बेशक, लोकसभा का चुनाव अपन बलबूते पर लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की दरकरार रहती है। इसके बावजूद भी अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो इतना तो माना ही जा सकता है कि उसका आम जनता में गहरा प्रभाव है। पहले लोकसभा चुनावों के बाद 1967 के लोकसभा चुनावों में 34 आजाद उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे थे। देश में इमरजेंसी लगने के बाद 1977 में चुनाव हुआ। तब सिर्फ सात आजाद उम्मीदवार सफल रहे। यह संख्या 1980 में मात्र चार रह गई। 1984 और 1989 के लोकसभा चुनावों में क्रमशः 9 और 8 आजाद उम्मीदवार ही निर्दलीय रूप से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

बुजुर्ग हिन्दुस्तानियों को याद होगा ही कि एक दौर में वी.के.कृष्ण मेनन, आचार्य कृपलानी, एस.एम.बैनर्जी, मीनू मसानी, लक्ष्मीमल सिंघवी, इंदर सिंह नामधारी, करणी सिंह, जी. जी. स्वैल जैसे बहुत सारे नेता आजाद उम्मीदवार होते हुए भी लोकसभा का कठिन चुनाव जीत जाते थे। पर अब इन आजाद उम्मीदवारों का आंकड़ा लगातार सिकुड़ता ही चला जा रहा है। अगर 1952 के पहले लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो हमें इन विजयी आजाद उम्मीदवारों की संख्या 36 मिलेगी। तब इनका समूह कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। यानि किसी भी गैर-कांग्रेसी दल से बड़ा था। निवर्तमान लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ तीन रह गई थी। अभी तक मात्र 202 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे हैं।

बेशक, लोकसभा का चुनाव अपन बलबूते पर लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की दरकरार रहती है। इसके बावजूद भी अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो इतना तो माना ही जा सकता है कि उसका आम जनता में गहरा प्रभाव है। पहले लोकसभा चुनावों के बाद 1967 के लोकसभा चुनावों में 34 आजाद उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे थे। देश में इमरजेंसी लगने के बाद 1977 में चुनाव हुआ। तब सिर्फ सात आजाद उम्मीदवार सफल रहे। यह संख्या 1980 में मात्र चार रह गई। 1984 और 1989 के लोकसभा चुनावों में क्रमशः 9 और 8 आजाद उम्मीदवार ही निर्दलीय रूप से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कह सकते हैं कि हरेक लोकसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले कुछ न कुछ विजयी रहे हैं। बेशक, ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जुझारू प्रतिबद्धता के साथ कुछ काम तो करते होंगे। वर्ना ये सब लोकसभा में कभी नहीं पहुंच पाते। खासतौर पर तब जबकि चुनावों में धन का इस्तेमाल तो बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप में बहुत बुलंद शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें से कुछ मनीषी भी रहे हैं।

कृपलानी जी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधी जी के सबसे उत्साही और विश्वासपात्र शिष्यों में से एक थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी कार्य किया था। लक्ष्मीमल सिंघवी जैसे सरस्वती पुत्र भी सदियों में पैदा होते हैं। वे ख्यातिलब्ध न्यायविद, संविधान विशेषज्ञ, कवि, भाषाविद एवं लेखक थे। वे 'धर्मयुग' में विधि संबंधी मामलों में खूब लिखते थे। जब मैं धर्मयुग में आवरण कथाएं लिखा करता था। उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। वे 1952 से 1957 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। चाहे सांसद रहे हों या किसी और संस्था से जुड़ गए हों, लेकिन उन्होंने वेतन के रूप में हमेशा एक रुपया ही लिया था। आप कानपुर में जाकर अब भी एस.एम. बैनर्जी के बारे में पूछ लें । आपको लोग उनके तमाम किस्से सुनाएँगे। वे एक विख्यात मजदूर नेता थे। वे पश्चिम बंगाल से कानपुर में नौकरी करने के लिए आए थे। कानपुर को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया था। कोलकाता से आये मजदूर नेता एस.एम. बैनर्जी ने 1957 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की तो 1962, 1967 और 1971 तक जीत का सेहरा वही पहनते रहे। शायद कानपुर अकेला शहर होगा, जहां चार बार लगातार कोई निर्दलीय सांसद चुना गया हो।

आपको विजयी हुए निर्दलीय उम्मीदवारों में इस तरह के कई नाम मिल जाएंगे जो उस लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए, जहाँ से उनका उस क्षेत्र से कोई सीधा संबंध नहीं था। वहां पर जनता से जुड़कर और उनके सुख-दुःख का हिस्सा बनकर वे वहां के हो गए। कृपलानी जी सिंध (अब पाकिस्तान) से आए थे। वे बिहार से सांसद बने। इंदर सिंह नामधारी का परिवार देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से बिहार आकर बस गया था। वे बरसों बिहार के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे। बिहार के विभाजन के बाद वे झारखंड में सक्रिय हो गए। इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पहले विधान सभा अध्यक्ष बने। वे वनांचल राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिसने दक्षिण बिहार के लिए अलग राज्य की मांग की थी।

अब डॉ. करणी सिंह की भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि नई पीढ़ी को उनके संबंध में कम जानकारी हो। वे देश के चोटी के निशानेबाज थे। डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज किसी खिलाडी के नाम पर रखा गया राजधानी का पहला स्टेडियम माना जा सकता है। आमतौर पर यह नहीं होता। ड़ॉ. करणी सिंह रेंज का निर्माण 9 वें एशियाई खेलों के निशानेबाजी के मुकाबलों के लिए 1982 में हुआ था। डॉ. करणी सिंह बीकानेर के राज परिवार से थे। वे देश के पहले निशानेबाज थे जिन्हें 1961 में ह्यअर्जुन पुरस्कारह्न देकर सम्मानित किया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे राज परिवार से आने के बावजूद आम जनता के सुख-दुख में शामिल होते रहते थे। वे 1952 से 1977 तक लगातार पांच बार सांसद रहे। उन्होंने दो चुनाव में 70 से 71 फीसदी मत प्राप्त किए थे। उनके बाद इस मत प्रतिशत को प्राप्त करने में कोई भी पार्टी प्रत्याशी सफल नहीं हो पाया। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार सांसद रहने का रिकॉर्ड करणी सिंह के नाम है।

अब लोकसभा चुनाव का उत्सव देश देख रहा है। सारा देश जानता है कि अब चुनाव लड़ना कितना खचीर्ला हो गया है। कैंपेन इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी इंसान आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से पहले कई बार जरूर सोचता होगा। इसके बावजूद तमाम जनता के बीच में काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावी रणभूमि में कूदने से पीछे नहीं रहते। उम्मीद करनी चाहिए कि देश आगामी लोकसभा में पहले से अधिक आजाद उम्मीदवारों को देखेगा।

वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पित थे डॉ. भीम राव अम्बेडकर

डॉ. केएल जौहर

जयंती पर विशेष

संविधान के 'जनक' कहे जाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ। उनके साथ स्कूल में बहुत भेदभाव किया जाता था। यहां तक कि उनको कक्षा से दूर बैठाया जाता। वे उस नल से पानी भी नहीं पी सकते थे जिससे आम विद्यार्थी पीते थे। जल्दी ही वे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र चले गए जो फिर जीवनभर उनकी कार्यस्थली रही। इसके बाद तो उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा भी उठा लिया। अनुसूचित जातियों का उत्थान उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। इस आशय को लेकर उनके कई लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए। डॉ. अंबेडकर ने कई पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जिनमें मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता प्रमुख हैं। उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' का गठन किया और अनुसूचित जातियों की दशा पर विस्तृत प्रकाश डाला। वे मानते थे कि हिन्दू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति ही इस भेदभाव का मूल सूत्रधार है। देशभर में घूमकर उन्होंने अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी से इस बात को लेकर रुष्ट थे कि उन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुछ खास व पर्याप्त नहीं किया। उन दिनों जब गांधी जी के नेतृत्व से कोई बड़े से बड़ा नेता भी उलझ नहीं पाता था, अंबेडकर ने अपनी आवाज उठाई। अब तक अंबेडकर अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। उन्हें 1930, 1931 और 1932 की गोलमेज कान्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। गांधीजी ने विरोध किया परन्तु सब बेअसर। गोलमेज कान्फ्रेंस के उपरांत 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा हुई।

अक्सर डॉक्टर अंबेडकर और उनके निर्देशन में निर्मित संविधान चर्चा का विषय बने रहते हैं। वर्तमान हालात में भी विपक्ष सोचता है कि यदि मौजूदा सरकार फिर सत्ता में आई तो वह इस संविधान को बदल डालेगी परन्तु सरकार इस बात से इंकार करती रही है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे मुद्दों पर आशंकाएं व चर्चा होना स्वाभाविक भी है। फिलहाल, इस स्थिति को यहीं छोड़ते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व पर ध्यान देना समीचीन होगा।

भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। एक निर्धन परिवार से थे परन्तु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, गहन ज्ञान और छात्रवृत्ति के बलबूते उनकी सारी उच्च शिक्षा अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर ब्रिटेन में हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि के साथ कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे बीसवीं शताब्दी में सबसे अधिक पढ़े-लिखे विद्वान थे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका और लंदन में सब जातियों में बराबरी और भाईचारे का अनुभव किया परन्तु जब वे 1917 में भारत लौटे तो एक विचित्र नक्शा उनकी आंखों के सामने आया। जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव ने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हालांकि वे काफी हद तक तो इस समस्या को अपनी बाल्यावस्था में ही देख चुके थे।

संविधान के ह्यजनकह्न कहे जाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ। उनके साथ स्कूल में बहुत भेदभाव किया जाता था। यहां तक कि उनको कक्षा से दूर बैठाया जाता। वे उस नल से पानी भी नहीं पी सकते थे जिससे आम विद्यार्थी पीते थे। जल्दी ही वे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र चले गए जो फिर जीवनभर उनकी कार्यस्थली रही। इसके बाद तो उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा भी उठा लिया। अनुसूचित जातियों का उत्थान उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। इस आशय को लेकर उनके कई लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए।

डॉ. अंबेडकर ने कई पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जिनमें मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता प्रमुख हैं। उन्होंने ह्यबहिष्कृत हितकारिणी सभाह्न का गठन किया और अनुसूचित जातियों की दशा पर विस्तृत प्रकाश डाला। वे मानते थे कि हिन्दू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति ही इस भेदभाव का मूल सूत्रधार है। देशभर में घूमकर उन्होंने अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी से इस बात को लेकर रुष्ट थे कि उन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुछ खास व पर्याप्त नहीं किया। उन दिनों जब गांधी जी के नेतृत्व से कोई बड़े से बड़ा नेता भी उलझ नहीं पाता था, अंबेडकर ने अपनी आवाज उठाई। अब तक अंबेडकर अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। उन्हें 1930, 1931 और 1932 की गोलमेज कान्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। गांधीजी ने विरोध किया परन्तु सब बेअसर।

गोलमेज कान्फ्रेंस के उपरांत 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा हुई। गांधी जी देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद थे। उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। अब तो सारा देश अंबेडकर पर दबाव डालने लगा कि वह गांधी जी से मुलाकात करें। अंततः यह मुलाकात 22 सितम्बर, 1932 को हुई और पूना पैक्ट के रूप में एक समझौता सामने आया। गांधी जी की जान बच गई जबकि अंबेडकर अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र लेने में सफल हुए। फिर भी गांधी और अंबेडकर में मनमुटाव तो जारी ही रहा।

यह गौर करने लायक बात है कि अंबेडकर ने एक दिन भी स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं काटी। देश-समाज की सेवा व उन्नयन का मकसद साधने का उनका तरीका अलग ही था। उनके बड़े हथियार थे- अनुसूचित जातियों का नेतृत्व, तीक्ष्ण बुद्धि और कानून पर पकड़। इसी बलबूते बाद में उन्हें संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक तरह से संविधान निर्माण हेतु आमंत्रित किया गया। जो संविधान हम आज देखते हैं वो बाबा साहेब अंबेडकर की देन है। उनकी कानून पर पकड़ और सूझ-बूझ को देखते हुए पंडित नेहरू ने उनको अपनी सरकार में सम्मिलित किया। वे 1951 तक कानून मंत्री रहे परन्तु फिर पंडित नेहरू से गंभीर मतभेद होने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

वर्ष 1952 में लोकसभा के लिए चुनाव में सफलता नहीं मिली। राज्यसभा के लिए मनोनीत किये गए परन्तु चुनाव की राजनीति से दिल उकता गये। वे अस्वस्थ रहने लगे। वहीं उनकी इच्छा के अनुसार अनुसूचित जातियों का उत्थान भी नहीं हो रहा था। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्तूबर, 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। फिर 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ह्यभारत रत्नह्न से नवाजा गया। हजारों कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय डॉ. अंबेडकर के नाम पर स्थापित किये गए। देश-विदेश में उनकी पहचान बनी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतवर्ष के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

हर संपत्ति का ब्योरा जरूरी नहीं

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उम्मीदवारों को अपनी हर चल संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। केवल उन संपत्तियों का खुलासा करना होगा जो उनकी सार्वजनिक छवि या जीवनशैली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और मतदाता की पसंद पर असर डालती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए व्यवस्था दी कि चुनाव में किसी प्रत्याशी के लिए अपनी हरेक चल संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी नहीं है। फैसला इस लिहाज से खास है कि इसमें मतदाताओं के साथ-साथ प्रत्याशी के अधिकार का भी ध्यान रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा यह इस बात की ओर भी ध्यान खींचता है कि शब्दों पर जरूरत से ज्यादा बल देना कभी-कभी अनजाने ही कानून को निरर्थकता की ओर ले जाने लगता है।

प्रत्याशियों की निजता : चुनाव सुधारों की बात करते हुए अमूमन मतदाताओं के जानने के अधिकार पर ज्यादा जोर रहता है। इस फैसले ने ध्यान दिलाया है कि प्रत्याशी भी इस देश के नागरिक हैं। ऐसे में मतदाताओं के सूचित होने के अधिकार को समुचित महत्व देते हुए भी प्रत्याशियों के निजता के अधिकार की ओर से पूरी तरह आंखें मूंद लेना ठीक नहीं होगा।

कागजी खानापूर्ति : ध्यान रहे, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है उसमें प्रत्याशी पर तीन वाहनों की जानकारी न देने और सरकारी आवास से जुड़े नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा न करने का आरोप था। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया कि तीनों वाहन भले ही कागज पर प्रत्याशी के परिजनों के नाम पर हों, लेकिन वे पहले ही बेचे या गिफ्ट किए जा चुके थे। ऐसे ही इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं था कि प्रत्याशी पर किसी तरह का बकाया नहीं था, बस नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा न करने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसे प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।

सीधी लकीर नहीं : फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कोई एक लकीर नहीं खींची जा सकती कि कौन सी चल संपत्ति ब्योरा देने लायक है और कौन सी नहीं। हर केस के हिसाब से गौर किया जाना चाहिए। किसी प्रत्याशी के परिजनों की सामान्य घड़ी का ब्योरा देना अनावश्यक हो सकता है, लेकिन अगर किसी के परिवार में बेहद महंगी कई सारी घड़ियां हों तो उसका ब्योरा छिपाया जाना अपराध हो सकता है।

व्याख्या की गुंजाइश : यहां इस सवाल से नहीं बचा जा सकता कि क्या इस फैसले से आगे ऐसे मामलों में अलग-अलग व्याख्याओं की गुंजाइश बन गई है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या इसका फायदा उठाते हुए आगे चलकर कुछ प्रत्याशी ऐसी भी सूचनाएं छुपा सकते हैं, जो चुनाव और वोटर के लिहाज से अहम हों?

सतर्कता की जरूरत : जाहिर है इस संभावना को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस अहम कानून की सार्थकता बढ़ाने और इसे प्रासंगिक बनाए रखने का काम किया है।

प्रथम चरण के 102 सीटों पर उम्मीदवारों के अपराधिक, गंभीर आपराधिक वह करोड़पति वित्तीय स्थिति का हैरानी भरा आंकलन

19 अप्रैल 2024 को होने वाले प्रथम चरण के 102 सीटों में 41 फीसदी यानें 42 सीटें रेडअलर्ट निर्वाचन क्षेत्र है,जिसको रेखांकित करना समय की मांग : एडवोकेट किशन भावनानी

लोकसभा प्रथम चरण चुनाव 2024-लोकतंत्र का मंदिर बनाम 41 फीसदी सीटों पर दागी उम्मीदवार

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर लोकतंत्र के सबसे बड़े विशाल मंदिर लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का को चयन करनें का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 में अभी मात्र 5 दिन बचे हैं,परंतु अभी उतना उत्साह या जोश नहीं दिख रहा है,परंतु अब आखिरी चार दिनों में चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने की पूरी उम्मीद है।मेरा मानना है कि अभी मतदाता पहले की अपेक्षा बहुत अधिकजागरूक हो गए हैं।भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है। बशर्ते वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसी उम्मीद की जाती है कि चुनाव में स्वच्छ छवि के लोग आगे आएं ताकि सरकार की बागडोर ईमानदार व्यक्तियों के हाथों में रहे लेकिन हम देखते हैं कि कई नेता ऐसे भी होते हैं जिनके खिलाफ कई प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं। सामान्य तौर पर कुछ मुकदमे तो द्वैषतावश या किसी परिस्थिति के कारण दर्ज हो सकते हैं।लेकिन अगर किसी के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हो तो यह चिंता का विषय है। हमारे देश में कई ऐसे नेता हुए हैं जो न सिर्फ चुनाव जीतने के बाद बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के बाद जेल तक पहुंचे हैं। बता दें कई उम्मीदवार जाकर मतदाता के सामने कितनी भी बीन क्यों ना बजा लें, या हरे गुलाबी देकर आए, परंतु आज मतदाता अपने विवेक का उपयोग करता है जिसे जागृत करने में,द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) तथा नेशनल इलेक्शन वॉच ने आम भूमिका अदा करने की कोशिश की है,क्योंकिएडीआर व एनएडब्लू ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में चुनाव लड़ रहे 102 सीटों के 1625 उम्मीदवारों में से 1618 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया है,जिसको हर एंगल से उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों का भी आंकलन किया है। बता दें कि चुनाव लड़ते समय खुद प्रत्याशियों द्वारा अपने ऊपर लगे आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख किया जाता है,चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्रों के साथ शपथ पत्र जमा कराया। इन शपथ पत्रों में सभी तरह की जानकारियां दी गई है। प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण और उनकी स्थिति का पूरा ब्यौरा भी स्वयं प्रत्याशियों की ओर से दिया गया है, जिसका विश्लेषण एडीआर ने किया है।जिसमें हैरानी वाली बात यह है कि, लोकसभा चुनाव में पहले चरण में जिन 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा उनमें से 42 सीट यानी 41 फीसद रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र हैं। एडीआर के मुताबिक रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र का अभिप्राय उन सीट से हैं जहां से किस्मत आजमा रहे तीन या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। विश्लेषण के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा इस चरण के लिए मैदान में उतारे गए सभी चारों उम्मीदवारों केखिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है।तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के 22 उम्मीदवारों में से 13 (59 फीसद), समाजवादी पार्टी के घोषित सात उम्मीदवारों में तीन पर (43 फीसद),तृणमूल कांग्रेस के घोषित पांच उम्मीदवारों में दो (40 फीसद), भाजपा द्वारा घोषित 77 उम्मीदवारों में से 28 (36 फीसद), कांग्रेस द्वारा घोषित 56 उम्मीदवारों में से 19 (34 फीसद) पर आपराधिक मामला दर्ज है। इसी प्रकार आल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की ओर से मैदान में उतारे गए 36 उम्मीदवारों में से 13 (36 फीसद)और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा घोषित 86 उम्मीदवारों में से 11 (13 फीसयद) दागी हैं। चूंकि 19 अप्रैल 2024 को होने वाले प्रथम चरण के 102 सीटों में 41फीसदी यानें 42 सीटें रेडअलर्ट निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनको रेखांकित करना समय की मांग है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे लोकतंत्र का मंदिर बनाम 41 फीसदी सीटों पर दागी उम्मीदवार! साथियों बात अगर हम एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण की करें तो, दोनों नें चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण के लिए मैदान में दावेदारी पेश कर रहे कुल 252 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सात उम्मीदवारों पर हत्या और 19 पर हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं, इन आंकड़ों से पता चलता है कि 161 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज होने की घोषणा की है वहीं 18 नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, जबकि 35 पर नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) से संबंधित मामले हैं। 1,618 उम्मीदवारों में से 15 ने उन मामलों की घोषणा की है, जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। एडीआर ने शपथ पत्र के आंकलन पर यह रिपोर्ट तैयार की है।रिपोर्ट में ही उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति का भी आंकलन पेश किया गया है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में सात उम्मीदवारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हैं, जबकि 19 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला है। एडीआर के मुताबिक 18 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है, और उनमें से एक पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। संगठन ने बताया कि 35 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर घृणा भाषण देने का आरोप है। राजनीतिक दलों की बात करें, तो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सभी चार उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. इस मामले में सबसे कम दागदार उम्मीदवारों वाली पार्टी बसपा है, जिसके 86 उम्मीदवारों में से 11 यानी 13 प्रतिशत पर आपराधिक मामले थे। साथियों बात अगर हम उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति के आकंलन को देखें तो, पहले चरण में 450 करोड़पति (जिनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है) उम्मीदवार हैं, जिनमें से अधिकतम 69 भाजपा से हैं।इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस से 49, फिर अन्नाद्रमुक से 35, द्रमुक से 21, बसपा से 18 हैं। तृणमूल और राजद से चार -चार उम्मीदवारों के पास एक करोड़ से अधिक संपत्ति है। अन्नाद्रमुक के उम्मीदवारों के पास सबसे अधिक औसत संपत्ति 35.61 करोड़ रुपये है। इसके बाद द्रमुक के पास 31.22 करोड़ रुपये, कांग्रेस के पास 27.79 करोड़ रुपये और भाजपा के पास 22.37 करोड़ रुपये हैं। छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने सबसे अधिक 716 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसके बाद तमिलनाडु के इरोड से अन्नाद्रमुक प्रत्याशी अशोक कुमार ने 662 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी है। भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु के शिवगंगा से किस्मत आजमा रहे देवनाथन यादव टी ने 304 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी है। जबकि अन्नाद्रमु के 36 उम्मीदवारों में 35 (97 फीसद), द्रमुक के 22 में से 21 (96 फीसद), भाजपा के 77 में से 69 (90 फीसद), कांग्रेस के 56 में से 49 (88 फीसद), तृणमूल कांग्रेस के पांच में से चार (80 फीसद) और बसपा के 86 में से 18 (21 फीसद) उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति एक करोड़ रुपए से अधिक होने की जानकारी दी है। साथियों बात अगर हम पार्टी वाइस उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति का आंकलन देखें तो, पार्टी-वार विवरणरिपोर्ट से यह भी पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 77 में से 28 (36 प्रतिशत) उम्मीदवारों और कांग्रेस के 56 में से 19 (34 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सभी चार (100 प्रतिशत) उम्मीदवार मुकदमों का सामना कर रहे हैं।इस बीच, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), समाजवादी पार्टी (एसपी), ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी), और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के आंकड़े 59 फीसदी, 43 फीसदी, 40 फीसदी और 13 फीसदी हैं। संपत्ति विश्लेषण एडीआर रिपोर्ट से पता चला है कि विश्लेषण किए गए 1,618 उम्मीदवारों में से 450 (28 प्रतिशत) के पास 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में, भाजपा ने 69 करोड़पति उम्मीदवारों (90 प्रतिशत) को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 49 करोड़पति उम्मीदवारों (88 प्रतिशत) को नामांकित किया है, इसके अलावा पहले चरण के दस दावेदारों ने अपने हलफनामे में शून्य संपत्ति घोषित की है। चुनाव लड़ने वाले प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति 4.51 करोड़ रुपये है।विभिन्न दलों के प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति इस प्रकार है, 77 भाजपा उम्मीदवारों के पास औसतन 22.37 करोड़ रुपये, 56 कांग्रेस उम्मीदवारों के पास 27.79 करोड़ रुपये, 22 डीएमके उम्मीदवारों के पास 31.22 करोड़ रुपये, 4 राजद उम्मीदवारों के पास औसतन 8.93 करोड़ रुपये हैं।7 एसपी उम्मीदवारों के पास औसतन 6.67 करोड़ रुपये और 5 एआईटीसी उम्मीदवारों के पास औसतन 3.72 करोड़ रुपये हैं।सबसे अधिक संपत्ति वाले शीर्ष तीन उम्मीदवार मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नकुल नाथ (716 करोड़ रुपये से अधिक), तमिलनाडु से अन्नाद्रमुक के अशोक कुमार (662 करोड़ रुपये से अधिक) और भाजपा के देवनाथन यादव टी (304 करोड़ रुपये से अधिक) हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि लोकसभा प्रथम चरण चुनाव 2024-लोकतंत्र का मंदिर बनाम 41 फीसदी सीटों पर दागी उम्मीदवार!उई बाबा!प्रथम चरण के 102 सीटों पर उम्मीदवारों के अपराधिक,गंभीर आपराधिक वह करोड़पति वित्तीय स्थिति का हैरानी भरा आंकलन आया है।19 अप्रैल 2024 को होने वाले प्रथम चरणके 102 सीटोंमें 41 फीसदी यानें 42 सीटें रेडअलर्ट निर्वाचन क्षेत्र है,जिसको रेखांकित करना समय की मांग है।

(नवरात्रि का पवित्र छठा दिवस)

माता का छठा भव्य, विराट स्वरूप माँ कात्यायनी

कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती (शक्ति) के नौ रूपों में छठवें रूप में अवतरित हुई है। यह अमर कोष में पार्वती के लिए दूसरा नाम है, संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी,काली, हैमावती, ईश्वरी इन्हीं के अन्य पवित्र नाम भी उल्लेखित हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी उल्लेखित किया जाता है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथमतः किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गये सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूपा है, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतांजलि के महाभाष्य में किया गया है, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गयी थी। उनका वर्णन देवी-भागवत पुराण,और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है जिसे ४०० से ५०० ईसा में लिपि बद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका-पुराण (१०वीं शताब्दी) में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है।परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी में उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन 'आज्ञा' चक्र में स्थित होता है। योगसाधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं।माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा इसकी भी एक कथा है- कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्वप्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने-अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी के फलस्वरूप यह कात्यायनी कहलाईं।ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था।माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिन्दी-यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भास्वर है। इनकी चार भुजाएँ हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वरमुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपरवाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल-पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है।माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधुली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए।

लेखक
संजीव ठाकुर
चिंतक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

'या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥अर्थ : हे माँ ! सर्वत्र विराजमान और शक्ति -रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार-बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ।इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हे मनोवान्छित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिये कात्यायनी मन्त्र-
ॐ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि !
नंदगोपसुतं देवि पतिं मे कुरुते नमः।।
माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म-जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत हो कर उनकी पूजा-उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए।
"जय माता कात्यायनी की जय"।

भारत को आकार देने में शिक्षा की भूमिका

विजय गर्ग

सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र-निर्माण को बढ़ावा देने में नैतिक शिक्षा और अंतःविषय दृष्टिकोण के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है छात्रों का जीवन एक बड़े परिवर्तन के बीच है, जिसका मुख्य कारण दुनिया भर में तेजी से बदलती मूल्य प्रणालियाँ हैं। हालाँकि, केवल अधिग्रहण द्वारा संचालित इस परिवर्तन से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। इसके बजाय, यह शिक्षा, एक अत्यधिक प्रतिष्ठित संस्थान, को केवल एक व्यावसायिक उद्यम में बदलने का जोखिम उठाता है जहां सफलता केवल भौतिक संपत्ति से मापी जाती है। नैतिक और नैतिक शिक्षा सफलता की कुंजी है, जो नई पीढ़ी को उन मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपनाने में सक्षम बनाती है जो तेजी से बदलाव वाले वातावरण में छात्र समुदाय की रचनात्मक इच्छाओं को पोषित कर सकते हैं। फिर भी, हमें इस संक्रमणकालीन चरण से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, प्रेरणा और प्रोत्साहन जैसे कीवर्ड एक सफल शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक शर्तें हैं। एक सक्षम शिक्षा प्रणाली में अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए असंख्य रणनीतियों को लागू करने में सक्षम आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। नवीनतम कौशल को बढ़ावा देना और नए नैतिक कोड और संज्ञानात्मक सोच को सूक्ष्मता से प्रसारित करना महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भारत के विकास अभियान के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों और शिक्षाविदों के रचनात्मक आग्रह को आकार देने वाले मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए जानी जाती है, इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान इसे बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतःविषय और बहु-विषयक अध्ययन के समकालीन महत्व के संबंध में मौजूदा ज्ञान में अंतर को पाटने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक अनुशासन को विविध सामग्री और विचारों से समृद्ध करने की आवश्यकता है। यहां तक ??कि विज्ञान के छात्रों को भी एनईपी 2020 द्वारा शुरू की गई बहु-विषयक प्रथाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से अवगत कराया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं और कई विषयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देती हैं। हाल के वर्षों में, नई शिक्षा प्रणाली ढांचे में लोकतंत्र, पर्यावरण, वैश्वीकरण और शासन के वास्तविक जीवन के प्रयोगों को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, विभिन्न विषयों की सामग्री और प्रकृति में पर्याप्त बदलाव आया है। यह प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा के नए दृष्टिकोण कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और जनता के बीच विश्वास पैदा कर सकते हैं। अनुसंधान और शिक्षण को तदनुसार उन्नत करने के लिए विश्व स्तर पर शिक्षा में नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रसार किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा प्रणाली की ताकत उसकी आंतरिक गतिशीलता, समावेशी विकास सुनिश्चित करने और विकसित भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने में निहित है। भारत के उद्यमशीलता कौशल ने तृतीयक बाधाओं पर काबू पाकर और नवाचार को बढ़ावा देकर हमें आगे बढ़ाया है। उल्लेखनीय पहलों ने केवल बाजार या कड़ी प्रतिस्पर्धा पर निर्भर रहने के बजाय कनेक्टिविटी और नए कनेक्शन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि लुसी लारकॉम ने एक बार कहा था, "यदि दुनिया आपको ठंडी लगती है, तो इसे गर्म करने के लिए आग जलाएं।" यह भावना पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता की हमारी भूली हुई सराहना के लिए सच है। छात्रों में रचनात्मकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, उन्हें नैतिक ज्ञान और रोजगार योग्य कौशल से लैस कर-के भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है। यह न केवल नैतिक क्षितिज को व्यापक बनाता है और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि नैतिक और नैतिक रूप से क्या सही है।व्यावहारिक दृष्टिकोण और कार्यशालाएँ आलोचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति के विविध रूपों के माध्यम से कौशल विकसित करने में मदद कर सकती हैं। नैतिकता घिसी-पिटी बातों से परे है, जो जो है उससे जो होना चाहिए, उसमें बदलाव को प्रेरित करती है। कलात्मक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारी की मजबूत भावना पैदा करना आवश्यक है। प्रमुख खतरों को खत्म करने के वर्षों के प्रयासों के बावजूद, आतंकवाद, जातिगत हिंसा और वर्ग संघर्ष जारी है। इन मुद्दों के लिए दूसरों को दोष देना मूर्खतापूर्ण है; हमें उनमें अपनी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। पहचान का संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय या धार्मिक पहचान को संरक्षित करने के प्रयास कभी-कभी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया को संकीर्ण विचारधारा वाले विश्वास के प्रसार का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा विश्वास शायद ही कभी टिक पाता है। हमारे देश के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवाओं में जिम्मेदारी पैदा करने के लिए एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। कम लागत, गहन वेबिनार के माध्यम से छात्रों और समाज को संवेदनशील बनाना इस संबंध में अत्यधिक प्रभावी हो सकता है, खासकर तेजी से वैश्वीकरण के युग में। मास मीडिया राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी में भूमिका निभा सकता है, जिसमें छात्रों की भागीदारी से जन जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। अकादमिक प्रवचन के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री में सुधार और सामाजिक विज्ञान में नवीन तंत्र शुरू करने से शिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों और सेवाओं को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह सामुदायिक विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षण और सीखने में पूरक सहायता प्रदान करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बौद्धिक कौशल को छात्रों को वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ने के लिए तैयार करना चाहिए, अन्य संस्थानों के हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों को आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्र मानकों को बढ़ाने के लिए, सहयोगात्मक वातावरण में समस्या-समाधान और पूछताछ-आधारित शिक्षण गतिविधियों को शामिल करते हुए, स्व-शैक्षणिक अभिविन्यास और उत्कृष्टता विकसित की जानी चाहिए। एक नए पाठ्यक्रम को आतंकवाद की समस्या और उसके कारणों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे इससे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का मार्ग प्रशस्त हो सके। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर सद्भाव और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अनुभवजन्य और मानक समझ पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। भविष्य के लिए सरकार की प्रेरक दृष्टि आशाजनक है, जो भारत को विश्व स्तर पर सबसे आगे रखती है। निष्कर्षतः, विकसित भारत@2047 की दिशा में शिक्षा की परिवर्तनकारी यात्रा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अकादमिक उत्कृष्टता के साथ-साथ नैतिक और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। तीव्र वैश्विक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों के लिए ज्ञान अंतराल को पाटने और अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। समसामयिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और रचनात्मकता पैदा करना जरूरी है। प्रयासों को शिक्षा प्रणाली में वास्तविक जीवन के अनुभवों को एकीकृत करने और महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षा में विविधता और समावेशिता को अपनाने से समाज का ताना-बाना मजबूत होगा और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान मिलेगा। इसके अलावा, कम लागत वाले वेबिनार और मास मीडिया जुड़ाव जैसी पहल शिक्षा के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं, युवाओं के बीच सामाजिक जागरूकता और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा दे सकती हैं। जैसा कि डब्ल्यूजटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यों से गुजरते हुए, नवाचार और प्रगति को अपनाते हुए पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नैतिक स्पष्टता और व्यावहारिक कौशल से सुसज्जित पीढ़ी का पोषण करके, हम भारत और दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। संक्षेप में, शिक्षकों, नीति निमार्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज की ओर यात्रा। नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देकर, अंतःविषय शिक्षा को बढ़ावा देकर और विविधता को अपनाकर, हम एक समृद्ध और समावेशी भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और लचीलेपन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर उत्कृष्टता की ओर इस यात्रा पर आगे बढ़ें।

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र ‑ 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

सुभाषित — *नियंत्रित और शांत मन विश्वमें सबसे शक्तिशाली होता है ऐसे मनके सामने संपूर्ण ब्रह्माण्ड नतमस्तक हो जाता है।* ❒ हितोपदेश

तालिबानकी सार्थक पहल

भारतकी बढ़ती वैश्विक शक्तिको देखते हुए अफगानिस्तानकी सत्तापर काबिज तालिबानके तेवर नरम होने लगे हैं। तालिबानी सरकारने धार्मिक अल्पसंख्यकोंके लिए बड़ा और सकारात्मक फैसला किया है। एक रिपोर्टमें दावा किया गया है कि तालिबानने देशभरमें विस्थापित हिन्दुओं और सिखोंको उनकी जमीन और सम्पत्तियां लौटाना शुरू कर दिया है। वर्ष २०२२ में जब तालिबानने अफगानिस्तानकी सत्तापर कब्जा किया था, तब उसने वहां रह रहे हिन्दुओं और सिखोंकी सम्पत्ति हड़प ली थी और उनपर हमले शुरू हो गये थे। सार्वजनिक रूपसे उनके धार्मिक कार्यक्रमोंके आयोजनों और त्योहारोंको मनानेपर प्रतिबन्ध लगा दिया, जिससे लोगोंके पास वहांसे भागनेके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। नतीजतन पिछले ढाई वर्षोंमें तकरीबन ९५ प्रतिशत हिन्दू और सिख नागरिक भारत लौट चुके हैं। सिख और हिन्दू समुदायके चंद परिवार ही वहां रह गये हैं। हालांकि इन समुदायोंका पलायन तो १९७० के दशकके अंत और १९८० के दशकमें राजनीतिक उथल-पुथल और अफगानिस्तानपर सोवियत आक्रमणके बीच ही शुरू हो गया था। कभी अफगानिस्तानका एक अहम हिस्सा रहे हिन्दू और सिख समुदाय तालिबान शासनके बाद तो अब नगण्य हो गयी है। अपहरण, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न, उनकी जमीन और सम्पत्तिको हड़प लिये जाने आदिसे हिन्दुओं और सिखोंकी आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हालत खराब हुई है। हालांकि पिछले ढाई वर्षोंमें इस समुदायके लगातार पलायनके बावजूद समुदाय प्रतिनिधियोंने काबुलमें तालिबानके अधिकारियोंके साथ लगातार कई बैठकें की थीं। इसमें उन्होंने उनकी जमीनोंपर कब्जेमें लेकर चिन्ता जाहिर की थी और तालिबानसे इस मुद्देको हल करनेकी अपील की थी। हिन्दुओं और सिखोंकी हड़पी गयी सभी सम्पत्तियोंको उनके मालिकोंको वापस करनेके लिए तालिबान सरकारके न्यायमंत्रीकी अध्यक्षतामें आयोगका गठन किया गया, वहीं अफगानिस्तानकी तालिबान सरकारके इस फैसलेको भारतकी विदेश नीतिकी बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भारत समय-समयपर अफगानिस्तानकी जनताको अनाज और दवाइयोंकी मदद भी भेजता रहा है और अपने बजटमें अफगानिस्तानके लिए दो सौ करोड़ रुपयेका प्रावधान किया है। तालिबान सरकारका यह कदम भारत लौट आये हिन्दू और सिखोंकी अफगानिस्तान वापसीका रास्ता खोल सकता है।

प्रदूषित होतीं गंगा

लाख कोशिशों और करोड़ों खर्चके बाद भी गंगाका प्रदूषणमुक्त न होना गम्भीर चिन्ताका विषय है। लम्बे समयसे गंगा नदीको प्रदूषित होनेसे बचानेका प्रयास जारी है लेकिन अबतक न तो कोई सफलता मिली, न ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। गंगाको प्रदूषित होनेसे बचानेके लिए सम्बन्धित विभाग कोई न कोई बहाना बनाकर और सम्बन्धित अधिकारियोंको दण्डित कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा ही एक मामला संज्ञानमें आया है जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगाको प्रदूषित करनेवालोंपर जुर्माना नहीं लगानेके आरोपमें उत्तर प्रदेशके मुख्य पर्यावरण अधिकारी (सीईओ) को दण्डित करते हुए दस हजार रुपये जुर्माना लगाकर अपने कर्तव्यकी इतिश्री मान लिया। एनजीटीका आरोप है कि उक्त अधिकारीने वाराणसीमें गंगा नदीको प्रदूषित करनेवाले लोगों और संस्थाओंपर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने सम्बन्धी उसके आदेशका पालन नहीं किया। इसी साल फरवरीमें अधिकरणने वाराणसी नगर निगरकी उस रिपोर्टपर गौर किया था, जिसमें कहा गया था कि दस करोड़ लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल (एमएलडी) नदीमें छोड़ा जा रहा था। इसके जवाबमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कहा था कि चार सप्ताहके भीतर दोषी संस्थाओं या लोगोंपर पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया जायगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सम्बन्धित प्राधिकारी कारवाई करनेमें पूरी तरह विफल रहे जिसके चलते उन्हें दण्डित किया गया। अब बड़ा प्रश्न यह है कि किसी भी मामलेमें आदेश-निर्देश तो जारी होते रहते हैं लेकिन इसकी निगरानीकी जिम्मेदारी किसकी है। यह घोर लापरवाही है जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पवित्र गंगा नदीसे लोगोंकी आस्था जुड़ी हुई है, जो आज भगवान शिवकी नगरी वाराणसीमें इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि स्नान या पान करनेकी बात तो बहुत दूर है, आचमन करनेके लायक भी नहीं है। गंगाको प्रदूषित करनेमें नदीके किनारे रहनेवाले लोग भी कम दोषी नहीं हैं, क्योंकि सबसे अधिक गन्दगी यही लोग फैलाते हैं। इन्हें सुधरनेकी जरूरत है। गंगाको स्वच्छ और निर्मल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलानेकी आवश्यकता है तभी गंगा नदीको प्रदूषणमुक्त किया जा सकता है।

लोक संवाद

मधेपुरामें अग्निका प्रचण्डरूप

महोदय,- गर्मीकी आहट आते ही देशमें आग लगनेकी घटनाओंमें तेजीसे वृद्धि होती है। इसके लिए अग्निशमन दलको हाईएलर्ट मोडमें रखा जाता है। परन्तु प्रत्येक नागरिकको इससे बचनेके तमाम उपायोंपर गम्भीरतापूर्वक तैयार रहना चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि जब अग्निशमन दलको सूचित किया जाता है तो उसके पहुंचनेमें जितनी भी देरी होती है स्थानीय लोग ही मशक्कत करते है। परन्तु वह सब नाकाफी ही हो जाता है जब अग्नि प्रचंड रूपमें होती है तो मानवीय हानिको रोकना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। मधेपुराके अनेक घर आग लगनेसे राखमें तब्दील हो गये। चूल्हेकी चिंगारीसे भड़की आगसे देखते ही देखते १५ घर झुलस गये। तीन जिलोंसे दस दमकलोंसे आग बुझायी गयी। पांच घण्टेतक तबाहीका मंजर भयभीत करने लगा। आग सब कुछ भष्मीभूत हो गया। आगसे बचनेके लिए बच्ची जिस कोनेने छिपी थी वहींपर उसका शव मिला। आगसे बेघर हुए सिंहेश्वर महेशुआ पंचायतके लोगोंको सरकार मुआवजा मुहैया कराकर रोजगार दे। बेलदौर थाना क्षेत्रके मुरली गांवमें शॉर्ट सर्किटसे दो दर्जन घर चपेटमें आ गये। सब खाक हो गया। यह दर्दनाक और दिल पसीझनेवाली घटनाएं है। समस्तीपुरमें छह सौ एकड़में लगी आगसे गेहूंकी फसल राख हो गयी। मधेपुरामें आगकी घटनामें तबाहीका मंजर देखा। सिलेंडर फटनेकी आवाज दूसरे गांवमें सुनाई दी। इसके बाद हृदयविदारक घटना घटित हुई है। गोपालगंजमें आगसे बचनेके लिए पलंगके नीचे छिपे भाई बहन जिन्दा जल गये। बिहारमें आगकी घटनामें सब कुछ खाक हो गया। यह मानव सर्जित घटना नहीं थी। यह प्रकृतिकी घटनासे सैकड़ों लोगोंको बेघर कर दिया। **-कांतिलाल मांडोत, सूरत।**

ट्रम्पकी जीतसे वैश्वीकरणका अंत

क्या अमेरिकामें राष्ट्रपतिके रूपमें डोनाल्ड ट्रम्पकी वापसी होगी। यह प्रश्न दुनियाके सामने महत्वपूर्ण है तथा शेष विश्वको भी प्रभावित करेगा। वास्तवमें ट्रम्पकी नीति संरक्षणवादसे प्रेरित है, जो वैश्वीकरणके लिए खतरा है। यह इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दशकोंसे अमेरिका और वैश्वीकरण एक-दूसरेके पर्याय रहे हैं।

❒ बलबीर पुंज

क्या अमेरिकामें राष्ट्रपतिके रूपमें डोनाल्ड ट्रम्पकी वापसी होगी। यह प्रश्न दुनियाके इस सबसे शक्तिशाली देशके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह शेष विश्वको भी प्रभावित करेगा। स्वयं वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनने बीते दिनों अपने चुनाव प्रचारके दौरान कहा था, भारतमें जी-२० हो या किसी अन्य देशमें हुई बैठक, जब भी दुनियाभरके नेता जुटते हैं तो वे यही कहते हैं कि आप उन्हें (ट्रम्प) जीतने नहीं देंगे। बाइडेन इसलिए भी आशंकित हैं, क्योंकि फरवरीमें ट्रम्पने यूरोपीय देशोंको चेतावनी दी थी कि यदि वे नाटोमें अपने बकायेका भुगतान नहीं करेंगे तो वह रूसको उनपर अक्रमण करने देंगे। क्या ऐसा होगा। क्या ट्रम्पकी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमें जीत वैश्वीकरणके ताबूतमें भी अंतिम कील होगी। ट्रम्पने अपने पिछले कार्यकाल (२०१७-२१) में जो निर्णय लिये थे, जिनमें चीन.विरोधी व्यापारिक दृष्टिकोणके साथ सात इस्लामी देशोंके नागरिकोंके अमेरिकामें प्रवेशपर प्रतिबंध लगानेका फैसलातक शामिल था, उनमें उनकी सबसे प्रमुख नीति अमेरिका फर्स्ट थी, जिसे ट्रम्प इस बार भी दोहरा रहे हैं। अपनी पहली सरकारमें ट्रम्पने शुल्कोंके माध्यमसे भारत-चीन सहित अन्य एशियाई देशोंके साथ यूरोपीय सहयोगियोंपर भी निशाना साधा था। ट्रम्प अब अमेरिकामें सभी आयातोंपर दस प्रतिशत तो चीनसे आयातपर ६० प्रतिशततकका शुल्क लगानेकी बात कर रहे हैं। वास्तवमें ट्रम्पकी यह नीति संरक्षणवादसे प्रेरित है, जो वैश्वीकरणके लिए खतरा है। यह घटनाक्रम इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि दशकोंसे अमेरिका और वैश्वीकरण एक-दूसरेके पर्याय रहे हैं।

बात केवल वैश्वीकरणतक ही सीमित नहीं है। दुनियामें आदर्श समाज कैसा हो और उससे प्रेरित आर्थिकी कैसी हो, इसपर शीतयुद्धसे अमेरिका और पश्चिमी देशोंका एकतरफा नियंत्रण रहा है। जब दूसरे विश्वयुद्धके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशोंके समर्थनसे संयुक्त राष्ट्रका गठन हुआए तब उसने वर्ष १९५१ में 'वन मॉडल, फिट्स ऑल' शेष विश्वपर थोपते हुए कहा था, ऐसा अनुभव होता है कि तीव्र आर्थिक प्रगति बिना दर्दनाक समायोजनके संभव नहीं। इसमें प्राचीन दर्शनोंको छोड़ना, पुरानी सामाजिक संस्थाओंको विघटित करना, जाति, मजहब और पंथके बंधनोंसे बाहर निकलना होगा।

इसका मर्म यह था कि मानव केन्द्रित प्रगति-उत्थानके लिए प्राचीन संस्कृति-सभ्यता और परम्पराओंको ध्वस्त करना होगा, चाहे उसका समृद्ध इतिहास क्यों न हो। यही चिन्तन वामपंथके प्रणेता कार्ल मार्क्सका भी था, जो १८५० के दशकमें ब्रितानियों द्वारा अनादिकालीन भारतीय संस्कृतिके दमन हेतु कुटिल उपायोंका समर्थन करते थे। उपरोक्त पश्चिमी जीवन-दर्शनका परिणाम क्या निकला, यह अमेरिकाकी स्थितिसे स्पष्ट है। वर्ष १४९२-९३ में यूरोपीय ईसाई प्रचारक क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोजे गये और वर्ष १७८९ से संविधान द्वारा संचालित अमेरिकाकी वर्तमान आबादी ३४ करोड़ है। कहनेको अमेरिका आर्थिक-सामरिक रूपसे समृद्ध है, परन्तु उसके १३ करोड़से अधिक युवा अकेलेपनसे ग्रस्त हैं। विश्व स्वास्थ्य संघटनने अकेलेपनको गम्भीर खतरा बताया है। इससे पनपे अवसादके कारण ही अमेरिकामें पिछले एक दशकमें प्रतिवर्ष ४००-६०० अंधाधुंध गोलीबारीके मामले सामने आ रहे हैं। एक तिहाई अमेरिकी युवा अपने माता-पिताके साथ रहनेको 'बुरा' मानते हैं, इसलिए अमेरिकी सरकार ६५ या उससे अधिक आयुवर्गके बुजुर्गोंकी देखभाल हेतु बाध्य है। इस संबंधमें वर्ष २०१९ में अमेरिकी सरकारने अपने राजकीय बजटमेंसे डेढ़ ट्रिलियन डालर व्यय किया था, जिसके २०२९ तक दोगुना होनेकी सम्भावना है। इसी असंतुलनके कारण अमेरिकामें एकल-व्यक्ति परिवारकी संख्या वर्ष १९६० में १३ प्रतिशतसे बढ़कर वर्ष २०२२ में २९ प्रतिशत हो गयी। सामाजिक-पारिवारिक मूल्योंके ह्राससे अमेरिका और पश्चिमी देशोंमें तलाक दर ४०-८० प्रतिशततक पहुंच गयी है।

किसी भी समाजमें संस्कृति और जीवनशैली एक-दूसरेकी पूरक होती हैं, जो उसके अर्थशास्त्रमें भी परिलक्षित होता है। अमेरिकी और पश्चिमी देशोंमें मानव केन्द्रित विकासने प्रकृतिका सर्वाधिक दोहन किया है। दुनियाके सामने गहराता जलवायु संकट इसका प्रमाण है। १९५१ के 'वन मॉडल, फिट्स ऑल' के कारण ही वर्ष २००७-०८ में पूरा विश्व मंदीकी चपेटमें आ गया। तब कालांतरमें संयुक्त राष्ट्रने २०१५ की अपने सहस्राब्दी लक्ष्य घोषणामें कहा कि संस्कृति ही विकासकी नींव होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमिमें अब अमेरिका समर्थित वैश्वीकरण भी समाप्तिकी ओर है। विगत दो दशकोंमें चीनके चमत्कारिक उभारमें वैश्वीकरणका बहुत बड़ा योगदान है। परन्तु चीन आर्थिक संकटसे जूझ रहा है, जिसमें धीमी होती विकास दर, घटता विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी क्षेत्रमें मंदी, सुस्त निर्यात, कमजोर मुद्रा और युवाओंमें लगातार बढ़ती बेरोजगारी शामिल हैं। बीते तीन वर्षोंमें चीनका शेयर बाजार ५० प्रतिशततक गिर चुका है। स्वयं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंगने भी इस नववर्षकी पूर्व संध्यापर पहली बार आर्थिक संकटको स्वीकार किया था। इस स्थितिके लिए चीनकी विकृत कोविड-नीति और उसकी अधिनायकवादी-साम्राज्यवादी मानसिकताके खिलाफ शक्तिशाली वैश्विक समूहों क्वाड सहितके संघर्षकी एक बड़ी भूमिका है। इस परिदृश्यसे भारतको प्रत्यक्ष-परोक्ष लाभ मिला है, क्योंकि वर्तमान मोदी सरकार जहां आत्मनिर्भर भारतपर बल दे रही है, वहीं मेक इन इंडिया नीतिके माध्यमसे विश्व प्रसिद्ध कम्पनियोंको भारतमें अपनी इकाई स्थापित करनेका सशर्त प्रस्ताव भी दे रही है। यही नहीं, पीएलआई योजना, घरेलू और विदेशी निवेशको प्रोत्साहित करके भारतके विनिर्माण क्षेत्रको मजबूती भी मिल रही है। इस कारण विनिर्माण क्षेत्रकी वृद्धि १६ वर्षके उच्चतम स्तर ५९.१ पीएमआईपर पहुंच गयी है। बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्यमें भारत राष्ट्रपति बाइडेनके नेतृत्वमें अमेरिकाका महत्वपूर्ण आर्थिक सांझीदार बन गया है। परन्तु ट्रम्प प्रशासनमें भारतके साथ शुल्कपर बातचीत और व्यापार समझौता सफल नहीं हो पाया था। ऐसेमें ट्रम्पकी वापसी होनेकी संभावनापर दिल्लीको वाशिंगटनके साथ व्यापारिक सहयोग हेतु पुन: रचनात्मक रूपसे सोचना होगा।

किसी भी समाजमें संस्कृति और जीवनशैली एक-दूसरेकी पूरक होती हैं जो उसके अर्थशास्त्रमें भी परिलक्षित होता है। अमेरिकी और पश्चिमी देशोंमें मानव केंद्रित विकासने प्रकृतिका सर्वाधिक दोहन किया है। दुनियाके सामने गहराता जलवायु संकट इसका प्रमाण है। १९५१ के वन मॉडल, फिट्स ऑलके कारण ही वर्ष २००७-०८ में पूरा विश्व मंदीकी चपेटमें आ गया। तब कालांतरमें संयुक्त राष्ट्रने २०१५ की अपने सहस्राब्दी लक्ष्य घोषणामें कहा कि संस्कृति ही विकासकी नींव होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमिमें अब अमेरिका समर्थित वैश्वीकरण भी समाप्ति की ओर है।

रोमांचकारी निष्कर्षके प्रणेता

प्रख्यात् मनीषी, संविधान सर्जक एवं श्रद्धेय राष्ट्रनिर्माता डा. बी.आर. अम्बेडकर अद्वितीय और प्रेरक हैं। वे अपने जीवनकालसे ज्यादा आधुनिक कालमें भी प्रभावी हैं। राष्ट्रनिष्ठ और बहुपठित थे। प्रखर राष्ट्रवादी हैं।

❒ हृदयनारायण दीक्षित

डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाकई भारत रत्न हैं। उन्होंने भारतीय सार्वजनिक जीवनमें हस्तक्षेप किया। वे अपने समकालीन विद्वानों, राजनेताओंके मध्य श्रेष्ठ बुद्धिजीवी थे। राष्ट्रनिष्ठ और बहुपठित थे। वे भारतीय समाज संरचनाके तर्कनिष्ठ आलोचक थे। उन्होंने ऋग्वेद सहित सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय वाङ्मय पड़ा। उपनिषद पुराण और स्मृति ग्रन्थ भी उनके प्रिय विषय रहे। उन्होंने प्राचीन इतिहासका गहन अध्ययन किया। शूद्रोंको अलग नस्ल बताने वाली नेतागीरीका प्रतिकार किया। मार्क्सवाद पड़ा और भारतीय परिस्थितियों खास तौरसे दलितोंके लिए अनुपयोगी बताया। उन्होंने बहुचर्चित आर्य आक्रमणके सिद्धांतका प्रतिकार किया। भारतीय इतिहास बोधके प्रेमी उनके ऋणी रहेंगे। राजनीतिने जाति और शूद्रको भारतीय इतिहासका प्राचीन तत्व बनाया है। ब्रिटिश विद्वान एवं जातिवादी राजनीतिका एक बड़ा धड़ा आर्योंको विदेशी हमलावर और शूद्रोंको पराजित नस्ल बताता रहा है। डा. आम्बेडकरने लिखा, यह धारणा गलत है कि आर्य आक्रमणकारियोंने शूद्रोंको जीता। पहली बात तो यह कि आर्य भारतमें बाहरसे आये थे और उन्होंने यहांके मूल निवासियोंपर आक्रमण किया, इस कहानीके समर्थनके लिए कोई भी प्रमाण नहीं है। भारत ही आर्योंका मूल निवास स्थान था, यह सिद्ध करनेके लिए प्रमाण-सामग्री काफी बड़े परिमाणमें है। आर्यों और दस्युओंमें युद्ध हुआ, यह साबित करनेके लिए कोई प्रमाण नहीं है। फिर दस्युओंका शूद्रों से कुछ लेना-देना नहीं है। (डा. बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज खण्ड ७ पृष्ठ ४२०) आर्योंको विदेशी माननेका झूठ अभी भी जारी है।

डा. आम्बेडकरकी पुस्तक 'हू वेयर शूद्राज' (शूद्र कौन थे) (१९४६) पठनीय है। उन्होंने एक विद्वान अधिवक्ताकी तरह पहले पाश्चात्य विद्वानोंके विचार दिये हैं। उन स्थापनाओंको तर्क सहित गलत बताया है। उन्होंने ऐसे विद्वानोंकी सात मुख्य स्थापनाएं बनायी- १. जिन लोगोंने वैदिक साहित्य रचा था, वे आर्य नस्लके थे। २. आर्य नस्ल बाहरसे आयी थी और उसने भारतपर आक्रमण किया था। ३. भारतके निवासी दास और दस्यु रूपमें जाने जाते थे और ये आर्योंसे नस्लके विचारसे भिन्न थे। ४. आर्य श्वेत नस्लके थे, दास और दस्यु काली नस्लके थे। ५. आर्योंने दासों और दस्युओंपर विजय प्राप्त की। ६. दस और दस्यु विजित होनेके बाद दास बना लिये गये और शूद्र कहलाये। ७. आर्योंमें रंगभेदकी भावना थी। इसलिए उन्होंने चातुर्वर्ण्यका निर्माण किया। इसके द्वारा उन्होंने श्वेत नस्लको काली नस्लसे, यथा दासों और दस्युओंसे अलग किया। इसके बाद सातों विचार बिन्दुओंकी सभी स्थापनाओंको गलत बताया। ऋग्वेदके उद्धरण दिये और लिखा 'इन (शब्दों) के प्रयोग देखनेसे निष्कर्ष यह निकलता है कि ये शब्द नस्लके अर्थमें कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए' वे आर्यों को विदेशी बतानेका तर्क काटते हैं 'जहांतक वैदिक साहित्यका सम्बंध है, वह इस सिद्धांतके प्रतिकूल है कि आर्योंका मूल निवास भारतसे कहीं बाहर था।' आर्य विदेशी होते तो भारतीय नदियोंको माता कहकर प्रणाम न करते। आर्य हम सबके पूर्वज थे।

डा. आम्बेडकरने रंग (वर्ण) भेदके आधारपर आर्यों और शूद्रोंको अलग बतानेवाली स्थापनाको भी गलत बताया। उन्होंने ऋग्वेदके तमाम उद्धरण दिये और लिखा, आर्य गौर वर्णके थे और श्याम वर्णके भी थे। अश्विनी देवोंने श्याव और रूक्षतीका विवाह करवाया। श्याव श्याम वर्ण है, रूक्षती गौर वर्ण है। डा. अम्बेडकरकी स्थापना है इन उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्योंमें रंगभेदकी भावना नहीं थी। ऋग्वेदके एक ऋषि दीर्घ तमस् है, वे श्याम वर्णके और कण्व भी श्याम वर्णके थे। आर्योंके दोनों अवतारी पुरुष श्रीराम एवं श्रीकृष्ण सांवले थे। महाभारतके प्रतिष्ठित योद्धा अर्जुन भी श्याम रंगके थे। समूचा आर्य समाज एक था। हिन्दू प्राचीन आर्य समाजकी ही नयी संज्ञा है। डा. आम्बेडकरने लिखा हिन्दुओंसे अछूतोंको अलग करनेकी मांगपर मुसलमानोंने जोर दिया था। २७ जनवरी १९१० को उन्होंने सरकारके सामने एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका दावा था कि देशकी राजनीतिक संस्थाओंमें उनके प्रतिनिधित्वका अनुपात सभी हिन्दुओंकी संख्याके अनुसार निश्चित न किया जाना चाहिए वरन् सवर्ण हिन्दुओंकी संख्याके अनुरूप ही निश्चित होना चाहिए। उनका कहना था कि अछूत हिन्दू नहीं हैं। लिखा कि १९०९ में मुसलमानोंकी ओरसे आगा खांने वायसराय मिंटोंके सामने आवेदन पेश किया था-राजनीतिक संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओंमें मुसलमानोंको पृथक् और पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। १९०१ में जो मर्दुमशुमारी हुई थी उसमें मुसलमान कुल आबादीका चैथाई या पांचवां हिस्सा थे। यदि हिन्दू समुदायसे अस्पर्श्य अंगोंको निकाल दिया जाय, जो प्रकृति पूजक हैं या छोटे-मोटे धर्म माननेवाले हैं, वे निकाल दिये जायं तो बहुसंख्यक हिन्दुओंके मुकाबले मुसलमानोंकी संख्याका अनुपात पहलेसे बढ़ जाता है। ऋग्वेदमें कहीं भी चार वर्ण नहीं है। शब्द ब्राह्मणका भी वर्णके अर्थमें प्रयोग नहीं हुआ। डा. रामविलास शर्माने लिखा (भारतीय संस्कृति और हिन्दी प्रदेश, पृष्ठ ५३) है, ऋग्वेदमें ब्रह्मन् शब्द बहुत बार आया है। इसका अर्थ ब्राह्मण वर्ण नहीं है। ब्रह्मन्की तरह अनेक बार ब्रह्माका भी प्रयोग हुआ है। इसका मूल अर्थ प्रशस्तिपरक काव्य है। कवि इन्द्रसे कहता है, हम तेरे लिए अभूतपूर्व स्तोत्र कहते हैं। ब्रह्मन्की तरह ब्रह्मा भी कवि, गायक, स्तोता हैं। वशिष्ठ इसी अर्थमें ब्रह्मन् है। इन्द्र वशिष्ठसे कहते हैं 'हे वशिष्ठ, ब्राह्मन्, तू उर्वषीके मनसे उत्पन्न हुआ है। इन तमाम संदर्भोंमें स्तुति और स्तोत्रकी चर्चा है। ब्राह्मणाम्का अर्थ ब्राह्मण जाति या वर्ण नहीं, कवि, ब्रह्मर्मकार गायक है।'

राष्ट्र सर्वोपरि आस्था है। डा. आम्बेडकरने लिखा, भारत एक भौगोलिक इकाई है। इस इकाईका निर्माण प्रकृतिने किया है। यह सही है कि भारतवासी आपसमें झगड़ते रहते हैं परन्तु इन झगड़ोंसे उस एकताका नाश नहीं हो सकता जो प्रकृतिके समान ही सनातन है। भौगोलिक एकताके साथ ही यहां सांस्कृतिक एकता भी है। डा. आम्बेडकरके निष्कर्ष रोमांचकारी हैं। भारत प्रकृति निर्मित राष्ट्र है। राष्ट्रकी सांस्कृतिक एकता प्रकृतिके समान सनातन है। संविधान निर्माणके आखिरी दिन(२५-११-१९४९) उन्होंने भावुक भाषण दिया। अन्तमें कहा 'यहां मैं अपना भाषण खत्म कर देता किन्तु मेरा मस्तिष्क देशकी भविष्य चिन्तासे परिपूर्ण है। क्या भारत अपनी स्वतंत्रता बनाये रखनेमें कामयाब होगा। जाति और मत-मतान्तर राजनीतिक पक्ष बन रहे हैं। क्या भारतीय मत-मतान्तरोंको राष्ट्रसे श्रेष्ठ मानेंगे या राष्ट्रके मत मतान्तरोंसे ऊपर।' डा. आम्बेडकरकी आस्थाका केन्द्र राष्ट्र था। हम सबको अपने भारतरत्नपर गर्व है।

अपार शक्ति

❒ सदानन्द शास्त्री

दुर्गाष्टमीका हिन्दू धर्ममें बड़ा ही महत्व है। प्रत्येक माहमें शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिपर दुर्गाष्टमी व्रत किया जाता है। इसे मासिक दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दौरान श्रद्धालु दुर्गा माताकी पूजा करते हैं। मुख्य दुर्गाष्टमी, जिसे महाष्टमी कहा जाता है, आश्विन माहमें नौ दिनके शारदीय नवरात्र उत्सवके दौरान पड़ती है। दुर्गाष्टमीको दुर्गा अष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमीको मास दुर्गाष्टमीके नामसे भी जाना जाता है। भगवती दुर्गाको उबाले हुए चने, हलवा-पूरी, खीर, पुए आदिका भोग लगाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गाकी मूर्तिका मंत्रोंसे विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। बहुतसे व्यक्ति इस महाशक्तिको प्रसन्न करनेके लिए हवन आदि भी करते हैं। शक्तिपीठोंमें इस दिन बहुत उत्सव मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमीका अत्यंत विशिष्ट महत्व है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको नवरात्र पूजाका जो आयोजन प्रारम्भ होता है, वह आज ही के दिन या दूसरे दिन नवमीको पूर्णता प्राप्त करता है। आजके दिन ही आदिशक्ति भवानीका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवती भवानी अजेय शक्तिशालिनी महानतम शक्ति हैं और यही कारण है कि इस अष्टमीको महाष्टमी कहा जाता है। महाष्टमीको भगवतीके भक्त उनके दुर्गा, काली, भवानी, जगदम्बा, नवदुर्गा आदि रूपोंकी पूजा-आराधना करते हैं। प्रतिमाको शुद्ध जलसे स्नान कराकर वस्त्राभूषणों द्वारा पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और फिर विधिपूर्वक आराधना की जाती है। हवनकी अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गुग्गुल और हवन सामग्रीकी आहुतियां दी जाती हैं। सिंदूरमें एक जायफलको लपेटकर आहुति देनेका भी विधान है। धूप, दीप, नैवेद्यसे देवीकी पूजा करनेके बाद मातेश्वरीकी जय बोलते हुए १०१ परिक्रमाएं दी जाती हैं। कुछ क्षेत्रोंमें गोबरसे पार्वती जीकी प्रतिमा बनाकर पूजनेका विधान भी है। वहां इस दिन कुमारियां तथा सुहागिनें पार्वती जीकी गोबर निर्मित प्रतिमाका पूजन करती हैं। नवरात्रोंके पश्चात इसी दिन दुर्गाका विसर्जन किया जाता है। इस पर्वपर नवमीको प्रात:काल देवीका पूजन किया जाता है। अनेक पकवानोंसे दुर्गाजीको भोग लगाया जाता है। छोटे बालक-बालिकाओंकी पूजा करके उन्हें पूड़ी, हलवा, चने और भेंट दी जाती है। दुर्गा अष्टमीके एक दिन बाद अंतिम नवरात्र होता है। नवरात्रके दौरान वैवाहिक जीवन और खान-पानमें संयमकी जरूरत होती है। कुछ लोग नवरात्रके दौरान भी मांस और मदिराका सेवन करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो मांस और मदिराके सेवनसे बचता है। नवरात्रके दिनोंमें माताओंके मंदिरोंमें भक्तोंकी कतार लगी रहती है। देश-विदेशसे लोग हिमाचलमें नयनादेवी, ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, बाला सुंदरी आदि मंदिरोंमें भक्त दर्शनके लिए आते हैं।

सहकारिताके जरिये विश्वकी आर्थिक महाशक्ति बन रहा देश

❒ आर.के. सिन्हा

यदि भारत दुनियाकी शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओंमेंसे एक बननेकी ओर तेजीसे बढ़ रहा है तो इसमें सहकारी आन्दोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका रहनेवाली है। यह एक ऐसी खिड़की है, जहांसे सतत आर्थिक विकासकी रोशनी लगातार आ सकती है। इसलिए मोदी सरकार भारतमें सहकारिता आन्दोलनको गति देना चाहती है। सरकार और अर्थशास्त्रियोंको पता है कि सहकारिता क्षेत्रके रास्ते भारत संसारकी एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। चूंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसपर करोड़ों लोगोंकी निर्भरता है, इसलिए इसका पोषण और संरक्षण भी जरूरी है। देशके २९ राज्योंमें लगभग ८,०२,६३९ सहकारी समितियां हैं और ये अरबोंका व्यापार भी कर रही हैं। देशमें सहकारी बैंकोंकी कुल संख्या १८८६ है, जिसमें १५०० शहरी सहकारी बैंक और ३८६ ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। ये सहकारी संस्थाएं देशभरमें विभिन्न समुदायोंकी वित्तीय जरूरतोंको पूरा करनेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केन्द्र सरकारने पिछले दस वर्षोंमें सहकारिताके क्षेत्रमें अभूतपूर्व काम किया है। उससे पहले देशमें सहकारी समितियों स्थिति अच्छी नहीं थी। यहां भी भ्रष्टाचारने अपने पैर गहरे जमा लिये थे। प्रबंधनके नामपर केवल कागजी कारवाई भर होती थी और अनावश्यक विवाद डालकर समितियां बंद भी कर देते थे। कुछ बड़े समूह मनमानी करते थे और किसानों तथा छोटे उद्यमियोंतक काम पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन अब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्व और स्वराष्ट्र एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहकी निगरानीने दृश्य बदलकर रख दिया है। कई अहम सुधार किये गये हैं। बेशक अमित शाहकी इस बातमें दम है कि ११५ साल पुराने सहकारिता आन्दोलनको मजबूती प्रदान करनेके लिए आजादीके बाद ही एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया जाना चाहिए था। लेकिन यह काम तब हुआ जब २०१९ में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधान मंत्री बने। तब उन्होंने एक अलग सहकारिता मंत्रालयका गठन किया। सहकारी समितियां आपसी सहयोगसे बनायी गयी संस्थाएं होती हैं। यह सामूहिकताके सिद्धांतपर काम करती हैं। पूंजीकी जुटान साझेदारीकी भावनासे होती है और उपयोगमें दूसरोंकी मदद करनेकी भावना होती है। इसकी विशालता और फैलावका इसीसे अंदाज लगाया जा सकता है कि इस समय भारतमें करीब दो लाख सहकारी डेयरी समितियां और ३३० सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं। अकेले गुजरातमें ८१३०७ सहकारी समितियां काम कर रही हैं। १९ बहुराज्य सहकारी समितियोंको राष्ट्रीय स्तरकी सहकारी समितियोंका दर्जा प्राप्त है। टर्नओवेरके हिसाबसे देखे तो वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए इफ्कोका टर्नओवर ६०,३२४ करोड़ रुपयेका टर्नओवर था और अमूलका २०२३-२४ के लिए १२,८८० करोड़ रुपये था। यही नहीं इफ्कोको दुनियाकी ३०० सबसे बड़ी सहकारिता समितिकी सूचीमें शामिल किया गया है। पहले सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालयके अंतर्गत था, लेकिन जुलाई २०२१ में मोदी सरकारने एक अलग सहकारिता मंत्रालयका गठन किया ही और स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह देशके पहले सहकारिता मंत्री बने। मंत्रालयने २०२२ में संसदमें बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक पेश किया। इस विधेयकका मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानूनमें संशोधनके जरिये एकसे अधिक राज्योंमें सदस्योंके हितोंकी सेवा करना और सहकारी समितियोंके स्वैच्छिक गठनको और लोकतांत्रिक बनाना था। इसके साथ ही संस्थाओंको और अधिक आर्थिक और सांघटनिक स्वायत्तता देना भी उद्देश्य था, ताकि इसका चहुमुखी विकास हो सके। इस नीतिके तहत सहकारी समितियोंको जरूरी सहयोग, प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। खास कर युवाओं और महिलाओंको मुख्यधारामें लानेमें सहकारी समितियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। क्षमता निर्माण, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और महिलाओंकी आर्थिक गतिविधियोंमें भागीदारीको एकीकृत करनेवाले समावेशी सहकारी मॉडल तैयार है। सहकारिता मंत्रालयने सहकारी क्षेत्रमें महिलाओंकी बेहतरी, सशक्तिकरण और आय सृजनके लिए जो प्रयास किये हैं उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बहुराज्य सहकारी समितियोंके बोर्डमें महिलाओंके लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियोंके बोर्डमें महिला निदेशकों नियुक्ति अनिवार्य कर दिया गया है। इससे देशभरमें १५५० से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियोंके बोर्डमें महिलाओंका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) में भी महिला सदस्योंको आरक्षण दिया गया है। एक लाखसे अधिक पैक्समें भी महिलाओंका प्रतिनिधित्व और निर्णयमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। महिला सहकारी समितियोंके परियोजना निर्माण, सहायता और क्षमता विकासके लिए एक वित्तीय सहायता योजना बनायी गयी है, जिसे नंदिनी सहकार योजनाका नाम दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियोंको ५,७१४.८८ करोड़ रुपयेकी सहायता प्रदान कर चुका है और इससे डेढ़ करोड़से अधिक महिला सदस्योंको सीधे लाभ हुआ है। कुल मिलाकर सहकारिता मंत्रालयने ५४ प्रमुख पहल की हैं जिससे महिलाओं सहित सहकारी क्षेत्रके सभी सदस्योंको सशक्त किया जा रहा है। प्रधान मंत्री मोदीने सहकारिताके जरिये करोड़ों लोगोंको स्वरोजगारसे जोड़नेकी सुदृढ़ व्यवस्था बनायी है। सहकारसे समृद्धिके दृष्टिकोणको साकार करनेके लिए स्वतंत्र सहकारिता नीतिपर अमल की जा रही है। मोदी सरकारने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से लेकर राज्योंके सहकारी समितियोंके रजिस्ट्रार कार्यालयों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकोंके कंप्यूटरीकरणतक पूरी सहकारी प्रणालीका आधुनिकीकरण कर दिया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और मध्यम और दीर्घकालिक ऋण चाहनेवाले किसानोंके लिए नयी सुविधा शुरू हो जायगी। पीएम मोदीने सहकारी क्षेत्रमें दुनियाकी सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजनाकी भी शुरुआत कर दी है, जो ११ राज्योंकी ११ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में काम करेगी। इस पहलके तहत गोदामों और अन्य कृषि-संबंधित बुनियादी ढांचेके निर्माणके लिए देशभरमें अतिरिक्त ५०० पैक्सकी आधारशिला भी रखी गयी है। इसका उद्देश्य पैक्स गोदामोंको खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखलाके साथ एकीकृत, खाद्य सुरक्षाको मजबूत करना और नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमके नेतृत्वमें सहयोगात्मक प्रयाससे देशमें आर्थिक विकासको बढ़ावा देना है। सरकारके सामने सहकारिता क्षेत्रसे जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं, खास कर सहकारी बैंकिंगके मामले में। सहकारी बैंकिंग क्षेत्रमें धोखाधड़ीसे संबंधित आकड़ें परेशान करनेवाले हैं। आरबीआईके अनुसार पिछले पांच वर्षमें देशभरके सहकारी बैंकोंसे कुल ४,१३५ धोखाधड़ीकी रिपोर्ट सामने आयी। १०,८५६.७ करोड़ रुपयेका इन बैंकोंमें फ्रॉड हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सहकारिता राज्योंके विषयमें आता है। केंद्र सीधे इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बातसे बहुत चिंतित हैं। वह आश्वस्त कर रहे हैं कि गरीबोंका बैंकमें जमा पैसा लूटनेवालेको बख्शा नहीं जायगा। उन्होंने हाल ही में केरलके मामलेमें कहा भी है कि मैं देखूंगा कि प्रत्येक पैसा संबंधित व्यक्तिको वापस मिल जाय। उल्लेखनीय है कि केरलके करुवन्नूर सहकारी बैंकमें लगभग ५०० करोड़ रुपयेके घोटाले हुए हैं और इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस मामलेमें कुछ स्थानीय सीपीएम नेताओंपर एक्शन भी लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सहकारिता क्षेत्रमें फैली गड़बड़ियोंको भी दूर करना होगा जिसको लेकर केन्द्र सरकार गम्भीर है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अनाम शहीदों को शत-शत नमन

भारत के आजादी के लिय अनथक लड़े गये संग्राम में अप्रैल का महीना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। दिसंबर 1914 में ब्रिटेन के शासकों में से एक जस्टिस सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। और उसके उसने इसने रोलेट एक्टर के नाम से जो कानून बनाया था, उसमें बिना कारण के गिरफ्तारी एवं बंद न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई एवं किसी भी तरह की अपील पर पाबंदी जैसे प्रावधान थे। इससे भारतीय जनमानस का उद्वेलित होना स्वाभाविक हो गया था। रोलेट एक्ट ही भारत में ₹जलियां वाला बाग₹ कांड करने के लिये अंतिम रूप से जिम्मेदार था। रोलेट एक्ट के विरोध में सारा देश सुलग उठा था। जगह- जगह उसके खिलाफ आवाजें उठ रही थीं, कहीं आंदोलन ता कहीं घेराव आदि हो रहे थे। इसी मध्य अप्रैल के महीने में सन 1919 को इस एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा गया था, उसी की परिणति जलियांवाला बाग कांड के रुप में हुई।

जलियांवाला बाग कांड ने सरदार ऊधमसिंह जैसे रण बाकुरे को मारने मरने के लिये खड़ा कर दिया था। ऊधमसिंह ने पंजाब की धरती पर अमृतसर जिले के सुगम गाँव में एक दलित परिवार में जन्म लिया था। उनकी माता श्रीमती हरनाम कौर और उनके पिता जल्द ही स्वर्ग को सिधार गये। जिससे वे बचपन में ही अनाथ हो गये। ऊपर से दलित होने और उस समय छुवाछूत की भावनाओं के कारण उनका हालचाल लेने वाला कोई भी नहीं था। परंतु ऊधमसिंह ने पंजाब के एक अनाथालय में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा के साथ साथ लकड़ी की दस्तकारी भी सीखी। अमृतसर में ही उन्होंने एक फर्नीचर की दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने ₹राम मोहम्मद सिंह आजाद फर्नीचर मार्टर रखा था। उनके इस तरह दुकान का नाम रखने के पीछे भी सर्वधर्म समभाव के साथ देश की एकता की भावना भरी हुई थीं, उन्होंने जैसे राम, हिंदुओं, मोहम्मद, मुसलमानों, सिंह सिक्खों तथा आजाद, भारत की आजादी के लिये रखा था। उधमसिंह अपनी रोजी रोटी के साथ - साथ आजादी संग्राम के भी सक्रिय सिपाही थे। वे अंग्रेजी के विरुद्ध होने वाले हर आंदोलनों में जरुरी हिस्सा बनकर काम करते थे। रोलेट एक्ट के विरोध में तीस मार्च से छह अप्रैल 1919 में जो आंदोलन चलाया गया, उसके आगे की रूपरेखा तय करने के लिये 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा आयोजित की गई। इस सभा का एक तात्कालिक कारण था कि अनेक नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिन्हें रिहाई करने के लिये एक विशाल बैठक जलियांवाला वाग में बुलाई गई थी। इस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओ. डायर था। उसे भी इस बैठक की खबर हो चुकी थी।

उसने ,जब जलियांवाला बाग की बैठक शुरू हो चुकी थी। वह स्थान आंदोलनकारी से खचाखच भर चुका था तभी बिना किसी चेतावनी के जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया। सैकड़ों पुलिस कर्मी बंदूकों से लैस उपस्थित जन समुदाय पर रायफल तानकर खड़े हो गए। माइकल ओ. डावर के साथ लेफ्टिनेंट जनरल ई. जी. डायर तथा लार्ड जैटलैंड भी थे। उन्हें देखकर आंदोलनकारी कुछ समझ पाते कि अकस्मात उस सभा में इन अधिसंख्य और निहत्थी जनता पर बिना सावधान किये अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उस समय सभा में आजादी का तराना गाते समय नत्थू लाल को पहली गोली लगी, जो उनके सीने को भेदती चली गई। उस सभा में खचाखच भीड़ में लगभग चार सौ लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। किशोरवय के ऊधमसिंह भी इस सभा वहाँ उपस्थित थे । और सौभाग्य से आततायियों की दुर्दांत गोलियों से बच गये थे, उन्होंने उपरोक्त तीनों अंग्रेज अधिकारियों जो इस काण्ड के मुख्य रूप से अपराधी थे, उन्हें मृत्युदण्ड देने की कसम खाई।

1940 में ऊधमसिंह को आखिर लंबे इंतजार के बाद मौका मिल ही गया। जब वो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी और एशिया सोसायटी की सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय लेफ्टिनेंट माइकल जी. डायर तथा लार्ड लैटलैंड को ऊधम सिंह ने अपनी गोली का निशाना बनाया। जनरल ई जी डायर पहले ही मर चुका था, और उधमसिंह की गोली के हमले में दुसरा अपराधी भी मौके पर ही मारा गया। हमले में लार्ड जैडलेंड घायल हो गया था बाद में वह भी मारा गया। अंग्रेज सरकार इस घटनाक्रम से इतनी बावरी हो गई कि. उसने अमृतसर की एक गली जिसमें अंग्रेज पर आंदोलनकारियों ने हमला किया था, उसमें भारतीयों को पेट के बल आने जाने का आदेश दिया था। सैनिकों ने जनता पर उसका कटटरता व निर्ममता से पालन करवाया। सात दिन बाद यह आदेश वापस लिया गया।

तात्पर्य यह हैं कि अप्रैल का महिना देश के लोगों के लिये बड़ा पावन महीना हैं, जब देश के शहीदों ने अपनी जान न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराने की ठानी थी। परंतु आज उन शहीदों की स्मृतियों पर हमारे भौतिक सुखवाद की गर्त पट चुकी है। सरकारी स्तर पर जो उपेक्षा है उसी का परिणाम आम आदमी तक पहुँच रहा हैं। यदि शहीदों की स्मृतियों को ही हम सम्हाल कर नहीं रख पाये तो इससे बड़ा क्या पाप होगा। समय रहते इस पाप को हर स्तर पर हम सभी को धोना है। आईए हम सभी उन अनाम शहीदों को जो जलियांवाला बाग₹ काण्ड में अपने आपको बलिदान कर दिया था,उन्हें शत शत नमन करें....।

- सुरेश सिंह बैस "शाश्वत"

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

-सुरेश गांधी

भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को 133वीं जयंती है. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता था. उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित समाज के लिए समर्पित कर दिया था. उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था. बाबा साहब का बचपन काफी संघर्षभरा था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपनी शिक्षा को पूरा किया. ये बाबा साहब की काबिलियत ही थी कि उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की. इतना ही नहीं, डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने विदेश से ली. इसके बाद दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया. उन्होंने अपने जीवन में दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊंच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कई काम किए. अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन (1927), महाड सत्याग्रह (1928), येवला की गर्जना (1935) आदि जैसे कई अहम आंदोलन चलाए, जिसमें लोगों का काफी सहयोग मिला. छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अंबेडकर का कहना था कि ह्रछुआछूत गुलामी से भी बदतर है.ह्र बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने की काफी कोशिशें कीं. उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों द्वारा पेयजल के संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ अछूतों को भी मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए संघर्ष किया. बाबा साहब को हमारे देश के संविधान का जनक कहा जाता है. देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के अलावा बाबा साहब ने एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और वकील के रूप में उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बता दें कि बाबा साहेब अछूत परिवार से आते थे. इसी वजह से स्कूल के दौरान उन्हें उच्च जातियों के छात्रों के साथ कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था. लेकिन जब वो सरकार में आए, तो उन्होंने ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए थे। वह 29 अगस्त, 1947 से लेकर 24 जनवरी, 1950 तक कानून मंत्री के पद पर रहे थे। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, अम्बेडकर एक न्यायविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने अछूतों (दलितों) के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मेहनत की और विदेशों में भी पढ़ाई की. उन्होंने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई करने के बाद वे भारत लौटे और वकालत करने लगे. अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और समान अवसर प्रदान करते हैं. साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुना गया. उन्होंने मौलिक अधिकारों, संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों और वंचितों के लिए सुरक्षा उपायों जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता उन्मूलन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा जैसे अधिकारों पर जोर दिया. बाबासाहेब ने एक मजबूत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करने के लिए एक संघीय प्रणाली का समर्थन किया. उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्यों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य किया जाए. भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, अम्बेडकर एक न्यायविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अछूतों (दलितों) के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.

डॉ अंबेडकर की प्रेरणादायी बातें

बाबा साहब पढ़ने में काफी तेज थे. उनके अंदर हमेशा से ही कुछ नया सीखने की इच्छा रहती थी. उनकी इस जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई. हम सभी को भी बाबा साहब से ये गुण सीखना चाहिए. बाबा साहब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते थे. डॉ अंबेडकर का मानना था, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है. धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए. मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है. अपने भाग्य के बजाए अपनी मजबूती पर विश्वास करो. यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा. इंसान का जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए. जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है. जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है.

मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं, जो महिलाओं ने हासिल की है. बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए. उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ करना चाहिए ताकि उसके आसपास के लोग भी बेहतर जीवन जी सकें. बाबा साहब खुद की क्षमताओं पर यकीन रखते थे. उनका मानना था कि अगर व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकता है. बाबा साहब हमेशा लोगों को साथ लेकर चले, इसीलिए उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा बन सका. उनका मानना था कि व्यक्ति की तरक्की में सभी का साथ होता है, इसलिए उसे लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए. वे कहते थे, शिक्षा जितनी पुरूषों के लिए जरुरी है उतनी ही महिलाओं के लिएं किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा. भाग्य में विश्वास रखने के बजाए अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए. शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो नका मूलमंत्र था। उनका कहना था धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए. जीवन लम्बा होने की बजाय महान होना चाहिए. अपने भाग्य के बजाए अपनी मजबूती पर विश्वास करो. जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है. संविधान यह एक मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं. यह जीवन का एक माध्यम है. पति-पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए. महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है. मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं. एक विचार की प्रचार-प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी. समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा. भीमराव आंबेडकर हमेशा कहते थे कि हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि वो एक भारतीय है और अंत में भी हम भारतीय ही रहेंगे। आंबेडकर का कहना था कि व्यक्ति को अपने हर काम में 100 फीसदी देना चाहिए। अगर फिर भी उसका परिणाम न मिले, तो उस चीज को वहीं छोड़कर अपने कर्मा पर ध्यान देना चाहिए। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि ज्ञान ही हर एक व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। हर किसी को अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, ये ही हर इंसान का पहला कर्तव्य है। कभी भी कोई अधिकार छीनना नहीं चाहिए। अधिकारों को वसूलना सीखें। हर धर्म के लोग हमारे भाई हैं। इसलिए कभी भी किसी से भेदभाव न करें।

समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृढ़ निश्चय से जीवन की हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है. आंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया था, जिसने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। वहीं, इस अनुच्छेद को उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। भीमराव आंबेडकर समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और जम्मू-कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 का विरोध करते थे। उनका कहना था कि भारत आधुनिक, वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता, तो उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान, उन्होंने समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश की थी। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुभवों के आधार पर जो बातें कहीं, वो आज के समय में लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं और भटके हुए लोगों को भी सही राह दिखाती हैं. उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा हिंदू समाज द्वारा अपनाई गई जाति व्यवस्था थी जिसके अनुसार वे जिस परिवार में पैदा हुए थे उन्हें ह्रअछूतह्र माना जाता था. लेकिन उनकी प्रतिभा, कभी हार न मानने वाला हौसला, गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान का जज्बा, शिक्षा ऐसी अनगिनत बाते हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं.

भीमराव आंबेडकर की शिक्षा

भीमराव आंबेडकर ने मुंबई के एलफिन्स्टन हाई स्कूल से शुरूआती शिक्षा प्राप्त की। इस स्कूल में वह एकमात्र अछूत छात्र थे, जिस कारण से उन्हें काफी परेशानी भी हुई। भीमराव आंबेडकर ने वर्ष 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद, उन्होंने एलफिन्स्टन कॉलेज में दाखिला लिया। बाबा साहेब ने वर्ष 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। बाबा साहेब को बड़ौदा (अब वडोदरा) के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि जब गायकवाड़ शासक के अनुरोध पर बाबा साहेब ने बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश लिया, तो उन्हें उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके बाद, बाबा साहेब ने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया। इसके साथ ही, उन्होंने दलितों के बीच अपना नेतृत्व कायम किया। इसी दौरान, भीमराव आंबेडकर ने कई सारे पत्रिकाओं को शुरू किया। वहीं, उन्होंने सरकार की विधान परिषदों में दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। बाबासाहेब ने 1926 में एक वकील के रूप में अपने करियर के दौरान तीन गैर-ब्राह्मण नेताओं का बचाव किया। इन नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। जाति वर्गीकरण के खिलाफ यह जीत बाबासाहेब के लिए काफी बड़ी थी और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन का जन्म यहीं से हुआ था। इसके अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते हुए, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने और अछूतों के उत्थान का प्रयास किया।

पुणे समझौता

वर्ष 1926 के बाद भीमराव आंबेडकर अछूत राजनीतिक की हस्ती बन चुके थे। बाबासाहेब ने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। वह ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे, उन्होंने अछूत समुदाय के लिए स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की मांग की, जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की दखलअंदाजी न हो। लंदन में 8 अगस्त, 1930 को शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान उन्होंने ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा था। ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनावी सीटों में दलित आरक्षण को लेकर यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव आंबेडकर के बीच 24 सितंबर, 1932 को एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट या पुणे समझौता कहा गया।

राजनीतिक सफर

बाबासाहेब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा के लिए 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें 14 सीटें मिलीं। भीमराव आंबेडकर ने 1937 में बांबे विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनाना था। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में काम किया। बाबासाहेब 1952 में पहले आम चुनाव में बॉम्बे नॉर्थ से चुनाव लड़े, वह लेकिन हार गए। इसके बाद, राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए गए। भंडारा सीट से 1954 के उपचुनाव में, वह लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे और तीसरे स्थान पर रहे।

धर्म परिवर्तन की घोषणा

भीमराव आंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा था, ह्रह्रहालांकि मैं एक अछूत हिन्दू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिन्दू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा।ह्रह्र इसके साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 साल तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। भीमराव आंबेडकर वर्ष 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वर्ष 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें उनके साथ-साथ अन्य पांच लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुछ समय बाद छह दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति-रिवाज के अनुसार किया गया।

बाबासाहेब और संविधान निर्माण

भीमराव आंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया। उन्होंने संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। संविधान समिति का काम 1946 में शुरू हुआ था और संविधान का निर्माण 26 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ था। संविधान भारत की संवैधानिक शासन व्यवस्था है और 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र की शुरूआत हुई थी।

बाबासाहेब का निधन

भीमराव आंबेडकर वर्ष 1948 से मधुमेह बीमारी से पीड़ित थे। वर्ष 1954 में जून से अक्टूबर तक काफी बीमार रहे और उन्हें देखने में भी परेशानी होने लगी थी। 6 दिसम्बर 1956 को बाबासाहेब का निधन दिल्ली स्थित उनके घर में हुआ था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

माता का छठा भव्य, विराट स्वरूप माँ कात्यायनी

(नवरात्रि का पवित्र छठा दिवस)

संजीव ठाकुर

कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती (शक्ति) के नौ रूपों में छठवें रूप में अबतरित हुई है। यह अमर कोष में पार्वती के लिए दूसरा नाम है, संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी,काली, हैमावती, ईश्वरी इन्हीं के अन्य पवित्र नाम भी उल्लेखित हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी उच्चारित किया जाता है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथमतः किया है।

स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गये सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूपा है। जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतांजलि के महाभाष्य में किया गया है, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गयी थी। उनका वर्णन देवी-भागवत पुराण,और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है जिसे ४०० से ५०० ईसा में लिपि बद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों,

विशेष रूप से कालिका-पुराण (१०वीं शताब्दी) में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है।परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी में उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन 'आज्ञा' चक्र में स्थित होता है। योगसाधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं।माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा इसकी भी एक कथा है- कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्वप्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।

कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने-अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया।

महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी के फलस्वरुप यह कात्यायनी कहलाई।ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं।

आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्त सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था।माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिन्दी-यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भास्वर है। इनकी चार भुजाएँ हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वरमुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपरवाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल-पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है।माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है।

नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है।

इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं।

इनका ध्यान गोधुली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए।

'या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥अर्थ : हे माँ !

सर्वत्र विराजमान और शक्ति - रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार-बार प्रणाम है।

या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ।इसके अतिरिक्त जिन कन्याओ के विवाह में विलम्ब हो रहा हो,

उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए,

जिससे उन्हे मनोवान्छित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिये कात्यायनी मन्त्र-

ॐ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि !

नंदगोपसुतम्‌ देवि पतिम्‌ मे कुरुते नमः।।

माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म-जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत हो कर उनकी पूजा-उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए।

₹जय माता कात्यायनी की जय₹।

पंडित होशियार चंद बेढंगा

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

नर्मदापुरम बाबू,बाबाओं और पण्डितों का नगर है। पुण्यनगरी में चहु ओर दानी धर्मात्माओ का तांता लगा होने से यहाँ दान-पुण्य के विपुल भण्डार पहाड़ों की शक्ल में मौजूद है लेकिन कुछ लकीर के फकीर पंडित है जो अपने बापदादों की याद में इन दान पुण्य के पहाड़ों को उनके द्वारा खड़ा किया मानते है। घाट पर हजारों श्रद्धालु तीज त्योहार पर स्नान दान पुण्य करने आते है पर वे यहा के स्थानीय पंडितों से सत्यनारायन की कथा करवा कर अपने बाप दादों के लिए पुण्य सकेलने की चाह में गैर पंडितों की टोली का शिकार होकर पावन नर्मदा तट तीर्थ पर मिलने वाले पुण्य से वंचित हो खुद के लिए अनजाने में नरक का मार्ग चुनते है। चूंकि यहा के जन्मजात पंडित तो पंडित है, उन्हे सभी पंडित मानते ही नही जानते है इसलिए उनका महत्व है परंतु में उन गैर पंडितों की बात कर रहा हूँ जो जन्म से नाई धोबी या अन्य के घर पैदा हुये पर कर्म से पंडित का काम कर पंडित जी बनकर कथा आदि करके पूज रहे है ओर दूसरे वे जो पंडित के घर पैदा होकर भी धर्म कर्म के अपने पैतृक कर्मों से बहुत दूर है। इसी प्रकार के एक पंडित होशियार चंद बेढंगा के विषय में अनेक चर्चे है जिन्हे बखान कर पाना मेरी तुक्ष्य बुद्धि के लिए संभव नहीं, फिर भी एक प्रसंग सुना है बताने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। पोंगा पंडित जी का भरा पूरा परिवार है जिसमे उनके अन्य भाई वेद पुराण उपनिषदों ओर ज्योतिष के परम ज्ञानी है तथा रत्नों के मर्मज्ञ है। इनमे होशियार चंद मनमौजी जन्म से कामचोर ओर महाआलसी है, वह बेकार है पर कोई भी बात हो इस बेढंगेपन से कहते है जो लोगों को चुभती है पर अच्छी लगती है ।लापरवाही में उन जैसा कोई नहीं, बचपन से स?कूल का मुंह नहीं देखा इसलिए पढे लिखे तो है नहीं परन्तु ज्ञानी भाइयों के छोटे अनुज होने से सभी उन्हे भी ज्ञानी समझते है! आखिर क्यों न समझे? भाइयों के कारण लोग इन्हे मुफ्त का सम्मान देकर पैर जो पड़ते ह? भाइयों की शोहवत में रहते कई मंत्र और पूजा पाठ की विधियॉ उन्हें ऐसे कंठस्थ है मानो वे वेद पुराणों के आचार्य हो, पर वे इनका अर्थ समझ पाते है इसकी कोई गारंटी नही लेता फिर भी कोई अपनी शंका का निदान न कर उन्हे मर्मज्ञ ही मानते है, बस यही खूबी उन्हे होशियार बनाती है, संयोग से घर में वे होशियार चंद के नाम से विख्यात हो गए पर घरवाले उन्हे मतकमाऊ होने का ताना देकर बेढंगा पंडित कहकर रोजाना चिढ़ाते है ओर चार पैसा कमाकर लाने का ताना देते है जिससे वे परिवार से कुढ़ा करते है। शादी के बाद बेढंगा जी अपनी पत्नी को छोड़ किसी काम के नहीं, घर से नहीं निकलते ओर दिन भर मक्खी मारा करते है ओर कोई काम करने का कहने पर जी चुराकर काम टालकर अपनी योग्यता का लोहा मनवा लेते हैं किन्तु इससे घर के सदस्य ओर उनकी पत्नी उनसे नाराज थी। महाआलसी पर बकवास में महा चतुर पंडित होशियार चंद बेढंगा से रोज सुबह से देर रात सोने तक कुछेक लोग आ टपकते है तब पूरा दिन कोरी बकवास में समय निकालकर उनसे तम्बाकू खाकर इधर-उधर पीक मारकर दीवार और सड़कों को पीकदान बना रखा है। एक दिन पंडिताईन ने उनसे कहा मेरा गुजारा कैसे करोगे, बाहर जाओ, कुछ करो, नहीं तो अच्छा होगा डूब मरो पण्डित जी भी हाजिर जवाबी फोरन बोले पानी लाओ डूब मरूंगा, किंतु मुझे घर से बाहर मत भेजो। पंडिताईन गुस्से से बोली फौरन निकलो, यहां पानी नहीं लाऊगी, अगर मेरे सामने सही में डूब मरे तो मैं विधवा हो जाऊगी और उन्होंने झट पण्डित जी को घर से बाहर का रास्ता दिखाकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। पंडिताइन की बात सुनकर होशियार चंद जी पहली बार घर से निकले कि कुछ आवारा कुत्तों ने उन्हें देखा और घर से न निकलने पर पहचान न होने पर अंजान व्यक्ति समझ उन पर भोंकने लगे। पण्डित जी कुत्तों को देख सरपट भागे, कुत्तों से तो बच गए किन्तु उन्हें भागते हुए सिपाही ने देख लिया फौरन सिपाही ने अनुमान लगाया ओर समझे मामला गडबड है पण्डित कहीं चोरी करके तो नहीं भाग रहा है बस पुलिसवाला पण्डित जी के पीछे डण्डा लेकर दौड पडा और पण्डित जी पीपल के पत्तों की तरह थर थर कॉपते भागते एक बंगले में घुस गए जो शहर के कप्तान साहब का था जो संयोग से अपने बंगले के दालन में एक चादर ओढ़कर किसी अनसुलझे पेचीदा मामले को हल किए जाने की युक्ति सोचते हुये गहरी नींद में जा चुके थे ओर एक डरावना सपना देख अपना आपा खो कर गाली गलौच कर रहे थे।

कप्तान साहब सपने में किसी शैतान के चंगुल में थे ओर उनके प्राण शैतान की मुट्ठी में , वे प्राण बचाने के लिए घिघिया रहे थे तो कभी जोरों से चीख रहे थे कि पुलिसवाले ओर कुत्ते से अपने प्राण बचाने निकला पंडित होशियार चंद झट से खुद के प्राण बचाने के लिए कप्तान साहब से लिपट गए। कप्तान साहब ने ज्यों ही आंखे खोलीं, त्यों ही पंडित को अपने से लिपटा पाया, तब सपने वाला वह महाभायंकर शैतान नही दिखा? कप्तान साहब घबरा कर पंडित से बोले तुम कौन? जिसने मेरे प्राणों को शैतान से बचाया, मैं प्रसन्न हूँ ओर तुम्हारा कृतज्ञ हूँ जो तुमने कृपा की । अगर तुम मोके पर नहीं आते निश्चित ही वह शैतान मेरे प्राण ले लेता, इस प्रकार कप्तान साहब ने सारा किस्सा होशियार चंद को सुनाया। कप्तान की बातें सुनकर पंडित जी की आँखों में चमक आ गई, चलो अब उनपर आया खतरा टल गया, तुरंत पंडित बेढंगा जी ने अपना रंग बदला ओर कप्तान साहब से कहा आज शनि के योग से राहू केतू की तिकड़ी से कप्तान साहब के प्राणों को खतरा था जिसे वे अपने घर के दिव्य साधना कक्ष में बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पूर्व ही भाँप गए ओर कप्तान साहब के दारुण दुख का नाश करने के लिए हर तरह का खतरा मौल लेते हुये आए ओर उनके प्राण बचाकर अपने जीवन को दाब पर लगा लिया।

पंडित होशियार चंद ने बड़ी चालाकी से हाथ आए इस मौके को गवाना उचित न समझ तुरंत ही कप्तान से कहा झआपके प्राणो के संकट को देख मैं घर से निकला ही था की पत्नी से खटपट हो गई। शनि की घड़ियों ने रोकना चाहा कि कोई आपकी मदद न करू, पत्नी की बिछाई गई बाधा को जैसे तैसे पार कर घर से निकल सड़क पर आपके घर की ओर दौड़ लगाई की मुझे भागता देख कुत्तों ने रोका पर मैंने भागना बंद नही किया कि मुझे एक मूर्ख पुलिसवाले ने रोका, किन्तु में बिना समय गवाए आपको बचाना चाहता था ओर कुत्तो ओर पुलिसवाले कि परवाह किए बिना भागा। अगर रुक जाता तो शनि के भेजे शैतान से आप कैसे बचते? आपके पास आया तो आपको संकट में देखा , मानों मौत आप पर सवार थी , बस मैं मौत के सामने आपको बचाने के लिए झगड़ा करने को तैयार था। किसी कायर की तरह चुप खड़ा रहे की अपेक्षा मैंने शैतान को ललकारा, वह भाग गया, मरा नही है, जीवित है, हो सकता है दुबारा आए ओर आप पर हमला करे। इसलिए मेरा आपके यहा रहना आवश्यक है। कप्तान साहब ने होशियार को गले लगा कर सदा के लिए पुलिस महकमे का ज्योतिषी बना दिया ओर कहा आपने मुझे बचाया मेरा जीवन बचाया, आपको जो भी, जितना धन चाहिए मैं दूंगा, तुरंत शहर भर के अपराधियों से हफ्ता वसूली का पुण्य होशियार चंद बेढंगा पंडित को अर्पित होने लगा। जिस पुलिसवाले ने उन्हे रोकने का प्रयास किया वह सेवा से बाहर कर दिया गया तथा कुत्ते के मुंह पर अलीगढ़ के ताले जड़ दिये गए ताकि यह कुत्ता दुबारा होशियार चंद पर नहीं भोंके । इस तरह पंडित होशियार चंद बेढंगा को उनही जैसा कप्तान मिल गया ओर दोनों को रोजगार बिना रुकावट के चल पड़ा।

अभी वे 400 प्लस की बात कर रहे हैं, मई के अंत तक इंतजार करें, पाएंगे कि संख्या 250 से कम रह जाएगी। जून के पहले हफ्ते तक यह संख्या 175-200 के बीच रहनी चाहिए...मैं आधा दर्जन अल्फांसों आमों के दाम की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि हर संदेश में राजनीति ही जुड़ी हो।
— डॉ. एस.वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त@DrSYQuraishi

इतिहास के सबक

भारत डोगरा

आधिपत्य नहीं सहयोग के संबंध जरूरी

विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के बावजूद विश्व में जिस तरह कई स्तरों पर लोगों के दुख-दर्द बढ़े हैं, युद्ध और हिंसा का संकट कई तरह से बढ़ा है, पर्यावरण का संकट उग्र हुआ है, उसने इस विषय पर चिंतन बढ़ाया है कि वे कौन-सी बुनियादी विसंगति या विकृतियां हैं जिनके कारण विश्व सही राह पर नहीं चल पा रहा है।

यदि इतिहास के पृष्ठों में इन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजें तो एक बड़ी समझ यह बनती है कि विभिन्न स्तरों पर आधिपत्य के संबंध हावी होने के कारण दुख-दर्द बहुत बढ़ सकता है। दूसरी ओर, आधिपत्य के स्थान पर सहयोग के संबंध आ सकें तो यह दुख-दर्द बहुत कम हो जाता है। बहुत-सी गंभीर, व्यापक समस्याओं की गहराई में हम जाएं तो कहीं न कहीं टूटते, बिखरते मानवीय संबंधों की भूमिका हमें दिखाई देगी। मनुष्यों के आपसी संबंधों की एक प्रमुख कमजोरी और कमी यह है कि एक दूसरे पर आधिपत्य करने, शासन करने, अपना बड़प्पन सिद्ध करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल रही है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस प्रवृत्ति के साथ अधिकतर एक दूसरे का हक छीनने, अधिक संचय करने या अधिक लालच की प्रवृत्ति जुड़ी रही है। पर जहां यह लालच नहीं है, वहां भी अहं के कारण अपनी उच्चता स्थापित करने या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति प्रायः देखी गई है। कारण अहं हो या लालच, मनुष्य के आपसी संबंधों में आधिपत्य करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त और व्यापक रही है। जहां जनसाधारण के दैनिक जीवन में इस प्रवृत्ति ने तरह-तरह के दुख-दर्द उत्पन्न किए, वहां युद्ध के मैदान में इस कारण भयानक खून-खराबा भी हुआ। इतिहास के पृष्ठ गवाह हैं कि बहुत प्राचीन समय से ही गुलाम और मालिक, गरीब और अमीर, पराजित और विजेता, कमजोर और बलशाली, यहां तक कि स्त्री और पुरुष के संबंध में आधिपत्य करने की प्रवृत्ति ने बहुत से लोगों को अत्यधिक और असहनीय दुख दिए।

बहुत से लोगों पर यह प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है कि उन्होंने अपने आदर्श के रूप में उन्हीं को ग्रहण करना आरंभ किया जो अपना आधिपत्य जमा सकें। सोचने-समझने के ढंग, बातचीत, कथा-कहानियों, यहां तक कि इतिहास में भी उन लोगों को अधिक महत्त्व दिया गया-और प्रायः प्रशंसा की भावना से ही दिया गया-जिन्होंने अपने आधिपत्य को अधिक फैलाने में सफलता प्राप्त की, चाहे इस प्रयास में उन्होंने कितने ही लोगों को नाहक ही अथाह कष्ट पहुंचाए हों। दूसरी ओर, अनेक धर्म-गुरुओं, दार्शनिकों और समाज सुधारकों ने इंसान की इस मूल कमजोरी और इससे जुड़े दुख-दर्द को पहचाना और लोगों को इससे बचाने का प्रयास किया। इनमें से अनेक प्रयासों का असर दूर-दूर तक हुआ और काफी समय तक हुआ। अतः इतिहास में ऐसे दौर भी आए जब आधिपत्य पर आधारित मानव संबंधों को बहुत से लोगों ने एक बुराई के रूप में पहचाना और इसके स्थान पर भाई-चारे, समता, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों की इज्जत करने और समझने का प्रयास करने की प्रवृत्ति को अपनाया। कुछ समयों और स्थानों में इन विचारों का प्रसार विभिन्न धर्मों और पंथों के रूप में हुआ, अन्य मौकों पर इनका प्रसार नई आर्थिक-राजनीतिक विचारधाराओं और उनसे जुड़ी क्रांतियों के रूप में हुआ। अनेक सराहनीय शुरुआतों के बावजूद बाद में इन प्रयासों में भी प्रायः कुछ कमजोरियां आ जाती थीं, और आधिपत्य की प्रवृत्ति को फिर प्रबल होने या पहले से भी अधिक प्रबल होने का मौका प्रायः मिल जाता था। आरंभ में इस प्रवृत्ति को हावी करने का अवसर किसी व्यक्ति को छोटे से समूह के स्तर पर ही मिल सकता था, पर बाद में आधिपत्य की महत्त्वाकांक्षा का बेहद विस्तार कर ऐसे साम्राज्य स्थापित किए गए जो लाखों पराजित लोगों और गुलामों पर आधिपत्य कर सके।

विश्व इतिहास के शायद सबसे निर्मम शोषण और तबाही की शुरुआत हुई। यूरोप से दौलत और जमीन के लालच में गए लोगों ने यहां के मूल निवासियों (रेड इंडियन) पर हर तरह के अत्याचार किए, उनसे जबरन मजदूरी करवाई, उनकी जमीन छीनी, अनेक जगह उनका कत्लेआम किया। करोड़ों की संख्या में यहां के मूल निवासी मारे गए। हजारों वर्ग मील के क्षेत्रों में वे खत्म ही कर दिए गए। अमेरिकी महाद्वीपों में कोलंबस के आगमन के समय (वर्ष 1500 के आसपास) लगभग 10 करोड़ लोग रहते थे। यूरोप के लोगों के यहां आने के बाद के डेढ़ सौ वर्षों में ही 90 प्रतिशत मूल निवासियों की मृत्यु हो गई, मात्र 10 प्रतिशत बचे। बाद में आस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों पर भी ऐसा ही अत्याचार हुआ।

उधर, अमेरिका के मूल निवासी बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे, इधर यूरोप के लुटेरों ने अफ्रीका के गुलामों को पकड़ कर अमेरिका के खेतों और खदानों में भेजना आरंभ किया। लगभग 350 वर्षों तक जारी रहे इस व्यापार में लगभग डेढ़ करोड़ अफ्रीकावासियों को गुलाम के रूप में अमेरिकी महाद्वीपों में भेजा गया। भेजने का तरीका इतना निर्दयी था कि लाखों गुलाम तो यात्रा के दौरान ही मर गए और अधिकांश अन्य की मौत कार्यस्थल पर निर्मम शोषण के कारण कुछ वर्षों में हो गई। साथ ही, एशिया के अधिकांश देशों का इतना कठोर शोषण हुआ कि भुखमरी और अकाल से लाखों लोग मरने लगे। इस औपनिवेशिक दौर ने कुछ देशों को बाहरी लूट के आधार पर भौतिक सुख-सुविधाओं और संपत्ति की ऐसी व्यवस्था खड़ी करने दी जिसे बनाए रखने के लिए आज भी अनेक तौर-तरीकों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषमता और आधिपत्य की प्रवृत्ति को दृढ़ किया जा रहा है। विभिन्न समाजों में कदम-कदम पर किसी जाति, नस्ल, वर्ग, गुट, व्यवसाय आदि का बड़प्पन सिद्ध करने और उसका आधिपत्य स्थापित करने के प्रयासों से सामुदायिक मेलजोल की भावना से कार्य आगे बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, नाहक तरह-तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं और सब लोगों की सूझबूझ और सोच-विचार का पर्याप्त लाभ हमें नहीं मिलता है। समाज की जो ऊर्जा सार्थक कार्य में लगनी थी, वह बेवजह उत्पन्न किए गए तनावों में नष्ट हो जाती है।

आधिपत्य के संबंधों में चाहे ऊपरी और फौरी तौर पर क्षति केवल दबाए गए व्यक्ति की होती है, पर गहरे और दीर्घकालीन स्तर पर क्षति दबाने और कुचलने वाले व्यक्ति की भी होती है। जो दूसरों से शोषण और निर्दयता का व्यवहार करते हैं, वे या तो इस कारण ऐसे अपराधबोध से पीड़ित होते हैं, जो उनके जीवन की सुख-शांति छीन लेता है, अथवा (इस अपराधबोध से बचने के लिए) उन्हें अपने जीवन में इतनी संवेदनविहीनता लानी पड़ती है कि वे जीवन के अनेक प्रसन्नता और संतोष देने वाले अनुभवों से वंचित हो जाते हैं। इसका असर उनके जीवन के सबसे नजदीकी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि जहां आधिपत्य के आधार पर बहुत सी भौतिक संपदा अर्जित कर ली जाती हैं, वहां भी तनाव, अवसाद और नैतिक पतन से जीवन तबाह रहता है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

इस तरह आधिपत्य के संबंधों के दोनों ओर दुख-दर्द बढ़ते हैं, आधिपत्य से त्रस्त होने वालों में भी और आधिपत्य जमाने वालों में भी। यह इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण पर उपेक्षित सबक है कि आधिपत्य के संबंधों को दूर कर सहयोग के संबंध विकसित करने के प्रयास निरंतरता से होने चाहिए।

वे कौन-सी बुनियादी विसंगति या विकृतियां हैं जिनके कारण विश्व सही राह पर नहीं चल पा रहा है। यदि इतिहास के पृष्ठों में इन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजें तो एक बड़ी समझ यह बनती है कि विभिन्न स्तरों पर आधिपत्य के संबंध हावी होने के कारण दुख-दर्द बहुत बढ़ सकता है। दूसरी ओर, आधिपत्य के स्थान पर सहयोग के संबंध आ सकें तो यह दुख-दर्द बहुत कम हो जाता है। बहुत-सी गंभीर, व्यापक समस्याओं की गहराई में हम जाएं तो कहीं न कहीं टूटते, बिखरते मानवीय संबंधों की भूमिका हमें दिखाई देगी। मनुष्यों के आपसी संबंधों की एक प्रमुख कमजोरी और कमी यह है कि एक दूसरे पर आधिपत्य करने, शासन करने, अपना बड़प्पन सिद्ध करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल रही है। इस प्रवृत्ति के साथ अधिकतर एक दूसरे का हक छीनने, अधिक संचय करने या अधिक लालच की प्रवृत्ति जुड़ी रही है

कुछ विज्ञापन कुछ विखंडन

मीडिया

सुधीश पचौरी

खबर चैनलों में आते विज्ञापन ध्यान खींचते हैं: एक निम्न मध्यवर्गीय घर। पत्नी के चेहरे पर नाराजी छाई है। दूधरहित काली चाय बनाकर देती है। उस चाय का घूंट लेकर जैसे ही पति मुंह बना कर कहता है कि ये क्या बना दिया है तो पत्नी कहती है तुमने व्हाट्सऐप सरकार बनाई उसकी महंगाई में यही मिल सकता है। फिर गुस्से से कहने लगती है, 'मेरे विकास का दो हिसाब'। फिर हाथ का चित्र आता है, जो कहता है : 'हाथ बदलेगा हालात'। यह विज्ञापन एनडीए के शासन में बढ़ती महंगाई पर कटाक्ष करता है, और कांग्रेस का 'हाथ' ही 'हालात बदलेगा', ऐसी आश्वस्ति देता है। दूसरा विज्ञापन 'बेरोजगारी' पर चोट करता है। 'वॉयसओवर' कहता है कि इंजीनियरिंग के आखिरी बरस में बता दिया गया था कि बड़ी नौकरी मिलेगी...इंजीनियरिंग पास जब ये नौजवान अपने बाल काढ़कर और टाई लगाकर नौकरी के लिए घर से निकलता है तो किसी बड़ी नौकरी की जगह, घर के सामने खड़ा एक 'ई-रिक्शा' नजर आता है। वह गुस्से में अपनी टाई निकाल कर उस 'ई रिक्शा' को ड्राइवर बन चलाने के लिए बैठ जाता है, और गुस्से से भर कर कहता है 'मेरे विकास का दो हिसाब'। फिर आता है 'हाथ' का वही चिह्न जो कहता है कि 'हाथ बदलेगा हालात'।

इनके बरक्स भाजपा के विज्ञापन कुछ अलग भाषा बोलते नजर आते हैं। एक विज्ञापन काफी लंबा है। इसमें मोदी की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को पहुंच रहे लाभों को आम लोगों द्वारा ही कई भाषाओं में गाकर बताया जाता है, और अंत में कहा जाता है 'ये तो अभी ट्रेलर है' और अंत में सब कहते हैं कि जब मोदी की गारंटी हमारा कल्याण है तो हमारी गारंटी मोदी को जिताना है। अंत में ऊपर 'विकसित भारत' लिखा आता है, और नीचे मोदी के चित्र के साथ लिखा आता है 'अबकी बार मोदी सरकार!' ऐसे ही एक विज्ञापन में तीन युवक मोदी द्वारा किए गए राम मन्दिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत अन्य तीर्थों के विकास के बारे में खुशी-खुशी बताते हुए भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और कहते हैं 'ये तो अभी ट्रेलर है'...फिर कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है तो हमारी भी गारंटी है कि मोदी को जिताएं...। ऐसे ही एक विज्ञापन एक परिवार की तीन पीढ़ी की स्त्रियों के जरिए कहता है कि मोदी जी ने दवाएं सस्ती की, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। अब सब खुश हैं। एक बच्ची कहती है मोदी जी कहते हैं कि 'ये तो अभी ट्रेलर है'... जब मोदी हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारी गारंटी मोदी को जिताने की है...ऐसे ही, एक पिता-पुत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चरचा करते हैं। फिर कहते हैं मोदी जी के कहते हैं 'ये तो अभी ट्रेलर है'...। फिर पुत्री कहती है कि हमारा सपना पूरा करने की गारंटी मोदी जी की तो मोदी जी का सपना पूरा करने की गारंटी हमारी...।'

'मोदी की गारंटी' के बदले 'जनता की मोदी को जिताने की गारंटी' की बात जनता की 'थैंक्स गिविंग' की तरह दिखती है। जैसे पब्लिक कहती हो कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हमारा भी कर्त्तव्य है कि उनके लिए भी कुछ करें...कहने की जरूरत नहीं कि ये विज्ञापन 'इंटरएक्टिव विज्ञापन' हैं, जो पॉजिटिव संदेश देकर जाते हैं और जो मोदी की नीतियों से बने लाभार्थियों को मोदी के पक्ष में 'एक्टिवेट' भी करते हैं। यहां एक भी चेहरा किसी से नाराज नहीं दिखता।

सब मोदी की गारंटियों के दीवाने दिखते हैं। यह इनका 'फीलगुड फेक्टर' है जबकि कांग्रेसी विज्ञापनों में नाराजी अधिक मुखर है। वे मोदी शासन के विरोध में जनता की नाराजी को हवा देते दिखते हैं। मानो जनता सत्ता से उतनी ही नाराज हो जितनी कि कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का एक तीसरा विज्ञापन अवश्य जरा पॉजिटिव दिखता है। इसमें तीस लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया जाता है। फिर एक युवक को नौकरी मिली बताई जाती है। अंत में बड़े अक्षरों में 'जून, 2024' लिखा आता है। साथ ही 'हाथ' के चित्र के साथ 'हाथ बदेलगा हालात' वाली कैचलाइन भी नजर आती है। साफ है कांग्रेसी विज्ञापनों में नाराजी ज्यादा दिखती है, जो विज्ञापन कला के हिसाब से भी उचित नहीं दिखती क्योंकि 'पॉजिटिव' विज्ञापन' ही असर करते हैं। नकारातमक विज्ञान कारगर नहीं होते। इस मानी में मोदी के विज्ञापन हर बार पॉजिटिव संदेश देते लगते हैं। इस तरह वे अधिक कारगर नजर आते हैं।

सब मोदी की गारंटियों के दीवाने दिखते हैं। यह इनका 'फीलगुड फेक्टर' है जबकि कांग्रेसी विज्ञापनों में नाराजी अधिक मुखर है। वे मोदी शासन के विरोध में जनता की नाराजी को हवा देते दिखते हैं। मानो जनता सत्ता से उतनी ही नाराज हो जितनी कि कांग्रेस नाराज है

पूर्व से पश्चिम तक संकट में एशिया

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान एशिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो को प्रकारांतर से खुला न्योता दिया गया। किशिदा ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के विश्व स्तर पर कायम वर्चस्व को बनाए रखने की वकालत की। उन्होंने अमेरिका की हिमायत में वे सभी बातें कहीं जो वहां के नेताओं और सांसदों के लिए कर्णप्रिय थीं। किशिदा ने अमेरिका के नेतृत्व और नीतियों की इतनी पुरजोर तारीफ की कि पता लगाना मुश्किल हो गया कि अमेरिका ही वह देश था जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले के लिए अमेरिका ने कभी जापान से माफी नहीं मांगी। किशिदा जैसे जापानी नेताओं ने मानो यह स्वीकार कर लिया कि परमाणु हमले के लिए हम खुद जिम्मेदार थे।

किशिदा का संबोधन भारत और एशिया के अन्य देशों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि उन्होंने चीन के साथ ही रूस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दक्षिण चीन सागर और पूर्व एशिया में चीन की आक्रामक गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि यह क्षेत्र नया यूक्रेन बन सकता है। जाहिर है कि वह अमेरिका के नेताओं से गुहार लगा रहे थे कि वे यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देते समय इंडो पेसेफिक देशों को नजरअंदाज न करें। किशिदा ने कहा कि उनका देश रूसी आक्रमण के खिलाफ संघर्षरत यूक्रेन के साथ खड़ा है। किशिदा ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इंडो पेसिफिक में सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। उनके भाषण का यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक 'एशियाई नाटो' के पक्ष में है।

गौर करने वाली बात होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्षों पहले क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाए थे। क्वाड का कोई सैनिक मंसूबा नहीं था, लेकिन किशिदा जिस एशियाई सुरक्षा ढांचे की बात कर रहे हैं, वह अमेरिका के वर्चस्व वाला सैनिक गठबंधन जैसा है। जाहिर है कि भारत किशिदा के इन विचारों और नीतियों से सहमत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक को दिए गए साक्षात्कार में चीन के साथ संबंधों को पटरी पर लाने के लिए एक पहल की है। मोदी ने कहा है कि सीमा पर लंबे समय से चल रहा तनाव दोनों देशों में से किसी के हित में नहीं है। उनकी यह सोच किशिदा से एकदम अलग है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच किशिदा की यह यात्रा बाइडन को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है। किशिदा ने कहा कि अमेरिका के नेताओं को अपनी ग्लोबल भूमिका को लेकर कोई संदेह और दुविधा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने अपने बलबूते दुनिया में स्थायित्व कायम रखा है। उसे अपनी यह भूमिका जारी रखनी चाहिए तथा इस क्रम में जापान पूरी तरह उसके साथ है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद निशस्त्र कर दिया गया था। तकनीकी रूप से जापान आज भी सेना नहीं रख सकता लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की सैन्य मुहिम को बिना शर्त समर्थन देने का ही नतीजा है कि जापान आज एक सैन्य ताकत बनने की राह पर है। जिस देश से शांति के पैगाम की उम्मीद थी, वह युद्ध का नगाड़ा बजा रहा है। वह भी ऐसे समय जब गाजा में इस्राइल का नरसंहार जारी है तथा फारस की खाड़ी के बीच संभावित संघर्ष जापान के लिए मारक सिद्ध हो सकता है। यह संघर्ष यदि व्यापक रूप लेता है तो दुनिया का कच्चे तेल का आधा कारोबार ठप हो जाएगा। रूस से ऊर्जा आयात कम करने वाला जापान इस नये संकट का सामना कैसे करेगा।

वास्तव में भारत के लिए भी पश्चिम एशिया का संकट नई आर्थिक चुनौती पेश कर सकता है। गनीमत यह है कि रूस एक विश्वसनीय ऊर्जा प्रदाता देश है जो आड़े समय में भारत के काम आएगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कितना ऊपर जाता है, यह विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए निर्णायक होगा। रूस के खिलाफ यदि प्रतिबंध जारी रहा और पश्चिमी एशिया से तेल आपूर्ति बाधित हुई तो जापान और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है।

किशिदा का संबोधन भारत और एशिया के अन्य देशों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि उन्होंने चीन के साथ ही रूस पर भी निशाना साधा

भारतीय संस्कृति का इंद्रधनुषी गुलदस्ता

बैसाखी पर्व

योगेश कु. गोयल

कृषि प्रधान देश भारत में बैसाखी पर्व का संबंध फसल पकने के बाद उनकी कटाई से जोड़कर देखा जाता रहा है। वैसे विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्यौहार माना जाने वाला यह त्यौहार पंजाब ही नहीं, बल्कि देश भर में लगभग सभी स्थानों खास तौर से पंजाबी समुदाय द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सिख बैसाखी से ही नये साल की शुरुआत मानते हैं, और इसलिए भी एक-दूसरे को बैसाखी की बधाइयां देते हैं। पंजाब देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है, जब यहां किसान अपने खेतों को फसलों से लहलहाते देखता है, तो खुशी से झूम उठता है। खुशी के इसी आलम में शुरू होता है गिद्दा और भांगड़ा का मनोहारी दौर। यही वजह है कि विशेष रूप से पंजाब में बैसाखी के पर्व पर गिद्दा और भांगड़ा के मनोहारी कार्यक्रम न हों, यह हो ही नहीं सकता। यहां ढ़ोल-नगाड़ों की धुन पर पारंपरिक पोशाक में युवक-युवतियां नाचते-गाते और जश्न मनाते हैं तथा गुरुद्वारों को फूलों तथा रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है।

उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब-हरियाणा में गिद्दा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले ही काफी जोश देखने को मिलता है लेकिन वास्तव में यह त्यौहार विभिन्न धर्म एवं मौसम के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे 'नबा वर्ष' के नाम से मनाया जाता है, तो केरल में 'विशू' तथा असम में 'बीहू' नाम से मनाया जाता है। बंगाल में 'पोइला बैसाखी' भी कहा जाता है, और वे इसे अपने नये साल की शुरुआत मानते हैं। हिन्दू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन गंगा आरती करने तथा पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा रही है।

बैसाखी पर्व के साथ भारतीय इतिहास की कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। इसी दिन अर्थात 13 अप्रैल, 1699 को सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोबिन्द सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी। इस पंथ की स्थापना करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था लोगों को मुगल शासकों के अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाना तथा इन अत्याचारों का सामना करते हुए देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। गुरु गोबिन्द सिंह कलम के साथ-साथ तलवार के भी उपासक थे और उनके पंच प्यारों में सभी जातियों के लोग शामिल थे। उन्होंने अन्याय, विरोध एवं पाखंड के सर्वनाश की प्रेरणा और मानव जाति को एकता का संदेश देते रहने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था।

बताया जाता है कि लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे 'शेरे पंजाब' महाराणा रणजीत सिंह का राजतिलक भी बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी को सूर्य वर्ष का प्रथम दिन माना गया है क्योंकि इसी दिन सूर्य अपनी पहली राशि मेष में प्रविष्ट होता है। इसलिए इस दिन को 'मेष संक्रांति' भी कहा जाता है। देखा जाए तो बैसाखी का पर्व हमारे लिए खुशियों का पर्व तो है ही लेकिन इसके साथ-साथ यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोये हुए है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोबिन्द सिंह जैसे महापुरुषों के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और हमें संदेश देता है कि हमें देश में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के नये युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

हाल फिलहाल हम तरस खाते हैं

बतंगड़ बेतुक

विभांशु दिव्याल

झल्लन ने हमें जुहार किया और हमारी बगल में अपना ठीया गह लिया। जब वह आदत के विपरीत बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो हमने ही अपना मुंह खोला, 'क्या हुआ झल्लन, आज चुप्पी काहे मार ली है, काहे चेहरे पर मनहूसियत उतार ली है?' झल्लन बोला, 'सही पकड़े हो ददाजू, हमारे भीतर मनहूसियत भर रही है, वही हमारे चेहरे पर उतर रही है। हम सुखी हों या दुखी हों, हंसे या रोयें, गुस्सा करें या तरस खायें, चिल्लाएं या हमदर्दी दिखाएं, इनमें से क्या करें यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, शायद इसीलिए हमारे चेहरे पर मनहूसियत छा रही है।' हमने कहा, 'आखिर हुआ क्या जिसने तुझे इतनी विकट दुविधा में ले लिया है और तेरे इर्द-गिर्द मनहूसियत ने डेरा डाल दिया है?' वह बोला, 'ददाजू, जब हाई कोर्ट ने ईडी का पूरा साथ दिया था और हमारे केजरी भैया को तगड़ा झटका दिया था तब हम निश्चिंत थे कि केजरी भैया हार नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा देंगे, उनका जो पक्ष हाई कोर्ट की समझ में नहीं आया उसे सुप्रीम कोर्ट को जरूर समझा देंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाएंगे और जिस सरकार को वह जेल के भीतर से चला रहे हैं उसे जल्दी ही बाहर लाकर चलाएंगे।'

हमने कहा, 'ठीक है, तेरे केजरी भैया ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की तारीख लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तू दुविधाग्रस्त क्यों हो रहा है, तू फालतू में क्यों रो रहा है?' वह बोला, 'ददाजू, सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगा तब सुनेगा, जो फैसला करेगा सो करेगा पर फिलवक्त तो हमें केजरी भैया की सरकार के दलित मंत्री आनंद कुमार पर गुस्सा आ रहा है जिसने पार्टी और सरकार से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और सच कहें तो हमारे केजरी भैया की पीठ में छुरा घोंप दिया है।' हमने कहा, 'इसमें छुरा घोंपने की बात कहां से आ गयी, मंत्री हैं, जब तक अच्छा लगा काम किया, जब बुरा लगा तो इस्तीफा सौंप दिया। जब केजरी भैया को छोड़कर जाने वाले बड़े-बड़े लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाये तो एक और व्यक्ति पार्टी से निकलकर उनका क्या बिगाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। तेरे भैया जेल में रहेंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे, बाहर आ गये तो बाहर से सरकार चलाएंगे, मोदी और मोदी सरकार के विरुद्ध जैसे चिल्लाते रहे हैं वैसे ही आगे भी चिल्लाएंगे।'

झल्लन बोला, 'ददाजू, या तो आप हमें बेवकूफ समझ रहे हो या आप जानबूझकर हमारी बात नहीं पकड़ रहे हो। जब जेलबंद केजरी भैया के जेलबाहर के सारे सिपहसालार चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया गया है, उन्हें ईडी द्वारा फंसाया गया है तब उनका ही एक कद्दावर मंत्री सीधे-सीधे उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगा रहा है, अपने आरोपों के समर्थन में सबको दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला दिखा रहा है। कह रहा है कि केजरी सरकार भ्रष्टाचार के दल-दल में फंसी हुई है इसलिए दुनियाभर में उसकी इतनी हंसी हुई है सो अब उसका जमीर गवारा नहीं करता कि वह इस भ्रष्ट सरकार का मंत्री बना रहे और अपनी अंतरात्मा की आवाज से धोखा करता रहे। अब बताइए, जब आपका अपना आदमी आपको आईना दिखा रहा है, आपको भ्रष्टाचारी बता रहा है तो ऐसे तो केजरी भैया के ईमानदारी के दावे की सारी हवा निकल जाएगी और मोदी सरकार के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान की गाड़ी ही पटरी से फिसल जाएगी। हमें लगता है आनंद कुमार के इस्तीफे ने आप नेताओं के हाथ से नैतिकता का हथियार ले लिया है और इस हथियार को भाजपाइयों के हाथ में दे दिया है।'

हमने कहा, 'देख झल्लन, हम नहीं कहते कि भाजपा दूध की धुली है या भाजपा की हर खिड़की ईमानदारी की तरफ ही खुली है। लेकिन हमें लगता है कि तेरे केजरी भैया की जो दुर्गति हो रही है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं यानी उनकी दुर्गति के कारण उनके अपने वाणी-व्यवहार हैं। यह आदमी भ्रष्टाचार मिटाने आया था, यह समझता था कि यह मंच से भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाता जाएगा, जनता के सामने उन्हें खलनायक बनाता जाएगा, अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाता जाएगा। पहले राज्य में फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा और जैसे ही यह अपनी सरकार बनाएगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। इसे भ्रम था कि नेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता इसकी ईमानदारी का जश्न मनाती रहेगी और इसे सत्ता का ताज पहनाती रहेगी। पर इस अल्पज्ञ को यह पता नहीं था कि भ्रष्ट व्यवस्था खुद इसे ही भ्रष्टाचार करने को विवश कर देगी, इसे और इसकी पूरी सरकार को भ्रष्टाचार में लिथेड़ देगी और अंततः इसकी बखिया उधेड़ देगी। कम से कम अब इसे ठोस वास्तविकता की जमीन पर आ जाना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी गलतियों को समझना और सुधारना चाहिए।' झल्लन सर खुजाते हुए बोला, 'ठीक है ददाजू हम समझ गये, हाल फिलहाल हम केजरी भैया पर तरस खा रहे हैं, अपनी बाकी की भावनाएं आगे के लिए बचा रहे हैं।'

हमने कहा, 'देख झल्लन, हम नहीं कहते कि भाजपा दूध की धुली है या भाजपा की हर खिड़की ईमानदारी की तरफ ही खुली है। लेकिन हमें लगता है कि तेरे केजरी भैया की जो दुर्गति हो रही है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं यानी उनकी दुर्गति के कारण उनके अपने वाणी-व्यवहार हैं। यह आदमी भ्रष्टाचार मिटाने आया था, यह समझता था कि यह मंच से भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाता जाएगा, जनता के सामने उन्हें खलनायक बनाता जाएगा, अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाता जाएगा। पहले राज्य में फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा और जैसे ही यह अपनी सरकार बनाएगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। इसे भ्रम था कि नेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता इसकी ईमानदारी का जश्न मनाती रहेगी और इसे सत्ता का ताज पहनाती रहेगी। पर इस अल्पज्ञ को यह पता नहीं था कि भ्रष्ट व्यवस्था खुद इसे ही भ्रष्टाचार करने को विवश कर देगी, इसे और इसकी पूरी सरकार को भ्रष्टाचार में लिथेड़ देगी और अंततः इसकी बखिया उधेड़ देगी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-33, अंक 240 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

गांधी ने हमें प्रसिद्ध मंत्र दिया था : सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद रखें और ध्यान रखें कि उसके हालात साजगार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आज जब असमानता जोर पकड़ चुकी है, तो नया मंत्र ईजाद करना होगा : अपने परिचित सबसे धनी व्यक्ति का चेहरा याद करें और प्रसन्न रहें।
—कौशिक बसु, अर्थशास्त्री@kaushikcbasu

बहस

प्रेम प्रकाश

विरासत विकास और दशक

देशकाल की समझ देश के साथ की भी है, और इससे आगे की भी। इस समझ के साथ काल और कालखंड को भी जोड़ दें, तो धारणा और तथ्य, दोनों थोड़े वर्गीकृत रूप में नजर आएंगे। इस भूमिका के साथ भारत के समकाल को देखना दिलचस्प है, खास तौर पर इसकी एक दशक की यात्रा। किसी देश की राजनीति में एक दशक का प्रभुत्व मामूली नहीं है। यह प्रभाव आलोचना और इतिहास के लिहाज से युगीन महत्त्व को व्याख्यायित करता है। इस लिहाज से देखें तो भारत की बीते एक दशक की यात्रा कई मायने में विलक्षण है।

यह पूरा दौर भारतीय राजनीति के केंद्र में नरेन्द्र मोदी के स्थापित होने का है। 2014 से 2024 के बीच केंद्र और राज्य के बदले सत्ता समीकरण से आगे वैचारिक और ऐतिहासिक तौर पर जो बात सबसे अहम है, वह यह कि इस दौरान भारत के संघीय ढांचे को लेकर कई तरह की आपवादिकता खंडित हुई हैं। इस खंडन से आगे जो बात स्थापित हुई है, वह यह कि अब जम्मू कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप या गोवा की चर्चा के लिए अलग से किसी डिस्कलेमर की जरूरत नहीं। आज ये सब भारत की अखंडता और उसकी सामासिकता को बराबरी के साथ मजबूत करते हैं। यही नहीं, जिस विरासत और विकास के नेरेटिव की बात मौजूदा लोक सभा चुनाव में हो रही है, उसमें देश के ये तमाम हिस्से पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शामिल हैं।

पिछले कुछ समय में ऐसे कई संदर्भ और घटनाक्रम सामने आए हैं, जब भारतीयता के डीएनए को लेकर समझ की नई चौंध पैदा हुई है। खास तौर पर हाल के दिनों में दो ऐसे वाकिये सामने आए, जब यह जाहिर हुआ कि दशकों तक भारतीय मुख्यधारा से तकरीबन कटे रहे सूबे आज किस तरह महत्त्व पा रहे हैं। इस लिहाज से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दौरा खास तौर पर महत्त्वपूर्ण है। मोदी ने इस द्वीप पर बिताए पलों को तस्वीरों के साथ शेयर किया। उन्होंने लक्षद्वीप को एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया। दिलचस्प है कि इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की मालदीव से तुलना शुरू हो गई। पर मालदीव के युवा अधिकारिता, सूचना एवं कला मामलों की उपमंत्री मरियम शिउना ने जब इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की प्रशंसा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो बात काफी आगे बढ़ गई। देखते-देखते सारा मामला भारतीय गौरव और अस्मिता से जुड़ गया। एक के बाद एक आए सैकड़ों ट्वीट्स में भारतीयों ने जहां शिउना की बखिया उधेड़ी, वहीं दुनिया ने भारतीय एकता एवं अखंडता की ताकत देखी। करोड़ों भारतीयों का राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रबोध इतना प्रभावी रहा कि मरियम शिउना को अपना ट्वीट डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ा। बड़ी बात यह है कि यह सब किसी कूटनीतिक हस्तक्षेप के बगैर हुआ।

ऐसा ही दूसरा मौका तब आया जब गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। हिन्दू आस्था और परंपरा के साथ गोवा के इस जुड़ाव ने सबको दंग किया। गौरतलब है कि आज की तारीख में यह जुड़ाव इकहरा नहीं, बल्कि भारतीय एकता एवं अखंडता का उत्तर आधुनिक आख्यान है। एक ऐसा आख्यान जिसमें भारतीयता का गर्व तो शामिल है ही, स्वाधीनता संघर्ष का भारतीय मूल्य भी प्रकाशित होता है।

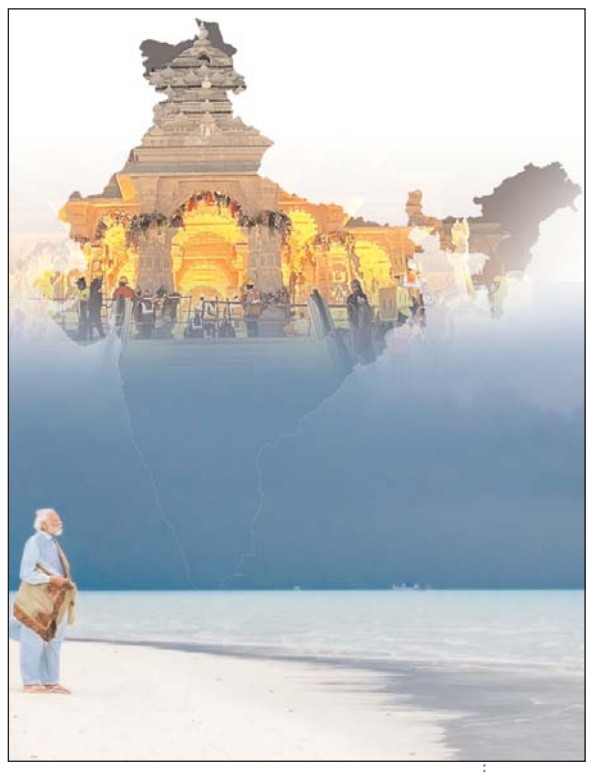

जिस गोवा के सांस्कृतिक आकर्षण को लेकर कभी एलेक पद्मसी जैसे दिग्गज कहते थे कि समुद्र के किनारे भारत का यह हिस्सा वेस्टर्न कल्चर का ईस्टर्न गेटवे है, वह गोवा आज सनातन और अध्यात्म के साथ अपने क्लचरल डीएनए पर नाज कर रहा है। गोवा का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के टैंपलेट के रूप में चर्चा में आना बीते एक दशक में भारत में आए बड़े परिवर्तन की गवाही है। इतिहास बताता है कि अंग्रेजों ने भारत पर करीब दो सौ साल शासन किया, लेकिन गोवा के लोगों ने साढ़े चार सौ

साल तक पुर्तगालियों को सहा। गोवा के मुख्यमंत्री इतिहास के इस पृष्ठ को खोलते हुए गर्व के साथ आज यह बात कहते हैं कि शताब्दियों लंबे विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप के बावजूद गोवा का कल्चरल कन्वर्जन न हो सका, वह लगातार भारतीय परंपरा के साथ जुड़ा रहा। भारत और भारतीयता से जुड़े नव विमर्श में जम्मू-कश्मीर का जिक्र भी जरूरी है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री के हाल के कश्मीर दौरे की चर्चा गौरतलब है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जब उन्होंने धारा 370 हटने के बाद वादी के लोगों के जीवन में आए बदलाव की चर्चा की तो इसके कई राजनीतिक-अराजनीतिक मायने निकाले गए। दिलचस्प है कि कश्मीर में आए बदलाव और खुलेपन का एक सिरा गोवा से भी जुड़ता है। ट्रैवलॉग की दुनिया के लोग लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, जिस कश्मीर को धरती पर जन्नत माना जाता है, वहां तो दुनिया भर से सैलानी पहुंच ही रहे हैं पर उस जन्नत से लोग जहां सैर- सपाटे के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, वह है गोवा।

बात गोवा की चली है तो यह जिक्र भी जरूरी है कि समुद्र तट से लगा भारत का यह सूबा सौ प्रतिशत घरों में नल से जल और बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य है। इतना ही नहीं, यह पहला राज्य है कि जहां प्रत्येक गांव में सड़कें हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने के मामले में भी गोवा बाकियों के लिए नजीर है। पूरे राज्य में उज्ज्वला योजना सौ प्रतिशत लागू की गई। गोवा आज किरोसीनफ्री स्टेट है। यह शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण वाला देश का पहला राज्य है। ऐसी योजनाओं की संख्या एक दो नहीं, बल्कि 13 हैं, जिनमें गोवा बाकी प्रदेशों के मुकाबले शीर्ष पर है।

आखिर में बात उन द्वीपों की, जिनका इस्तेमाल सिर्फ मानचित्र पर भारत के भौगोलिक विस्तार को दिखाने भर के लिए होता रहा। भूले नहीं हैं लोग उस ऐतिहासिक क्षण को जब गत वर्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 बेनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र सम्मानित शहीदों के नाम पर किया गया। देश की एकता एवं अखंडता के लिए बलिदान का इतिहास आज भारत को विरासत से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का न सिर्फ हौसला दे रहा है, बल्कि इसके साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का नया देशकाल भी आकार ले रहा है। ■

भूले नहीं हैं लोग उस ऐतिहासिक क्षण को जब गत वर्ष नेताजी की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 बेनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र सम्मानित शहीदों के नाम पर किया गया। देश की एकता एवं अखंडता के लिए बलिदान का इतिहास आज भारत को विरासत से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का न सिर्फ हौसला दे रहा है, बल्कि इसके साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का नया देशकाल भी आकार ले रहा है

डॉ. अशोक कुमार

मोबाइल में सिमटता बाल मन

आम तौर पर देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे बड़ों को देखकर मोबाइल के आदी हो रहे हैं। बच्चों में मोबाइल के उपयोग करने की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ रही है, वह चिंताजनक है। मनोवैज्ञानिक आधार पर माना गया है कि मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। फोन के अंदर से रेडियेशन की तरंग बच्चों के साथ साथ सबके लिए हानिकारक है। इससे बच्चों की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने लगती है और धीरे-धीरे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की क्षमता घटने लगती है जैसे उनका हंसना, बोलना, चलना, घूमना, खेलना आदि। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने परीक्षण पश्चात बताया है कि रेडिएशन कैंसर की नींव भी रख रहा है। एक अन्य प्रभाव देखा जा रहा है कि बच्चों के मानसिक विकास में रुकावट हो रही है। मोबाइल में हर समय व्यस्त बच्चे न तो पारिवारिक माहौल में सही ढंग से घुल-मिल पाते हैं, और न ही सामाजिक क्रियाकलाप से जुड़ पाते हैं। लगातार फोन के व्यवहार से बच्चों में सिर दर्द की शिकायत आम हो रही है, और उनकी आंखों पर चश्मे भी चढ़ने लगे हैं।

सवाल है कि आखिर, बच्चों की मोबाइल लत के पीछे कारण क्या हैं। आम तौर पर देखा जा रहा है कि अधिकांश माता-पिता अपने बच्चे को अधिक प्यार-दुलार के चलते हर सुविधा से लैस करने की चाहत में जरा भी कंजूसी नहीं करते। इसी कमजोरी के कारण बच्चे को पहले तो खिलौने के रूप में यह मिलता है, और बाद में यह लत बन जाती है। दूसरा कारण यह है कि जब बच्चा बाल हठ से रोना-धोना मचाता है, तो माता-पिता उसे फोन देकर फुसलाने की तरकीब रचते हैं। फोन में चलंत दृश्यों की चंचलता बच्चे का रोना तुरंत बंद कर देती है, और वह उसी में मगन हो जाता है। कई बार खाना खिलाने के लालच में बच्चों को फोन देना भी लत का प्रमाण है। कुछ बच्चे फोन स्क्रीन पर कोई खेल या कार्टून देखते हुए खाना खाने के अभ्यस्त हो गए हैं। कुछ माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे के हाथ में फोन देने से उसका मानसिक विकास तेजी से होगा और वह ज्ञान ग्रहण करने में शीघ्र समर्थ हो सकेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्मार्टफोन तकनीक का उपयोग करने वाले बच्चों से जुड़े जोखिमों को भी पहचानना शुरू कर दिया है। संगठन के प्रारंभिक सुझाव बता रहे हैं कि दो से चार वर्ष के बच्चों को एक दिन में एक घंटा, चार वर्ष से अधिक उम्र वालों को सिर्फ दो घंटे फोन उपयोग करना ही उचित है। एक शोध के अनुसार सात से सोलह साल के अधिकांश बच्चे, जिन्होंने स्मार्टफोन में अधिक समय बिताया था, तिरछी नजर की

त्रुटि के साथ मोटापे के भी शिकार हो गए। देश में मोबाइल फोन में लिप्त बच्चों के तीन सर्वेक्षण सांख्यिकी चौंकाने वाले दृष्टिगोचर हुए हैं। बच्चों में मोटापे की अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। वर्तमान में करीब एक करोड़ पैतालीस लाख बच्चे इसके शिकार हैं जबकि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का कथन है कि 2030 तक 2.8 करोड़ बच्चे (5-17 वर्ष) मोटापे की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। दूसरी चिंताजनक समस्या बच्चों की नींद की है जिसके आंकड़े बता रहे हैं कि 63% किशोर दस घंटे की जगह मात्र 6 घंटे सो रहे हैं। अध्ययन के अनुसार इस कारण मोबाइल फोन इस्तेमाल के साथ पढ़ाई का तनाव, अवसाद और पारिवारिक समस्या भी पाई गई है। इन विकट परिस्थितियों से देश के नौनिहालों को कैसे रास्ते पर लाया जाए, यह भी विचार किया जाना चाहिए। सबसे मुख्य उपाय लग रहा है कि माता-पिता स्वयं मोबाइल फोन का कम से कम उपयोग करें जो बच्चों की दृष्टि से दूर हो। बच्चों को स्कूल समय के बाद आउटडोर गेम में संलग्न करने से उनकी अभिरुचि जागृत होगी जो उनके शारीरिक विकास में सहायक हो सकेगी। अपने हमउम्र के बच्चों के साथ मिलने-जुलने का अवसर मिलेगा जिससे सामाजिक बंधन में बच्चे बंध सकेंगे।

बच्चों को नृत्य, संगीत, गेम्स की ओर भी प्रेरित कर उनके रूटीन को सही दिशा में लाया जा सकता है। सावधानी के रूप में अभिभावक यह जरूर करें कि किसी भी सूरत में बच्चों के मन को बहलाने में फोन उन्हें न दें। फोन की जगह खिलौने या पुस्तक देकर उनकी जिद्द को दूर किया जा सकता है। पहले बच्चों को नानी, दादी रात में सोते समय प्रेरक कहानियां सुनाकर सुलाती थीं, जो अब संभव नहीं है लेकिन बच्चों की प्रकृति और अभिरुचि का अध्ययन करके आधुनिक कथा कहानियों से उनका मन बहलाया जा सकता है। दिन प्रति दिन विज्ञान के हर क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार तीव्र हो रही है। संभव है कि भविष्य में वर्तमान काल के संवाद के अनोखे अंग मोबाइल की जगह किसी विकल्प का आविष्कार हो जाए। विज्ञान ने निर्माण के गुण से संबंधित अधिक से अधिक उपकरणों को जनमानस के हित में प्रस्तुत किया है जबकि हर अनुसंधान के साधन में प्रतिकूल असर भी छिपे हैं। जरूरत है कि मोबाइल फोन के सकारात्मक पक्ष से हम अपने को स्वयं जोड़ते हुए घर के बच्चों को भी समुचित वातावरण मुहैया कराएं ताकि किशोरों के कोमल मन-मस्तिष्क का भटकाव न हो सके। ■

पुस्तक समीक्षा नवोदित

एक पुस्तक ऐसी भी

वरिष्ठ साहित्यकार उदभ्रांत की एक अद्भुत पुस्तक आई है-'हिन्दी की वाचिक परंपरा का समकालीन परिदृश्य'। शायद हिन्दी साहित्य में ऐसी पुस्तक पहले न छपी हो। उदभ्रांत 24 घंटे लिखने वाले, साहित्य में जीने वाले साहित्यकार हैं। डेढ़ सौ पुस्तकों के लेखक हैं। उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। कई शिक्षा संस्थानों में उनकी रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने हर विधा में लिखा है...कहानी, कविता, आलोचना, इंटरव्यू, डायरी, अनुवाद...महाकाव्य, खंडकाव्य। काव्य में भी नवगीत, मुक्त छंद, गजल। इतना ही नहीं, उनकी एक विशेषता और है कि उन्होंने जो लिखा, वह छपा, पुस्तक रूप में भी। उनकी एक पुस्तक तो हरिवंश राय बच्चन से पत्राचार की है तो एक पुस्तक में उनका वह लेखन संकलित है, जो उन्होंने फेसबुक पर लिखा है। उनका लिखा साहित्य पढ़कर पता चलता है कि किस-किस तरह किस-किस विषय पर लिखा जा सकता है।

उनकी पुस्तक 'हिन्दी की वाचिक परंपरा का समकालीन परिदृश्य' में उन वक्तव्यों, संबोधनों अथवा व्याख्यानों को संग्रहीत किया गया है, जो उनकी पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर अथवा इस उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठियों में दिए गए हैं। इनमें देश के सभी ख्यातिप्राप्त लेखक, कवि और आलोचक हैं। आलोचकों में नामवर सिंह, नित्यानंद तिवारी, बलि सिंह, संजीव कुमार, भगवान सिंह, खगेंद्र ठाकुर, कर्ण सिंह चौहान, पुरुषोत्तम अग्रवाल, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश ऋषिकल्प, हरदयाल, अरविंद त्रिपाठी, अजय तिवारी, सुरेश शर्मा, निर्मला जैन, हेमलता महेश्वर, पीएन सिंह, पंकज शर्मा। उपन्यास और कहानीकारों में कमलेश्वर, अमर गोस्वामी, रवींद्र कालिया, नरेंद्र कोहली, राजेन्द्र अवस्थी, प्रदीप पंत, मधुकर गंगवार, विनोद शाही, डाक्टर माहेश्वर, विभूतिनारायण राय। कवियों में अशोक वाजपेयी, कुबेर दत्त, केदारनाथ सिंह। शायरों में जगन्नाथ आजाद, मखमूर सईदी, नोमान शौक वगैरह जैसे 52 लोगों के वक्तव्य हैं। कई के तो कई-कई हैं। सब ने उदभ्रांत के लेखन को साहित्य की विभिन्न कसौटियों पर कसा है।

इस पुस्तक में भी किसी भी पुस्तक के बराबर का श्रम दरकार थी। गोष्ठियों में सबके वक्तव्य रिकॉर्ड करना फिर उनको ट्रांसक्राइब करना, फिर कंपोजिंग और प्रूफरीडिंग, भले ही दूसरे भी सहयोग करते हैं, पर दिमाग तो एक ही का खर्च होता है। बहरहाल, पुस्तक उदभ्रांत के लेखन को समझने में बहुत सहायक है। उनके लिखे को पढ़ने की उत्सुकता जगाती है। जिनके शैक्षिक पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं हैं, वे तो पढ़ेंगे ही, देश के बड़े लेखक को हमें वैसे भी पढ़ना चाहिए। इससे जानकारियां बढ़ती हैं, दिमाग रौशन होता है, बेहतर जिंदगी जीने में कई तरह से यह सहायक होता है, विषम परिस्थितियों में संतोष देता है, और प्रेरित करता है।

पुस्तक : हिन्दी की वाचिक परंपरा का समकालीन परिदृश्य
सम्पादक : उदभ्रांत
प्रकाशक : नमन प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 499/- ■

राग रंग आलोक पराड़कर

परंपरा के कई रंग

परंपरा से आशय अविच्छिन्न क्रम, प्रथा, प्रणाली, चला आता हुआ अटूट सिलसिला का लगाया जाता है। लेकिन यह क्रम तभी आगे बढ़ता है, जब हम उसमें उसी अनुरूप जोड़ते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं। सदा से चले आते हुए भी परंपरागत वह प्रवाह है, जो परंपरा पर अवलंबित होकर भी नया समाहित किए हुए है। पद्मजा कला संस्थान ने 10 अप्रैल को लखनऊ के संत गाडगे जी महाराज सभागार में 'परंपरा 2024' का आयोजन किया तो इसे परंपरा के इन आशयों से जोड़कर भी देखा जा सकता है।

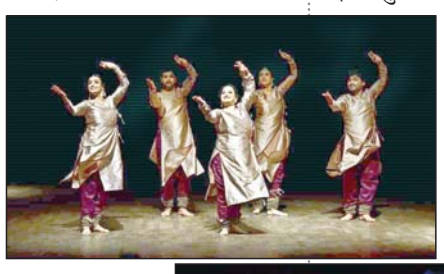

आयोजन के केंद्र में संस्थान की सचिव कथक नृत्यांगना डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव थीं। आकांक्षा नगर के कथक नर्तक और गुरु दिवंगत पंडित अर्जुन मिश्र की शिष्या हैं। पंडित अर्जुन मिश्र ने जहां एकल नृत्य प्रस्तुतियों और नृत्य नाटिकाओं से प्रशंसा अर्जित की वहीं बड़ी संख्या में उनके शिष्य-शिष्याएं भी रहे। वे नियमित तौर पर किसी संगीत संस्थान में नहीं रहे लेकिन व्यक्तिगत रूप में अपनी संस्था बनाकर उन्होंने कई प्रतिभाशाली कलाकार तैयार किए। उनके शिष्य-शिष्याओं में आज कई प्रमुख कथक कलाकार हैं, जो नगर और बाहर अपने कार्यक्रमों से सराहना बटोर रहे हैं। कथक की चीजों को आगे की पीढ़ी को सौंपने की इस परंपरा को उनकी शिष्या आकांक्षा ने भी कुशलता से अपनाया है, और वे भी अपने प्रदर्शनों के साथ ही व्यक्तिगत रूप में नृत्य का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। समारोह में 50 के करीब शिष्य-शिष्याओं का नृत्य प्रस्तुतियों में भाग लेना दर्शाता है कि उनके विद्यार्थियों की कितनी अधिक संख्या है। इनमें चार वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के प्रशिक्षु कलाकार थे। कई अपनी तैयारी से प्रभावित भी करते हैं, और कुछ ने नृत्य आधारित रिएलिटी शो में भाग लेकर लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया है।

समारोह से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी रही कि इसमें हुई नृत्य प्रस्तुतियों में गुरु से मिली शिक्षा के साथ ही कुछ नया सोचने और जोड़ने की ललक भी दिखी जो विभिन्न रूपों और नृत्य संयोजनों में सामने आई। आरंभ 'तालांगी' से हुआ जिसमें सात मात्रा के रूपक, नौ मात्रा के बसंत, 11 मात्रा के अष्टमंगल, 14 मात्रा के धमार और 16 मात्रा के तीन तालों पर आधारित प्रभावपूर्ण नृत्य संरचना देखने को मिली। इसका नृत्य संयोजन देखते ही बन रहा था। एक अन्य नृत्य प्रस्तुति 'तालीम' थी जिसमें चार साल से लेकर 25 साल तक के कथक के विद्यार्थी थे जिन्होंने परंपरागत कथक के साथ ही भजन पर भी नृत्य किया। 'कथक के रंग, माटी के संग' में चैती, कजरी तथा अन्य उपशास्त्रीय रचनाओं पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। 'एही ठैयां मोतिया हेरानी हो रामा...', 'बरसन लागी सावन बुंदिया रामा.. ' जैसी रचनाएं इसमें शामिल थीं। इन प्रस्तुतियों का नृत्य निर्देशन करने वाली आकांक्षा श्रीवास्तव के साथ ही इनमें सिजा राय,अर्पणा शुक्ल, शैली मौर्या, खुशी मौर्या, प्रीति तिवारी, आरोहिणी चौधरी, सिमरन कश्यप, सपना सिंह, श्रद्धा श्रीवास्तव, श्रेया सिंह, मोनिका सरीन, शिवानी, आराध्या दीक्षित, विकास अवस्थी, प्रखर मिश्र, अंश रावत, अतुल माने, आदित्य गुप्त, मोहित सोनी, आयुष अग्रवाल, सुमति मिश्र, मंगला श्रीवास्तव, वैष्णवी सक्सेना, प्रिशा अग्रवाल, श्रेया अग्रहरी, अनामिका यादव, पर्णिका श्रीवास्तव, रितिका, इहारा, अहाना गुप्त, कृतिका गुप्त, स्वरा मिश्र, रिदम गुप्त, देबश्मिता पाल, प्रियांशी गुप्त, आयुषी सिंह, पाखी मिश्र, समृद्धि श्रीवास्तव, इशानी शुक्ल, उन्नयन शुक्ल, वरुनिका गुप्त, रचना, नीतू, आकृति श्रीवास्तव, आकृष्टी जायसवाल, अदिति बसक, मानसी मौर्या, आराध्या अग्रवाल, जाह्नवी पाण्डेय, निलीशा निगम ने प्रतिभाग किया।

सिजा राय के निर्देशन में इस मौके पर कथक और कुछ दूसरी नृत्य शैलियों के मिलाप पर आधारित प्रस्तुति भी हुई जबकि कथक से इतर दो किशोर कलाकारों की प्रस्तुति ने भी मन मोहा। संकल्प मिश्र ने सितार पर 'किरवानी' की प्रस्तुति की जिन्हें उनके पिता सितार वादक नवीन मिश्र और गायिका माता मंजूषा मिश्र ने शिक्षा दी है। तबले पर उनके साथ तबला वादक विकास मिश्र और आकांक्षा श्रीवास्तव के बेटे मनन मिश्र ने संगत की। किशोर कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए विकास मिश्र भी तबले पर थे। वरिष्ठ गायक पंडित धर्मनाथ मिश्र, कथक नृत्यांगना कुमकुम धर, संस्था के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने कलाकारों का सम्मान किया। इस मौके पर नगर के कई प्रमुख कलाकार उपस्थित थे। संचालन राजेंद्र विश्वकर्मा ने किया। ■

कैनवस जय त्रिपाठी

दिक् से दिगंत तक देखना

समकालीन कला में आज भी ऐसे कलाकार हैं, जो अपनी कला के लिए लड़ सकते हैं, उसके मानकों के साथ समझौता नहीं कर सकते। समय के साथ-साथ परिवर्तन उनकी कला का महत्त्वपूर्ण कारक है। समकालीन भारतीय कला के मूर्धन्य कलाकारों में एक स्वामी हुए हैं, जो कला जगत को ऐसी दिशा दिखा गए हैं कि प्रेक्षक उसे सतह से आकाश तक फैले कला-सत्य को बस निहारता रह जाता है। वह वैसे ही कलाकार थे, जो कलाकारों एवं कलानुरागियों को पूरी स्वतंत्रता देते थे कि वह जैसे चाहे उनकी कला का अवलोकन करे। उन्होंने कला को व्यापकता में ग्रहण कर उसको वैचारिक एवं सांस्कृतिक एकता के सूत्र में भी पिरोने का काम किया है। पिछले दिनों एक सार्थक कला चर्चा के दौरान इस अद्भुत कलाकार से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरण ने उनके प्रति मेरी अभिरुचिता को समग्रता में और भी तरोताजा किया। समकालीन कलाकार जगदीश स्वामीनाथन ने एक नई धारा बनकर कला के कूल-किनारे को चुनौती देकर उसमें अनंत संभावनाओं के क्षितिज खोले थे। युवा कलाकारों के चितेरे मन में एक बड़ी हिलोर पैदा की थी।

इन दिनों राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में आयोजित ढेर सारे कला कार्यक्रम व कला प्रदर्शनियां उसी हिलोर की पैदा हुई अनवरत हलचल हैं। इनके माध्यम से आधुनिक समकालीन कला में परंपराओं का पाट-परिदृश्य चौड़ा हुआ है तो उसकी सतहों को ऊंचा उठा कर उनमें एक नवोन्मेष पैदा किया है। यह कला में नवाचारों को एक अभियान की तरह निखार देना है।उसमें नए-नए रंग भरना है। नई दिल्ली की त्रिवेणी कला दीर्घा में गत हफ्ते चित्रकार **जे.पी.सिंह** के अमूर्त संसार को दशति चित्रों की एकल प्रदर्शनी 'बियांड द कॉन्शियसनेश' प्रदर्शित थी। ये अमूर्त चित्र उनकी कलात्मक विधा और कला तत्वों के स्तर पर चित्रों की रचनात्मकता के आंतरिक संकेतों को आत्मसात किए हुए हैं। जेपी ने बिंदु,त्रिकोण आदि के माध्यम से पंचतत्व, पुरुष और प्रकृति जैसे भारतीय दर्शन से अपनी कला अभिव्यक्ति को रचा है। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो यह केवल सामान्य देखना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि हम किसी वस्तु को किस कोण से या किस तरह से देख पाते हैं। जे.पी.सिंह की कृतियों को देखकर देखने का सही विन्यास समझ में आता है-कि किस तरह से देखना सही तरह से देखना कहा जाएगा। कला का मर्म ही यही है कि वह प्रेक्षक-दृष्टि को चित्रों तक लाकर उसके पार दिगंत तक ले जाती है-कला के आयामों को व्यापकता में अवगाहन के लिए। जैसे स्वयं को समझने का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से अमूर्त कला को जानने का भी कोई अंत नहीं है-वह अनंत है। रविन्द्र भवन की ललित कला दीर्घा में भी प्रत्येक सप्ताह सिलसिलेवार नवीन प्रदर्शनियां सुखद हैं। इसी क्रम में 'बियांड इमेजिनेशन-ए क्रिएटिव जर्नी' शीर्षक से कोलकाता के सात कलाकारों **देबनाथ दास, दीपांकर घोष, फारूक अहमद, मनोज बारुई, श्रीरूप सरकार, उत्पल दास, तुषार कांति प्रधान** की समूह प्रदर्शनी देखी। इन कलाकारों के माध्यम जो भी हों, वे उनमें गहरा प्रभाव पैदा करते थे। अपने रचनात्मक कला विस्तार व प्रतिबद्धता को कलात्मकता से रचते दिखाई देते हैं। आकर्षक शिल्पों को रचते फारूक अहमद, धातु आदि का कई तरह से प्रयोग करते हैं। कोकोनट सेल व फाइबर आदि का सतह पर प्रयोग करना उनकी तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। मूर्तिकार फारूक इस पर जितना विचार करते हैं, तकनीकी रूप से भी वे उतना ही समृद्ध दिखते हैं। इनके शिल्प बचपन की यादों,अनुभवों,भावनाओं, समय और अस्तित्व की कहानियां कहते हैं। ललित कला की दीर्घा न. 7 में प्रदर्शित **सुरेश चंद्र जांगिड़** के एकल चित्र पशु-पक्षियों तथा जानवरों पर केंद्रित होकर प्रकृति पर विचार करते हैं। जानवरों के प्रति गहन लगाव को उनकी बौद्धिक संरचना और रचनात्मक सोच में देखा जा सकता है। जो आज के विस्तारित होते युग में आध्यात्मिक चिन्तन-मनन को दर्शाता है। कैनवस में पेपर पर कटी आकृतियों में सधे प्रयोग से बने चित्र सुरेश चंद्र की मानवीय भावना के लिरिकल साक्ष्य हैं। अतः उनकी रचना दर्शकों के मन में एक संवेदनशील उपस्थिति के रूप में दर्ज हो जाती है। छोटे-छोटे चित्रों की श्रृंखला में प्रत्येक रचना अलग-अलग आकारों में होते हुए भी अपने समय की धड़कन हैं। ■

कल्पमेधा

प्रगतिशील समाज संगठनों की उपयोगिता से आगे निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे बच्चों की पोशाकें छोटी पड़ जाती हैं।
- हेनरी जार्ज

इरादे का इजहार

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

सबसे चर्चित मुद्दा है भाजपा का अधिनायकवाद। भाजपा ने संघवाद और इस संवैधानिक घोषणा को कमजोर कर दिया है कि भारत राज्यों का संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सिद्धांत बेहद संदेहास्पद है।

घोषणापत्र आमजन से जुड़े मुद्दों पर इरादों और नजरिए की लिखित घोषणा होता है। इस संबंध में जो कुछ उदाहरण दिमाग में आते हैं, वे हैं- 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की आजादी की घोषणा और 14-15 अगस्त, 1947 को जवाहरलाल नेहरू का 'नियति से साक्षात्कार' भाषण। डा मनमोहन सिंह का 24 जुलाई, 1991 को दिया वह यादगार भाषण, जिसमें उन्होंने विक्टर ह्यूगो को उद्धृत करते हुए कहा था कि 'पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका समय आ गया हो।' उस विचार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। उन बयानों/ भाषणों में पुरजोर तरीके और स्पष्ट रूप से नए शासकों के इरादे का इजहार था।

किसी बयान में उसे जाहिर करने वाले का असली इरादा छिपा भी हो सकता है। झूठे भविष्यवक्ता झूठे बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी के कुछ बयान बार-बार याद आते हैं, 'मैं हर भारतीय के बैंक खाते में पंद्रह लाख रुपए डालूंगा', 'मैं प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा' और 'मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा', आदि। उनके सिपहसालारों ने उन बयानों को चुनावी जुमला कह कर उनका मजाक उड़ाया था।

भारत में राष्ट्रीय उपस्थिति वाले दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने 30 मार्च को अपनी घोषणापत्र समिति का गठन किया, कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। काश, मैं इस स्तंभ में दोनों घोषणापत्रों की तुलना कर पाता, मगर फिलहाल केवल कांग्रेस का घोषणापत्र उपलब्ध है। इसलिए, मैं उन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करूंगा, जिनके आधार पर पाठकों और मतदाताओं को दोनों घोषणापत्रों की तुलना करनी चाहिए।

भारत का संविधान

कांग्रेस ने कहा है कि, 'हम इस बात को दोहराते हैं कि भारत का संविधान हमारी कभी न खत्म होने वाली यात्रा में हमारा एकमात्र मार्गदर्शक और साथी होगा।' लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या भाजपा संविधान का पालन करेगी या इसमें आमूलचूल परिवर्तन करेगी। यह प्रश्न 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', समान नागरिक संहिता; नागरिकता संशोधन अधिनियम (अब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित), और अन्य जैसे अस्थिर करने वाले और विभाजनकारी विचारों की वजह से उठा है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह संविधान में निहित संसदीय लोकतंत्र के 'वेस्टमिंस्टर सिद्धांतों' का पालन करेगी।

समाजार्थिक और जाति जनगणना, आरक्षण

कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उसके नेतृत्व वाली सरकार देशव्यापी समाजार्थिक और जाति जनगणना कराएगी। वह आरक्षण पर पचास फीसद की सीमा हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसद आरक्षण सभी जातियों और समुदायों के लिए खुला रहेगा।

कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी, जो रोजगार और शिक्षा में विविधता का आकलन करेगा और बढ़ावा देगा। भाजपा को अपनी अस्पष्टता छोड़नी चाहिए और इन मामलों में अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट करने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि समानता के बृहद मुद्दे पर दोनों दल कहां खड़े हैं।

अल्पसंख्यक

भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक रहते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसका मानना है कि सभी भारतीय समान रूप से मानवाधिकारों का लाभ पाने के हकदार हैं, जिसमें हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार शामिल है, और यहां बहुसंख्यकवाद या अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बहुलवाद और विविधता भारत के लोकवृत्त की रचना करते हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर 'तुष्टीकरण' का आरोप लगाया है, जो उसके सुपरिचित अल्पसंख्यक विरोधी रुख का एक कूट-शब्द है। क्या भाजपा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने और समान नागरिक संहिता पारित करने के अपने दृढ़ संकल्प को फिर से दोहराएगी? चूंकि धार्मिक अल्पसंख्यक इन दोनों कानूनों को भेदभावपूर्ण मानते हैं, इसलिए वे उत्सुकता से भाजपा के घोषणापत्र का इंतजार कर रहे हैं।

युवा और रोजगार

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश छीज रहा है। इसकी वजह है, संतोषजनक औसत से कम विकास दर (5.9 फीसद), ठहरा हुआ विनिर्माण क्षेत्र (जीडीपी का 14 फीसद), कम श्रमबल भागीदारी दर (50 फीसद) और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी (42 फीसद, स्नातकों के बीच)। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नौकरियों में तीस लाख रिक्तियों को भरने, प्रशिक्षुता का अधिकार अधिनियम पारित करने, कारपोरेट जगत के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआइ) लागू करने का वादा किया है, जो नई नौकरियां पैदा करेगी, और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 'फंड आफ फंड्स' योजना स्थापित करेगी। इनसे जाहिरा तौर पर युवा उत्साहित हैं। भाजपा-एनडीए सरकार के पास युवाओं के लिए नौकरियों की कोई विश्वसनीय योजना नहीं थी। सवाल है कि क्या भाजपा इससे अधिक आकर्षक योजना पेश कर पाएगी।

महिलाएं

चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सबसे उत्साही भागीदार होती हैं। वे प्रचार भाषण सुनती और उस पर आपस में चर्चा करती हैं। वास्तविक साक्ष्यों से पता चलता है कि कांग्रेस की 'महालक्ष्मी योजना' (हर गरीब परिवार को प्रति वर्ष एक लाख रुपए), मनरेगा के तहत 400 रुपए की दैनिक मजदूरी, महिला बैंक का पुनरुद्धार और केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण का वादा महिलाओं और लड़कियों को आकर्षित कर रहा है। क्या भाजपा धर्म (हिंदुत्व) की अपील से आगे बढ़कर ठोस योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आगे आएगी, यह देखने की बात है।

संघवाद

सबसे चर्चित मुद्दा है भाजपा का अधिनायकवाद। भाजपा ने संघवाद और इस संवैधानिक घोषणा को कमजोर कर दिया है कि भारत राज्यों का संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सिद्धांत बेहद संदेहास्पद है। यह एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक सरकार, एक पार्टी और एक नेता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में संघवाद पर एक अध्याय में बारह बिंदु है; क्या भाजपा किसी पर भी सहमत है? सबसे दूरगामी वादा, कानून के कुछ क्षेत्रों को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने पर आम सहमति बनाना है। इन्हीं बारह बिंदुओं पर भाजपा की साख की परख होगी।

जहां तक मेरा सवाल है, सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा चुनाव लड़ने वाले दलों की संविधान, संसदीय लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वतंत्रता और गोपनीयता तथा संवैधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता है। मेरा वोट उस उम्मीदवार को होगा, जो इन सिद्धांतों की शपथ लेगा और इन्हें कायम रखेगा।

सबसे चर्चित मुद्दा है भाजपा का अधिनायकवाद। भाजपा ने संघवाद और इस संवैधानिक घोषणा को कमजोर कर दिया है कि भारत राज्यों का संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सिद्धांत बेहद संदेहास्पद है। यह एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक सरकार, एक पार्टी और एक नेता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में संघवाद पर एक अध्याय में बारह बिंदु हैं; क्या भाजपा किसी पर भी सहमत है?

बदलाव की तस्वीर

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

भाईचारा दुबारा कैसे कायम होगा, कहना मुश्किल है। जो भी जीत कर लोकसभा में आएंगे, उनको गहराई से सोचना होगा। इसके अभाव से फायदा होता है सिर्फ देश के दुश्मनों को। आम मतदाताओं से बातें करने के बाद ऐसा लगा मुझे कि संविधान और लोकतंत्र को लेकर जो चिंताएं दिल्ली और मुंबई के राजनीतिक पंडितों में हैं, आम लोगों में नहीं हैं, लेकिन तनाव-सा जरूर है मुसलिम मतदाताओं में।

फैज अहमद साहब के एक शेर से शुरू करती हूं, उसको थोड़ा बदल के। शेर है 'बहार के आने पे' और बहार की जगह मैं 'चुनाव' डाल रही हूं- 'चुनाव आए तो खुल गए हैं, नए सिरे से हिसाब सारे'। वास्तव में लोकसभा चुनाव जब भी आते हैं, मैं बैठ कर हिसाब करती हूं कि पिछले पांच सालों में अच्छा क्या हुआ है देश के लिए। हमारे-आपके लिए भी। इन दो चीजों के बारे में सोच कर हमको तय करना है कि वोट अबकी बार किसको देना है। हिसाब दिल्ली में बैठ कर नहीं किया जा सकता है। इसलिए करने से पहले मैंने दौरे लगाए राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के। इन दौरों पर मैं राजनेताओं की आम सभाओं में जानबूझ कर नहीं जाती हूं। आज के दौर में सारे राजनेताओं के सारे भाषण टीवी पर देखने को मिलते हैं और आनलाइन भी। मैं जाती हूं यह देखने कि पांच साल पहले यहां हाल क्या देखा था और परिवर्तन के तौर पर क्या हुआ है। मेरी कोशिश यह है कि जो परिवर्तन सामने आया है, उसके बारे में ईमानदारी से लिखूं।

इसलिए आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ की कोई बहुत बड़ी प्रशंसक न कभी पहले थी और न अब हूं, लेकिन पिछले सप्ताह लखनऊ और उसके आसपास कुछ गांवों में घूम कर आई हूं और सबसे ज्यादा परिवर्तन मैंने यहां देखा है। हवाईअड्डा अभी तक वही पुराना-सा है, इसलिए मैंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश भी वही पुराना होगा। यानी गांवों में जाने के लिए गाड़ी को रोक कर पैदल जाना होगा, इसलिए मजबूत जूते पहन कर आई थी। हैरान हुई जब सड़कें इतनी अच्छी देखीं कि गाड़ी भीतर तक जा सकी। हैरान हुई देख कर कि जो सरकारी स्कूल कभी लगभग खंडहर होते थे, अब इतने अच्छे हो गए हैं कि निजी स्कूल जैसे दिखने लगे हैं। लोगों का कहना था कि अब निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि अभी भी 'सीरियस' मामला हो तो लखनऊ जाना पड़ता है, लेकिन निजी अस्पताल काफी खुल गए हैं।

कई गांवों में 'नल से जल' वाली योजना पूरी हो चुकी है और कई जगह पाइपें अभी बिछ रही हैं। लोगों ने कहा कि उनका वोट मोदी-योगी को जाएगा, इसलिए कि उन्होंने 'काम' किया है। एक मुसलिम बस्ती में मेरे मतदान से जुड़े सवालों का जवाब देने से लोग कतराए थे। लेकिन जब पूछा कि उनको गैस चूल्हे, मुफ्त राशन और अन्य समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं तो उन्होंने माना कि ये सारी चीजें उनको मिली हैं।

लखनऊ शहर के पुराने इलाके में गई तो देखा कि जहां इमामबाड़ों के सामने सड़ते कूड़े के ऊंचे ढेर पड़े हुए थे, अब सफाई की गई है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ अब पेरिस या लंदन बन गया है, लेकिन परिवर्तन जरूर आया है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। पुराने शहर को अगर थोड़ा और चमकाया जाए तो पर्यटन से जो कमाई जोधपुर के लोग करते हैं, वैसा लखनऊ के लोग भी कर सकेंगे। यहां यह कहना जरूरी है कि जोधपुर में मैंने उतना परिवर्तन नहीं देखा, जितना लखनऊ में दिखता है। लखनऊ में मैंने एक करीबी रिश्तेदार से जब योगी के बारे में पूछा तो कहा उन्होंने कि जिस रफ्तार से विकास हो रहा है, आज उसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था। कभी पुलिस अफसर हुआ करते थे मेरे चाचा, इसलिए मैंने उनसे कानून-व्यवस्था के बारे में पूछा। जवाब मिला कि पहले पुलिस के हाथ बंधे रहते थे। अब ऐसा नहीं है।

हिसाब जब नुकसानदेह परिवर्तन का किया तो मेरी फेहरिस्त में सबसे ऊपर आया भाईचारा। हिंदुओं और मुसलमानों में अब एक गहरी खाई बन चुकी है, जिसके होते हुए देश का नुकसान ही हो सकता है, लाभ नहीं। हिंदुओं का कहना है कि उनको मुसलमानों से शिकायत यही है कि उनकी नजर में शरीअत सबसे ऊपर है और हिंदुओं की नजरों में संविधान सबसे ऊपर। मुसलमानों की नजर में मंदिर निर्माण और मंदिर-मस्जिदों के विवादों से 'इस्लाम खतरे में है'। ऊपर से जब भाजपाई राजनेता शहरों के नाम बदलते हैं और उर्दू को विदेशी भाषा कहते हैं, उनकी सभ्यता को भी खतरा दिखता है।

भाईचारा दुबारा कैसे कायम होगा, कहना मुश्किल है। जो भी जीत कर लोकसभा में आएंगे, उनको गहराई से सोचना होगा। इसके अभाव से फायदा होता है सिर्फ देश के दुश्मनों को। आम मतदाताओं से बातें करने के बाद ऐसा लगा मुझे कि संविधान और लोकतंत्र को लेकर जो चिंताएं दिल्ली और मुंबई के राजनीतिक पंडितों में हैं, आम लोगों में नहीं हैं, लेकिन तनाव-सा जरूर है मुसलिम मतदाताओं में। मोदी की 'तानाशाही' के बारे में भी मैंने जिक्र तक न सुना। शायद इसलिए कि उनके जीवन में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आपातकाल में जब इंदिरा गांधी ने बुनियादी अधिकार ताक पर रख दिए थे, तो आम मतदाता अच्छी तरह समझ गए थे लोकतंत्र का महत्त्व। फिलहाल उनको नहीं लगता है कि देश में 'अघोषित आपातकाल' की स्थिति बनी हुई है।

वापस दिल्ली जब लौट कर आई तो यूट्यूब पर प्रशांत किशोर का हाल में दिया गया इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम अगर होंगी तो कुछ बीस-तीस ही होंगी। आगे उन्होंने कहा कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या दलों की सरकार तभी बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी की कम से कम सौ सीटें कम होंगी। मैं भविष्यवाणी करने से दूर रहती हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि प्रशांत किशोर की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं।

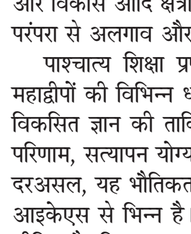

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारतीय ज्ञान परंपरा की कसौटी

शिक्षा

सत्येंद्र किशोर मिश्र

वर्तमान शिक्षा प्रणाली सरकारी बाबू बनाने तक सीमित है, जिसका मकसद छात्र की वास्तविक क्षमता को निखारने के बजाय एक आत्मकेंद्रित, नौकरी चाहने वाले जीविकोपार्जन केंद्रित व्यक्ति का निर्माण करना है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भारत की संस्कृति तथा ज्ञान परंपरा को नजरअंदाज कर भारतीय आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना ही नष्ट कर दी।

प्राचीन भारत में एक ऐसी काल और स्थान निरपेक्ष उन्नत ज्ञान-प्रणाली थी, जो आध्यात्मिकता और दर्शन, बौद्धिकता और तार्किकता तथा विज्ञान और कला के क्षेत्र में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय ज्ञान प्रणाली (आइकेएस) की बुनियाद पर भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की परिवर्तनकारी यात्रा है। वैश्विक स्तर पर तेज बदलाव और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति से भारतीय समाज में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। निस्संदेह भारत ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और विकास आदि क्षेत्रों में कई सीमाएं लांघी हैं, पर भारतीय संस्कृति तथा परंपरा से अलगाव और मूल्यों में गिरावट भी दिखी है।

पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली अनेक प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक महाद्वीपों की विभिन्न धाराओं को समाहित करते हुए आधुनिक यूरोप में विकसित ज्ञान की तार्किकता के साथ जुड़ी है। इसके केंद्र में बौद्धिक परिणाम, सत्यापन योग्यता, अमूर्तता के सामूहिक ज्ञान की अवधारणा है। दरअसल, यह भौतिकता, सांस्कृतिक रूप और यथार्थ विवरण के रूप में आइकेएस से भिन्न है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सरकारी बाबू बनाने तक सीमित है, जिसका मकसद छात्र की वास्तविक क्षमता को निखारने के बजाय एक आत्मकेंद्रित, नौकरी चाहने वाले जीविकोपार्जन केंद्रित व्यक्ति का निर्माण करना है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भारत की संस्कृति तथा ज्ञान परंपरा को नजरंदाज कर भारतीय आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना ही नष्ट कर दी।

आइकेएस में दर्शन, व्यावहारिक शिक्षा, कला, कौशल, शिल्प कौशल, कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान शामिल हैं, जिनके अध्ययन, अनुकूलन और आधुनिक जीवन में एकीकरण से परिवर्तनकारी शुरुआत होगी। इसमें पारंपरिक चिकित्सा, ज्योतिष, योग, ध्यान सहित पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की एक विस्तृत शृंखला शामिल है, जिसकी भारतीय संस्कृति तथा इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके प्रमुख स्तंभों में वैदिक साहित्य है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है। वैदिक साहित्य दार्शनिक शिक्षा, नैतिक सिद्धांत और व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ प्राचीन भारत की गहन समझ और ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सहस्राब्दियों से भारतीय जीवन शैली को आकार देकर साहित्य, कला, संगीत, वास्तुकला और शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता रहा है।

आज योग और ध्यान की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन में भूमिका को वैश्विक मान्यता प्राप्त है। भारतीय षड्दर्शन आत्मचिंतन का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। न्यायदर्शन तर्क और ज्ञानमीमांसा पर केंद्रित है, जबकि वैशेषिक दर्शन परमाणुओं और उनके संयोजनों के विश्लेषण के माध्यम से प्रकृति की वास्तविकता का पता लगाता है। सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन ने गहरी दार्शनिकता की नींव रखी। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में महत्त्वपूर्ण खोज की। सौरमंडल के सूर्यकेंद्रित माडल पर आर्यभट्ट का ज्ञान अपने समय से सदियों आगे था। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और सर्जरी का एक अद्वितीय ग्रंथ है। एनईपी के पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान का एकीकरण है जो न केवल तकनीकी रूप से संपन्न होने, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में नवीनतम प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग पर बल देती है।

एनईपी का लक्ष्य आइकेएस की बुनियाद पर भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है। भारत विश्व में सांस्कृतिक विरासत, जीवन मूल्यों और समृद्ध साहित्य के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए भारतीय और स्थानीय संदर्भ और लोकाचार में दृढ़ता, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएं, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके भी जरूरी हैं। पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा छात्रों के लिए भरोसेमंद, प्रासंगिक और प्रभावी हो, जिससे युवा पीढ़ी भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व कर सकेगी।

आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों- जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानसिक अवसाद- का सामना करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे मानव और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित हो सके। आज भारत को राज्य, आर्थिक दर्शन, सामाजिक संरचना सहित भारतीय संविधान में राष्ट्र-राज्य और राज्यों के संघ की धारणा से लेकर, समानता एवं मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि हेतु प्रासंगिक सिद्धांत निर्माण के लिए आइकेएस आधारित गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

पर, अति उत्साह और आवेग में यह सोचना कि समस्त ज्ञान-विज्ञान आइकेएस के अंतर्गत ही हैं, पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली सर्वथा निरर्थक तथा बेकार है, बौद्धिकता के स्तर पर घातक हो सकता है। निस्संदेह आइकेएस की एक गौरवशाली विरासत है, इसको समझने, खोजने तथा सामायिक तथा राष्ट्रीय संदर्भों में स्थापित करने की जरूरत है, पर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के युग में अन्य वैश्विक ज्ञान परंपराओं को बगैर सही ढंग से सत्यता तथा तार्किकता की कसौटी पर कसे, पूरी तरह से खारिज करना तथा आइकेएस को समग्रता में अपना लेना उचित नहीं होगा। असल चुनौती प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता के संदर्भों में पुनर्व्याख्या करने, समझने तथा व्यवहार में लाने की है।

चुनाव बनाम गारंटियां

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक चैनल की गंभीर-सी बहस में एक पत्रकार ने साफ कहा कि मोदी जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि मेरे साथ चलो। आज वे गारंटी देते हैं। नतीजा कि 2024 की लड़ाई ही नहीं दिखाई पड़ती।

आम आदमी पार्टी के एक सांसद जमानत पर बाहर आए। निराशा में आशा का कुछ संचार हुआ, लेकिन चैनलों ने यह बताकर सारे उत्साह पर पानी फेर दिया कि जमानत 'सशर्त' है, मुकदमा चलना है। फिर आया हाइकोर्ट का मुख्यमंत्री की अपील पर फैसला। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज कहते हैं कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री की भूमिका दिखती है... अदालत राजनीतिक स्थिति देख फैसला नहीं देती... और बचा-खुचा उत्साह भी ठंडा हो गया। इसके आगे 'सुप्रीम कोर्ट शरणम् गच्छामि' होना था, सो हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखेंगे... जल्दी क्या है..! पहले कहते थे कि हम जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन अब कह रहे हैं कि तिहाड़ 'गैस चेंबर' है। यह कैसा गजब का 'गैस चैंबर' है कि मुख्यमंत्री का वजन 'एक किलो बढ़ा' बताया जाने लगा!

फिर आया चैनलों पर महाराष्ट्र के कांग्रेस से निष्कासित किए गए नेता संजय निरुपम का 'उवाच' कि कांग्रेस में 'पांच पावर सेंटर' हैं। गांधीजी की धर्मनिरपेक्षता धर्मविरोधी नहीं थी, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता में धर्म का विरोध है, राहुल गांधी के आसपास ज्यादातर वामपंथी हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। रामलला के कार्यक्रम में सब बुलाए गए थे, उसके जवाब में सारे उत्सव को ही निशाना बनाया गया... राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया गया... कांग्रेस वैचारिक आधार पर दिशाहीन हो गई है। जब मैंने शिवसेना पर हमला करने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला तो मुझे निकाल दिया गया... कब कौन निकाल दिया जाएगा, नहीं मालूम... कहां से लाते हैं ये ऐसे अंहकार..!

देर तक चैनलों में 'संजय उवाच' छाया रहा। तिस पर यह कि उसी शाम कांग्रेस के एक प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। यहां भी सनातन का 'दर्द' था। गौरव बोले कि न मैं सनातन के विरोध में बोल सकता था, न 'वेल्थ क्रिएटर्स' के खिलाफ बोलना चाहता था, इसलिए छोड़ दी।

फिर आया कांग्रेस का 'पांच गारंटी' और 'पच्चीस वादे' वाला 'न्याय पत्र' और चैनल कराने लगे चर्चा पर चर्चा। इसी बीच राहुल भैया ने एक रैली में ऐसा 'खटाखट' किया कि सब खटाखट करने लगे। एक रैली में बोले कि हर युवक को साढ़े आठ हजार रुपए महीने और गरीबी रेखा से नीचे की महिला को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे, जो 'खटाखट खटाखट' उनके खाते में डाले जाएंगे। 'खटाखट' शब्द पर उनको तुरंत तालियां मिलीं। भाजपा प्रवक्ता कहिन कि ऐसे ही दिए तो तिजोरी खाली हो जाएगी।

फिर एक शाम खबर आई कि वायनाड के मतदान के बाद ही अमेठी, रायबरेली सीटों पर कांग्रेसी उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। निंदक आनंदित कि क्या वायनाड की सीट भी पक्की नहीं? इसे देख मानो वाड्रा भैया ने तसल्ली दी कि अमेठी चाहती है कि गांधी परिवार का कोई लड़े।

बहरहाल, तमिलनाडु के युवा भाजपा नेता अन्नामलाई उर्फ 'सिंघम' के साथ मोदी के एक के बाद एक कई रोड शो में आती भीड़ मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती रही और दो सर्वे भी कहते रहे कि इस बार तमिलनाडु से भाजपा दो से चार सीट तक निकाल सकती है और केरल में भी खाता खोल सकती है।

इसी बीच दिल्ली सरकार के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने 'आप' और सरकार से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि 'पार्टी के भ्रष्टाचार' से आजिज आकर उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन वे किसी पार्टी में नहीं जा रहे। 'आप' प्रवक्ता कहिन कि ये 'डराने' और 'तोड़ने' की साजिश है। फिर गुरुवार की रात को एक चैनल ने 'सोशल मीडिया' के हवाले से यह खबर तक चला दी कि आप के कई नेता ऐसे ही ऊहापोह में हैं। भई! बिना प्रमाण के ऐसे 'सुर्रे' छोड़ना भी कोई 'खबरनबीसी' है क्या?

एक चैनल की गंभीर-सी बहस में एक पत्रकार ने साफ कहा कि मोदी जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि मेरे साथ चलो। आज वे गारंटी देते हैं। नतीजा कि 2024 की लड़ाई ही नहीं दिखाई पड़ती। लोकतंत्र में मेहनत से जीता जाता है। एक चुनाव विश्लेषक कहे कि विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है किसी बड़े मुद्दे का न होना। मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा 'मोदी की गारंटी' है। अन्य चर्चा में एक पत्रकार ने बताया कि एक बैठक में जब राम मंदिर दर्शन करके एक सज्जन आए तो बाकी के लोगों ने उसके 'चरण स्पर्श' किए। दूसरे पत्रकार ने बताया कि पश्चिमी यूपी में जब उसने नौजवानों से 'महंगाई' और 'बेरोजगारी' के बारे में कहा तो वे बोले कि वह सब देख लेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। मोदी की 'गारंटियां' इतनी लोकप्रिय हुई हैं कि नकल में विपक्ष को भी 'गारंटी' की बात करनी पड़ रही है।

'विज्ञापन युद्ध' भी शुरू है। कांग्रेस के विज्ञापन 'महंगाई और बेरोजगारी' की शिकायत करते हैं कि 'मेरे विकास का दो हिसाब', जबकि मोदी के विज्ञापन उनकी योजनाओं के लाभार्थियों से कहलवाते हैं कि जो विकास हुआ है, वह तो अभी 'ट्रेलर' है... मोदी की गारंटी हमारा विकास है, तो हमारी गारंटी भी मोदी को जिताना है..!

राजनीति का अपराधीकरण विकास में सबसे बड़ा बैरियर: मुख्यमंत्री

● विपक्ष पर मढ़ा आरोप माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले सुरक्षा नहीं दे सकते

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/बिजनौर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना विकास में सबसे बड़ा बैरक है। 1980 में मुरादाबाद में भयंकर दंगा हुआ था। दर्जनों लोग मारे गए थे। लोगों ने उस समय से 2017 तक रिपोर्ट दबाकर रखी थी। मैंने इसकी जांच शुरू कराई तो दंगा कराने वालों के चेहरे उजागर हो गए। निर्दोष व्यापारी, हिंदू, सिख मारे गए थे पर कोई पूछने वाला नहीं था। 2016 में सहारनपुर में भी सिख विरोधी दंगा हुआ था पर दंगाई आज जान की भीख मांगते हुए छिपे-छिपे फिर रहे हैं। भाजपा ने विकास व सुशासन का

सीएम योगी ने मुरादाबाद से भाजपा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह के पक्ष में की जनसभा

मॉडल दिया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यहां सब चंगा है। कर्फ्यू का स्थान अब कांवड़ यात्रा ने ले लिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के पक्ष में जनसभा कर उन्हें चुनाव जिताने की अपील की। सीएम योगी ने मुरादाबादवासियों से मोदी को भी तीसरा कार्यकाल देने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस, सपा व बसपा के एजेंडे में विकास व गरीब कल्याण नहीं था। आस्था से खिलवाड़ करना यह जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। अपराधी व माफिया को गले का हार बनाकर जनता, बेटी-व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। भाजपा की सरकार जो कहती है, करके दिखाती है। अब माफिया-अपराधी जेल में हैं या जहन्नुम में। किसी बेटी-व्यापारी को धमकी देने की कोशिश अब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे परिणाम मालूम है। यह सुरक्षा भाजपा ही दे सकती है। वे लोग यह सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, जो माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। बड़े-बड़े माफिया जिनकी कभी तूती बोलती थी, आज वे घिघियाते हैं। उनकी हालत देख रहे हैं। कहते हैं कि जान बख्श हो, ठेली पर सब्जी लगाकर पेट भर लेंगे, लेकिन किसी की जमीन पर कब्जा नही करेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति इसलिए सुरक्षित है, क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली और लखनऊ में बैठी है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है, जब बुरा निर्णय लेते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सपा का सांसद कहता था कि मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा। हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे, जो हिंदू समाज को अच्छा लगे पर मैं बता देना चाहता हूं कि भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है।

रामलला की जमीन हो या गरीब की कोई कब्जा नहीं कर पाएगा: योगी

● कहा, सुरक्षा में सेंध लगाने वाला जेल बाद में जाएगा, पहले तैयार हैं जहन्नुम के रास्ते

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/बरेली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलला की भूमि हो या किसी गरीब-व्यापारी और सामान्य नागरिक की जमीन। जो भी भूमाफिया सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करेगा। उसे लेने के देने पड़ेंगे। उससे ब्याज सहित वसूली होगी। उनकी संपत्तियों पर गरीबों के लिए वैसे ही आवास बनाएंगे, जैसे प्रयागराज में बनाया था। जब एक जैसी सरकारें होती हैं, अच्छे लोग चुनकर जाते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। आपने कमल को वोट दिया तो विकास और सुरक्षा भी हो रही है। हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया है। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व प्रदेश सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद व बरेली से भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल सिंह गंगवार के पक्ष में जनसभा कर उन्हें चुनाव जिताने की अपील की। सीएम ने बैसाखी की बधाई दी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वंचित कर दिया था पर अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थीं।

अपराधियों, माफिया व दंगाइयों की फैक्ट्री है सपा: केशव मौर्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधियों, माफिया , दंगाईयों की फैक्ट्री है। सपा की सरकार के समय प्रसिद्ध नारा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। हर सपाई का था नारा, खाली मकान-प्लॉट हमारा। अखिलेश यादव की सरकार के समय प्रदेश का हर जिला अपराध से पीड़ित था और दंगों की आग में झुलस रहा था। अपराधियों की रहनुमाई के कारण सपा अब सफा हो गई। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के विरोधी हैं। इनका पीडीए परिवार डिवेलप्मेंट अथॉरिटी है। इंडी गठबंधन के सभी नेता एक दूसरे के परिवारों का ही हित साधने में ही बिजी हैं। इनकी सरकार में सर्वाधिक उत्पीड़न पिछड़ों, दलितों का ही हुआ है।

मौर्य ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रदेश में पिछले सात सालो में एक भी दंगा नही हुआ। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही हो रही है। सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प, भयमुक्त वातावरण तथा विकास की ओर तेजी से बढ़ते देश में जनता स्वयं मोदी बनकर चुनाव लड़ रही है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रभु श्रीरामलला वर्षो की लम्बी प्रतीक्षा के बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए और कई पीढियों की अभिलाषा पूर्ण हुई। रामभक्तों पर गोली चलाने वाला रामद्रोही परिवार को भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा का निमत्रंण भेजा, लेकिन उस निमत्रंण को ठुकराने का काम सपा व कांग्रेस ने किया। जिन्होंने राममंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है उनको रामभक्त ठुकरा देगे। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं है बल्कि राष्ट्र मंदिर है। उन्होंने कहा कि सारे विधायकों के साथ सपा के बहुत से विधायक भी श्री रामलला के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन सपा बहादुर अखिलेश यादव ने अपने दल के विधायको को श्रीरामलला के दर्शन करने से रोक दिया और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह व्याप्त हुआ और अंतरआत्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों ने मतदान भी किया। मौर्य ने कहा कि सपा भ्रष्टाचार की जननी है। सपा गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी है। सपा मुखिया का मनोबल टूट चुका है। समाजवादी पार्टी बिखर चुकी है। सपा, बसपा व कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अखिलेश यादव का अपराधियों व भ्रष्टाचारियों से पुराना नाता है। भ्रष्टाचार व अपराध इंडी गठबंधन के पर्याय हो गए है। उत्तर प्रदेश की चुस्त-दुरूस्त कानून व्यवस्था, विकासपरक योजनाओं से जनता को लाभ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति से चारों दिशाओं में भाजपा की आंधी चल रही है। जिससे भाजपा को सफलता मिलेगी और अबकी बार 400 पार का लक्ष्य पूर्ण होगा।

भाजपा यूपी की सभी सीटें हारेगी: अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/बिजनौर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को नगीना में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दीपक सैनी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया। अखिलेश यादव ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा सरकार जनता के अधिकारों को छीन रही है। ये संविधान खत्म करना चाहते है। भाजपा संविधान की भक्षक है। लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। सत्ता में बैठे लोग पता नहीं कहां से ऐसी भाषा सीख कर आये है। संविधान की शपथ लेकर बड़े पदों पर बैठे भाजपा नेताओं की भाषा डराने वाली है। भाजपा के नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे है वह संविधान की शपथ लेने वाले नेताओं की नहीं है। बड़े पदों पर बैठने

वालों की भाषा और व्यवहार विनम्र होना चाहिए तभी हमारा संविधान और लोकतंत्र बचेगा। 2024 लोकसभा चुनाव विशेष परिस्थितियों का चुनाव है। एक तरफ संविधान बचाने वाले समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग है तो दूसरी तरफ संविधान को कमजोर करने वाली भाजपा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में परिवर्तन की हवा चल रही है। समाजवादी पार्टी में पीडीए परिवार भाजपा के एनडीए को हराने जा रहा है। भाजपा यूपी की सभी सीटें हारेगी। भाजपा देश में चार सौ सीटें हारने जा रही है। हार के डर से भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकारी संस्थाओं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का अपने लिए प्रयोग कर रही है। भाजपा हार रही है इसलिए विरोधियों को संस्थाओं के जरिए डरा रही है। दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। झारखण्ड के मुख्यमंत्री रहे हेमन्त सोरेन को जेल भेज दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों, नौजवानों सभी को धोखा दिया है। भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानून लायी थी। काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन में लगभग एक हजार किसानों की जान चली गयी। आज किसानों की फसलों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। भाजपा ने वादा करके भी किसानों को एमएसपी की गारन्टी नहीं दी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। भाजपा ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी। भाजपा सरकार में हर पेपर लीक हो जाता है। भाजपा जानबूझकर पेपर लीक कराती है। लीक करने वाले भाजपाई है। भाजपा सरकार की नीयत नौजवानों को नौकरी देने की नहीं है। आज नौजवान और किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नौजवानों, किसानों में भाजपा को लेकर भारी आक्रोश है। किसान, नौजवान लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दस साल में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गयी है। सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। भाजपा ने हर जगह लूट मचा रखी है। नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बांड तक हर जगह भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बांड के नाम पर वसूली की। सरकारी संस्थाओं से छापे डलवाकर और डराकर उद्योगपतियों और कम्पनियों से वसूली की। देश के इतिहास में पहली बार ऐसी वसूली हुई। जिन कम्पनियों की कोई कमाई नहीं उनसे भी चंदा वसूल लिया। वैक्सीन बनाने वाली कम्पनी से भी चंदा वसूल लिया। जिन कम्पनियों ने चंदा वसूला उन्होंने दवाओं, खाने पीने की चीजों समेत सभी के दाम बढ़ा दिया। भाजपा ने चंदा वसूली के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया। भाजपा की वसूली से महंगाई बहुत बढ़ गयी।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता चुनाव में तमाम तरह की बातें करेंगे लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की आय, किसानों की फसलों के लिए एमएसपी पर कुछ नहीं बोलते हैं।

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जनविरोधी: मायावती

● बसपा सुप्रीमो ने हरिद्वार जिले के रुड़की में जनसभा को संबोधित किया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ हरिद्वार

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जनविरोधी हैं। धर्म की आड़ में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया। सरकार पांच किलो मुफ्त राशन देकर गरीबों के साथ मजाक कर रही है। गरीब को राशन के साथ-साथ रोजगार चाहिए।

शनिवार को हरिद्वार जिले के रुड़की (लिब्बरहेड़ी) में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुपीमो ने बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अल्पसंख्यकों के साथ छलावा किया है। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर बराबर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही दलों ने जातिवादी मानसिकता के साथ काम किया है। इन्होंने लोगों का विकास नहीं किया बल्कि केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। उन्होने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। फ्री और फेयर चुनाव हुए तो भाजपा का दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटना आसान नहीं होगा। देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आदि से जनता त्रस्त है।धर्म के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। केंद्र की गलत नीतियों और कार्य प्रणाली को लोग आजमा चुके हैं। साम-दाम-दण्ड-भेद हर हथकंडा अपनाकर राजनीतिक दल सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि विरोधी दलों के वादों और घोषणा पत्र के झांसे में नहीं आना है। बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती केवल कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना है। बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पार्टी बसपा को ही वोट देना है। बसपा सरकार में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। कहना था कि बीएसपी प्रत्याशियों को मतदाता वोट की राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे। मायावती ने कहा कि उत्तराखंड में प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं जमीन खिसक रही है तो कहीं पहाड़। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड यूपी में हुआ करता था और उनकी सरकार थी तो यहां के लोगों को मुलभूत सुविधाएं दी जाती थी। एक व्यवस्थित ढंग से पहाड़ों का विकास किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में बसपा की चार बार सरकार रही है।

विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं: धर्मपाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/अलीगढ़

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने शनिवार को अलीगढ़ में ब्रज क्षेत्र के लोकसभा प्रवासियों, विधानसभा प्रभारी व संयोजको के साथ चुनाव प्रबंधन पर मंत्रणा की। प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वह सभी संकल्प पूर्ण हो रहे है, जिन संकल्पों के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनें थे। वैभवशाली राष्ट्र निर्माण का स्वप्न साकार रूप ले रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूर्ण करने के लिए तीसरी बार नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हमें अपनी समग्र शक्ति के साथ प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए जुटना होगा। जिसको जो दायित्व मिला है, उस दायित्व को सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास हम सभी को करना है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। इसलिए झूठ, छल, प्रपंच से चुनाव को प्रभावित करने का

प्रयास करेगा। हमें सावधानी से विपक्ष के हर षडयंत्र को समाप्त करना है।

उन्होंने कहा कि जनसभाएं, रैलियां, नुक्कड सभाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन सहित जनसम्पर्क के माध्यम से बार-बार और हर बार अबकी बार 400 पार का संदेश लेकर जनता के बीच पहुंचना है। बूथ समिति की मजबूत संरचना तथा सक्रियता संगठन की रणनीति को माइक्रोलेबल पर प्रभावी बनाती है। यही कारण है कि भाजपा का बूथ से लेकर केन्द्रीय स्तर तक का प्रत्येक पदाधिकारी पन्ना प्रमुख के रूप में बूथ समिति का सदस्य है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष अभी प्रत्याशी चयन तथा प्रत्याशी परिवर्तन के दौर में है। जबकि भाजपा के परिश्रमी कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों व अभियानों के माध्यम से घर-घर तक संवाद कायम किये हुए है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए मतदान पूर्ण होने तक अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहे। कल 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयन्ती को समरसता दिवस के रूप में मनाना है।

कांग्रेस ही दे सकती है देश में लोकतंत्र की मजबूती की गारंटी: अविनाश पांडेय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/सहारनपुर

लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने निकले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा कदीम एवं सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के अंबाला रोड पर दो जलसों को संबोधित किया।

राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पाण्डेय ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए चुनाव प्रचार में जलसों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हार और जीत का चुनाव नहीं है, वास्तव में यह चुनाव सत्य-असत्य का है। अविनाश पांडे ने कहा कि 2014 से पूर्व की गारंटिया, जिसमें प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख, 2022 तक किसनों की दुगनी आय व सबके लिए आवास आदि के जो वायदे मोदी जी ने किये थे और जिन्हें अमित शाह जी ने बाद में चुनावी जुमलो का नाम दिया, उन झूठी गारंटियों का मुकाबला कांग्रेस के 5 न्याय व 25 गारंटियों से है, जिनमें से कई गारंटियां तो पहले ही कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है और आज सच्चाई के रूप में जनता के सामने है।

विकसित यूपी की छवि प्रस्तुत कर बीजेपी मतदाताओं को कर रही आकर्षित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आम चुनाव 2024 की चुनावी जनसभाओं में इस बार उत्तर प्रदेश का जिक्र 'विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश' के रूप में हो रहा है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अपनी जनसभाओं में विकसित उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। इसके माध्यम से प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुए बड़े बदलावों के विषय में जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि विगत 7 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अवस्थापना सुविधाओं में जो आमूलचूल कार्य किए हैं, उससे प्रदेश का माहौल बदला है। अच्छी कनेक्टिविटी से प्रभावित होकर देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर रहा है। लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इसी विकास और बदलाव को आगे भी जारी रखने के

लिए इस बार 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जानकारों की मानें तो इस लक्ष्य को प्रदेश की जनता का भी समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर इन चुनावों में यह नारा गेमचेंजर बनेगा, इसकी पूरी संभावना है। हर चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आम चुनाव 2024 भी इससे अलग नहीं है। ये वो मुद्दा है, जिस पर भाजपा को अपनी विपक्षी पार्टियों पर भारी बढ़त हासिल है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी ने विगत सात वर्ष में यूपी में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरान प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना सुविधाओं और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे संचालित हो रहे हैं, जबकि 7 निर्माणाधीन हैं। इस तरह देश के कुल एक्सप्रेसवे कवर क्षेत्र में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से ज्यादा की हो गई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य भी है। यहां 4 अंतर्राष्ट्रीय और 11 घरेलू एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, जबकि 6 निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, देश में घोषित दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। इसमें 6 नोड (अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट) को चिन्हित किया गया है। लखनऊ नोड में ब्रम्होस तथा झांसी नोड में भारत डायनामिक्स की इकाइयां स्थापित हो रही हैं। कानपुर नोड में अडाणी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीस लि. की परियोजना क्रियान्वित हो रही है। इसके साथ ही, 10 केंद्र पोषित व 7 राज्य पोषित कुल 17 नगरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में औद्योगिक शहर बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। यूपी की कनेक्टिविटी सिर्फ हाईवे और एयरपोर्ट के माध्यम से ही नहीं बल्कि मेट्रो और जलमार्ग से भी संभव हो पा रही है। प्रदेश में 4 शहरों (गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, कानपुर, आगरा) में मेट्रो दौड़ रही है तो काशी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी एवं बरेली में मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही, लखनऊ में दूसरे चरण के तहत मेट्रो के विस्तार की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत हो चुकी है जो देश की पहली रीजनल रेल सेवा भी है। वाराणसी में रोप-वे परियोजना पर भी कार्य हो रहा है। इसके साथ ही जलमार्ग की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 विजन के अंतर्गत प्रयागराज को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है, जबकि हल्दिया-वाराणसी पथ तथा वाराणसी में गंगा नदी पर मल्टी मोडल टर्मिनल संचालित किया जा रहा है।

चुनाव में सक्रियता से कार्य कर रहीं हैं प्रवर्तन एजेन्सियां

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियां काफी सक्रियता से काम कर रही हैं। इनके द्वारा 1 मार्च से 12 अप्रैल, 2024 तक कुल 14367.38 लाख रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किए गए। इसमें 2393.09 लाख रुपए नकद धनराशि, 3480.68 लाख रुपये कीमत की शराब, 5361.92 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 1981.05 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1150.62 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 12 अप्रैल, 2024 को कुल 278.66 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 16.94 लाख रुपये नकद धनराशि, 67.26 लाख रुपये कीमत की 22912.60 लीटर शराब, 70.67 लाख रुपये कीमत की 44833.90 ग्राम ड्रग, 103.12 लाख रुपये कीमत की 1449.65 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 20.66 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। 12 अप्रैल, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 12.50 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 250 ग्राम ड्रग तथा जनपद मिर्जापुर की मिर्जापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 12.50 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 65 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी। जनपद बांदा की बांदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 55.45 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 792.09 ग्राम बहुमूल्य धातु एवं 10.09 लाख रुपये नकद तथा जनपद गोरखपुर की गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 47.67 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 657.56 ग्राम बहुमूल्य धातु पकड़ी गयी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

मायावती की राजनीति का रंग

अब लोकसभा चुनाव का जुनून हर एक राजनीतिक दल के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। भारत की राजनीति को अगर हम वर्तमान संदर्भ में रखकर देखें तो एक बात स्पष्ट निकल कर आती है कि 1989-90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश में जातिगत राजनीति का जुनून भी सिर चढ़कर बोला। विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में भी उत्तर प्रदेश में इस राजनीति का इस कदर बोलबाला रहा कि भारत के मतदाता नागरिक जातिगत आधार पर बुरी तरह बंट गए। राजनीतिक पटल पर 1984 में स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ जातिगत राजनीति भी धीरे-धीरे शबाब पर आने लगी। काशीराम के साथ जब मायावती आईं तो उन्होंने इस राजनीति को और तीखा बनाने का प्रयास किया और हिंदू समाज में दलितों को अलग से पहचान देकर अपनी बहुजन समाज पार्टी की पहचान को उनके साथ जोड़ा। दूसरी तरफ इसी राज्य में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम मतदाताओं के साथ यही संबंध स्थापित किया। इससे सबसे बड़ा नुक्सान उस समय तक राजनीतिक शिखर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी को हुआ।

असल में यह और कुछ नहीं था बल्कि 1963 में स्वर्गीय आचार्य कृपलानी द्वारा कांग्रेस को निपटाए जाने का वह फार्मूला था जो उन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश के अमरोहा चुनाव क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव लड़ते हुए दिया था। आचार्य भारत के स्वतंत्रता के वर्ष 1947 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और उसके बाद उसका आचार्य नरेंद्र देव की प्रजा समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। 1963 में जब आचार्य अमरोहा संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ रहे थे तो उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में इसके नेता स्वर्गीय हाफिज मोहम्मद इब्राहिम प्रत्याशी थे। तब आचार्य ने अपनी एक चुनावी सभा में यह वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस को समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय कांग्रेस का चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। आचार्य ने चुटकी लेते हुए कहा था कि कांग्रेस के दो बैल हैं एक मुसलमान और दूसरे दलित। इन दोनों को अगर जुए से खोल दो तो कांग्रेस खुद ही मर जाएगी। यह तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने आचार्य जी के इस फार्मूले पर जानबूझकर अमल किया परंतु यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 1989-90 में बनी राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसा ही माहौल बना दिया।

> राजनीतिक पटल पर 1984 में स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ जातिगत राजनीति भी धीरे-धीरे शबाब पर आने लगी। काशीराम के साथ जब मायावती आईं तो उन्होंने इस राजनीति को और तीखा बनाने का प्रयास किया और हिंदू समाज में दलितों को अलग से पहचान देकर अपनी बहुजन समाज पार्टी की पहचान को उनके साथ जोड़ा। दूसरी तरफ इसी राज्य में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम मतदाताओं के साथ यही संबंध स्थापित किया। इससे सबसे बड़ा नुक्सान उस समय तक राजनीतिक शिखर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी को हुआ। असल में यह और कुछ नहीं था बल्कि 1963 में स्वर्गीय आचार्य कृपलानी द्वारा कांग्रेस को निपटाए जाने का वह फार्मूला था जो उन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश के अमरोहा चुनाव क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव लड़ते हुए दिया था।

दूसरी तरफ भारतीय जन संघ अपने जन्म से लेकर ही उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नौका पर सवार था। 1989 में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के उग्र हो जाने पर जो परिस्थितियां बनी उनमें एक तरफ जनसंघ या भाजपा हो गई और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी व मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो गई। कांग्रेस के लिए तब स्थान पूरी तरह सिमट गया जो आज हमें प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी पार्टी के अभी तक 45 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इन्हें लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में इसलिए चर्चा है कि मायावती ना तो भाजपा नीत एनडीए में है और ना ही विपक्ष नीत इंडिया गठबंधन में है। इसलिए कहा जा रहा है कि मायावती के प्रत्याशी इन दोनों ही गठबंधनों को नुक्सान पहुंचाएंगे। चुंकी मायावती जातिगत राजनीति की प्रतीक है इसलिए उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशी भी राज्य के जातिगत समीकरण को नई दिशा दे सकते हैं जिसका नुक्सान किस सीट पर किस गठबंधन को होगा नहीं कहा जा सकता और किसे लाभ होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तब से लेकर आज तक इस पार्टी का जिक्र जातिगत गुणा गणित के आधार पर ही किया जाता है। वैसे गौर से देखा जाए तो चुनाव का यह नजरिया संविधान विरोधी है क्योंकि चुनाव के लिए बने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर चुनाव नहीं लड़ सकता। उसे केवल नागरिक आधार पर ही चुनाव लड़ने की इजाजत है। मगर हम देखते हैं कि चुनाव के आते ही मतदाताओं को राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति को दुखद कहा जा सकता है परंतु यह सारा मामला चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है।

सवाल यह है कि चुनाव आयोग 1989 के बाद से इस तरफ से आंखें बंद किए क्यों पड़ा है जिसका लाभ सभी राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से उठाते रहे हैं। 2024 के चुनाव असाधारण चुनाव बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन चुनावों में भारतीय संविधान का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस विमर्श की अपनी-अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है तो वह इस तरफ से बेपरवाह दिखती है और उसके द्वारा उतारे गए 45 प्रत्याशी इस बात के गवाह हैं कि उनके सामने सिर्फ उनके चुनाव क्षेत्र का जातिगत गुणा गणित है। अब यह मतदाताओं को देखना है कि वे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को क्या केवल वोट काटु प्रत्याशी मानते हैं या उनमें विजय की संभावनाएं देखते हैं। मुलायम सिंह के बाद उनकी विरासत उनके पुत्र अखिलेश यादव के हाथ में आ जाने के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन तो आया है और यह परिवर्तन इसलिए भी है क्योंकि उनकी पार्टी का कांग्रेस से समझौता है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह समझौता जातिगत समीकरणों को तोड़ते हुए किस प्रकार नागरिक समीकरणों को जोड़ पाता है क्योंकि हमारा संविधान यह बताता है कि चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की बल्कि केवल एक नागरिक की होती है। स्वतंत्र भारत का चुनावी इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भारत के आम मतदाता नागरिक स्तर पर अपना गठबंधन बनाते हैं तो वह बड़े से बड़े राजनीतिक दल के होश भी उड़ा सकते हैं। 1971-1977-1989-2004 और 2014 के चुनाव इसी तथ्य के गवाह हैं। इसकी वजह यह है कि अंत में मतदाता ही लोकतंत्र का मालिक होता है। अत: मायावती की राजनीति चाहे जो कुछ भी हो मगर वह लोक मूलक राजनीति न होकर जाति मूलक राजनीति कही जा सकती है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

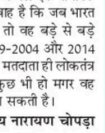

शायद यह चुनावी मौसम का...

स्कूल, कालेज और मोहल्ले की हर दीवार पर इश्तिहार है,
शायद यह चुनावी मौसम का बुखार है,
अब खबरों से ज्यादा न्यूज चैनलों पर किसी दल का प्रचार है,
और जहां देखो वहीं चुनावी रैलियों की भरमार है...!!

गीता पाढा

मोदी फिर आए तो कई मंत्रालय एक होंगे

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'सुबह आंख खुली तो चेहरे पर बिखरी थी एक मखमली धूप जिसने अपने चेहरे पर मल रखा था सुलगती रातों के अवशेष'

400 पार के उद्घोष के साथ नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में हैं। देश का चुनावी मिज़ाज भले ही किंचित बदला सा नज़र आ रहा हो पर मोदी को अपनी सत्ता की 'हैट्रिक' का पक्का भरोसा है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो मोदी ने आगामी जून में गठित होने वाले अपने नए मंत्रिमंडल के चेहरे-मोहरे पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्र यह भी खुलासा करते हैं कि केंद्र सरकार के कम से कम 10 मौजूदा मंत्रालयों का विलय हो सकता है। मसलन, इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री और कॉमर्स को मिला कर एक मंत्रालय बनाया जा सकता है।

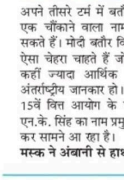

स्किल डेवलपमेंट को मानव संसाधन मंत्रालय का हिस्सा बनाया जा सकता है। रेल, सड़क परिवहन और एविएशन को मिला कर एक बड़ा मंत्रालय बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक जैसे मंत्रालयों पर तो पहले से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इनका अस्तित्व भी नेस्तनाबूद हो सकता है। हां, एक बड़ा खुलासा और। मोदी अपने तीसरे टर्म में बतौर वित्त मंत्री एक चौंकाने वाला नाम सामने ला सकते हैं। मोदी बतौर वित्त मंत्री एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो राजनेता से कहीं ज्यादा आर्थिक मामलों का अंतर्राष्ट्रीय जानकार हो। इस कड़ी में 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एन.के. सिंह का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहा है।

मस्क ने अंबानी से हाथ मिलाया

इस बात का खासा शोर है शराबा है कि 'टेस्ला और एक्स' कंपनी के मालिक एलॉन मस्क पीएम मोदी से मिलने इसी महीने भारत आ रहे हैं। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि इस दफे मस्क को भारत लाने में देश के चुनिंदा उद्योगपति मुकेश अंबानी की एक महती भूमिका है। इस बात की भी चर्चा है कि भारत में 'ईवी' गाड़ियां बनाने के लिए टेस्ला और रिलायंस के बीच एक 'जेवी' हो सकता है। हालांकि मस्क टेस्ला की गाड़ियों को भारत में बेचने की इच्छा 2015 से ही जताते आ रहे हैं। इसी कड़ी में टेस्ला ने 2017 में अपनी सब्सिडियरी भारतीय कंपनी को बेंगलुरू में पंजीकृत भी करा लिया था, पर बात बन नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त 'लोकल सोर्सिंग' में नियम कानून बेहद सख्त थे।

इन्हीं दिक्कतों का हवाला देते हुए एलॉन मॉस्क ने 2019 में सार्वजनिक मंचों से भारत की 'हाई इंपोर्ट ड्यूटी' को आड़े हाथों लिया था। इसके बाद जून 2023 में मस्क पीएम मोदी से मिले, जब मोदी अपने अमरीकी दौरे पर थे। इस मुलाकात का असर यह हुआ कि इस वर्ष मार्च में केंद्र सरकार ने ईवी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी।

इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी सामने आया और गडकरी ने कहा कि 'मस्क को अगर टेस्ला को भारत लाना है तो उन्हें यहां मेन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी।' सूत्र बताते हैं कि टेस्ला अब गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपनी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए जगह तलाश रही है और माना जाता है कि इस कड़ी में उन्हें रिलायंस के रूप में एक लोकल पार्टनर भी मिल गया है।

सियासी मोती चुनने में पारंगत हंस

पंजाबी फोक सिंगर हंसराज हंस राग और सियासी राग चुनने में पारंगत माने जाते हैं। इस बार जब उनका उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा से टिकट कटा तो उन्होंने किंचित विद्रोही मुद्रा अख्तियार कर ली, आप नेताओं से उनकी पींगे बढ़ने लगी थीं। इसे देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पंजाब के फरीदकोट सीट से चुनाव लड़ाने का आनन-फानन में फैसला कर लिया।

सियासी मोती चुगने में माहिर हंस पहले ही कई राजनीतिक दलों का सफर तय कर आए हैं। वे शिरोमणि अकाली दल में रहे, फिर वहां से कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से भाजपा में और अब की बार उनकी आप की मुंडेर पर नजर थी। पर फरीदकोट का मैदान हंस के लिए आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि वहां उनका मुकाबला एक जाने-माने सूफी सिंगर मोहम्मद सादिक से है जो कि वहां से कांग्रेस के निवर्तमान सांसद भी हैं। इस घमासान को दिलचस्प बनाने के लिए एक तीसरे पापुलर सिंगर करमजीत निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। वैसे भी हंसराज हंस अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में जहां भी जा रहे हैं वहां उन्हें स्थानीय किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

क्या बिट्टू से दोस्ती निभाएंगे मनीष?

लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू और आनंदपुर साहिब से निवर्तमान कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी में गहरी छनती है। परिस्थितियां बदलीं और इस दफे बिट्टू कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा शीर्ष बिट्टू को आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ा सकता है, जहां से वे 2009 में अपना पहला चुनाव जीते थे। सूत्रों की मानें तो बिट्टू ने मनीष को फोन कर कहा कि 'आप मेरे दोस्त और बड़े भाई की तरह हो सो आनंदपुर साहिब से आपके खिलाफ चुनाव लड़ने में मुझे हिचक हो रही है। क्या यह संभव है कि आप सीट बदल कर लुधियाना या चंडीगढ़ चले जाओ' इस पर मनीष ने कहा कि 'यह तो हाईकमान पर निर्भर है कि वह मुझे कहां से चुनाव लड़ाना चाहता है फिर भी मैं एक बार सोनिया जी से बात करूंगा।' ताजा जानकारियों के मुताबिक खड़गे के नेतृत्व वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने इस दफे मनीष तिवारी का नाम चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित किया है। आज या कल में ही इस पर राहुल गांधी की सहमति या असहमति की मुहर लगनी है, तब कहीं जाकर इस बात का पता चल पाएगा कि क्या वाकई मनीष तिवारी अपने दोस्त की भावनाओं की रक्षा कर पाए हैं?

भाजपा में असंतोष के स्वर

क्या 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनाव में भगवा ताने-बाने की गांठें कमजोर पड़ी हैं। वरना चुप सियासी सन्नाटों से हाईकमान की मंशाओं को बटोरने वाले भगवा नेता बागी राग गाने की हिमाकत कैसे कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों भाजपा महासचिव सुनील बंसल ने कुछ सीनियर भाजपा नेताओं को तलब कर उन्हें कुछ महती चुनावी जिम्मेदारियां देने की पहल की। पर बंसल उस वक्त हैरत में डूब गए जब उन्होंने पाया कि इनमें से कई स्थानीय नेता चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इनमें से कई नेता वैसे थे जो पार्टी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, पर शीर्ष नेतृत्व ने बाहर से आए नेताओं को उनकी जगह प्राथमिकता दे दी।

कई नेता यह कहते मिले कि उन्होंने 2014 से लगातार पार्टी टिकट का इंतजार किया पर वे अब निराश हैं। इस पर बंसल ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि 'आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें पार्टी टिकट से मैदान में उतारा जाएगा।'

नहले पर दहला जड़ती ममता

पिछले दिनों बेंगलुरू बलास्ट के दो आरोपियों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। जैसे ही यह खबर आई भाजपा डिजिटल सेल के प्रमुख अमित मालवीय का 'एक्स' पर पोस्ट आ गया कि 'पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए एक 'सेफ हेवेन' बन गया है।' मालवीय की पोस्ट सामने आते ही पश्चिम बंगाल पुलिस के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से इसका जवाब आता है कि 'आप सेफ हेवेन कैसे कह सकते हैं क्योंकि इन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करवाने में हमने एनआईए की पूरी मदद की है।' मामला यहीं नहीं थमा। उस वक्त कूच बिहार में रैली कर रही ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रहीं। ममता ने कहा कि 'बंगाल आतंकवादियों के लिए सेफ हेवेन नहीं है, ब्लास्ट के आरोपी कर्नाटक के हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो घंटे ही बिताए थे कि मेदिनीपुर पुलिस ने यह सूचना एनआईए को दी और उन्हें झट से पकड़वा दिया।' यानी भाजपा के सोशल मीडिया पर अब विरोधी दल भी बीस साबित हो रहे हैं।

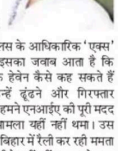

...और अंत में

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हिरासत में हैं। और पार्टी की आवाज़ सड़कों पर चूंकि आप के कई नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं इसे देखते हुए आप की कोर टीम का सुझाव है कि 'अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरना चाहिए।' खास कर इन आशंकाओं के बीच कि यहां किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आप से जुड़े सूत्र खुलासा करते हैं कि 'सुनीता केजरीवाल भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के खिलाफ नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं।' कहते हैं पार्टी कैडर का यह सुझाव यहां के मौजूदा आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती को भी मुफीद लग रहा है। वह अपनी सीट छोड़ने को तैयार बताए जा रहे हैं।

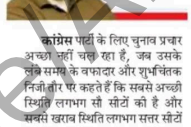

कांग्रेस का चुनाव प्रचार और संभावनाएं!

खरी-खरी बात
-वीरेन्द्र कपूर

कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अच्छा नहीं चल रहा है, जब उसके लंबे समय के वफादार और शुभचिंतक निजी तौर पर कहते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति लगभग सौ सीटों की है और सबसे खराब स्थिति लगभग सत्तर सीटों की है। नि:संदेह, उनसे यह अपेक्षा न करें कि वे सार्वजनिक रूप से ऐसा कहेंगे। सार्वजनिक रूप से वे दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ वे लगभग 250 सीटें जीत सकते हैं। पार्टी में क्या चल रहा है और इसकी स्थिति से भलीभांति अवगत कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमें पिछले सप्ताह अनौपचारिक रूप से मिलने का मौका मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की कि लंबे प्रशिक्षण के बावजूद राहुल गांधी अभी भी एक बुद्धिमान और स्पष्ट वक्ता के रूप में परिपक्व नहीं हुए हैं। अपने श्रोताओं के साथ जुड़ाव स्थापित करने में उनकी विफलता ने उन्हें चिंतित कर दिया है, खासकर तब जब संगठन उन्हें प्रचार अभियान में सबसे अधिक तवज्जो देने के लिए बाध्य है।

इसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और वायरल वीडियो चर्चा में आया। इस वीडियो में खड़गे एक सार्वजनिक बैठक में मंच पर बैठे और खुलेआम अपने दुर्भाग्य पर विलाप करते नजर आ रहे हैं। वस्तुत: उन्हें यह कहते हुए सुना जाता है कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं 80 साल का हूं, वे मुझे धक्का देते हैं जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि वे सारा ध्यान गांधी परिवार पर केंद्रित करते हैं। मुद्दा यह है कि पूरी पार्टी राहुल गांधी की छवि को आगे बढ़ाने में लगी हुई है।

एआईसीसी के अनुभवी सदस्य एक दिलचस्प सुझाव लेकर आए। उनके अनुसार, पार्टी को शशि थरूर या यहां तक कि मनीष तिवारी जैसे किसी व्यक्ति को अपने नेता के रूप में पेश करना चाहिए और उन्हें चुनाव अभियान की कमान संभालने की अनुमति देनी चाहिए। यह इस स्पष्ट समझ के साथ किया जा सकता है कि यदि पार्टी अपने दम पर या सहयोगियों के साथ गठबंधन में सरकार बनाने की स्थिति में है तो नेतृत्व कौन करेगा?

कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ठीक उसी प्रकार कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार फसल-बंटवारे की व्यवस्था में वास्तव में भूमि जोतने वाले के साथ भूमि के स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यदि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए थरूर या तिवारी जैसे योग्य और बुद्धिमान नेताओं की सेवाओं का उपयोग करती है तो उन्हें लाभ होगा। चुनावों के बाद गांधी परिवार यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि यदि कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा बनती है तो सत्ता के पदों से किसे पुरस्कृत किया जाए और यदि विपक्ष में है तो किसे संसदीय नेता नियुक्त किया जाए।

एक नेता ने अफसोस जताया कि इस वक्त सबसे पुरानी पार्टी चुनावी दलदल में फंसी हुई है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी और नेहरू जैसा करिश्मा अब दिखाई नहीं दे रहा है। 'मोदी के असफल होने का इंतजार करना, लोगों का विश्वास खोना एक कर्म का खेल है, यह आसमान से मुराद के आपकी झोली में गिरने का इंतजार करने जैसा है। राहुल लगभग दो दशकों से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस भूमिका के लिए आवश्यक परिपक्वता और ज्ञान की प्रतीक्षा बनी हुई है। फिर भी परिवार उस भूमिका को अधिक योग्य उम्मीदवार को सौंपने से इन्कार करता है, भले ही यह केवल मतदाताओं को आकर्षित करने के सीमित उद्देश्य के लिए हो। जिस दूसरे नेता से हमने बात की उन्होंने केसी वेणुगोपाल पर अपना गुस्सा निकाला जो राहुल के भरोसेमंद सहयोगी बनकर कई अन्य कांग्रेसियों को गलत तरीके से परेशान करते हैं।

> पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और वायरल वीडियो चर्चा में आया। इस वीडियो में खड़गे एक सार्वजनिक बैठक में मंच पर बैठे और खुलेआम अपने दुर्भाग्य पर विलाप करते नजर आ रहे हैं। वस्तुत: उन्हें यह कहते हुए सुना जाता है कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं 80 साल का हूं, वे मुझे धक्का देते हैं जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूं।

विशेष रूप से उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक में शामिल नहीं होने के पार्टी नेतृत्व के फैसले पर अफसोस जताया। भले ही गांधी और खड़गे को नहीं जाना था, उन्हें कनिष्ठ नेताओं को नियुक्त करना चाहिए था ताकि भाजपा यह प्रचार न करे कि पार्टी ने ऐतिहासिक कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। गांधी परिवार ने लोगों के सामूहिक मानस के बारे में बहुत कम समझ दिखाई। अमेठी और रायबरेली सीटों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने में पार्टी की विफलता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अफसोस जताया कि मीडिया में अटकलें पार्टी पर खराब प्रभाव डालती हैं। क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या कोई और, रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि चूंकि उन्होंने सक्रिय राजनीति में शामिल होने की उत्सुकता दिखाई है इसलिए उम्मीदवार के नाम में देरी सम्भव है।

दावा किया गया है कि राहुल को डर है कि दूसरी सीट से उनके नामांकन की घोषणा करने से वायनाड के मतदाता नाराज हो जाएंगे जो उन पर आरोप लगाएंगे कि अगर वह अमेठी में जीत गए तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। हमें उनसे दिल्ली से उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में हो रही देरी के बारे में पूछने का कोई मतलब नजर नहीं आया। बीजेपी और आप दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। कुछ नेताओं की चुनाव लड़ने की अनिच्छा के कारण देरी हुई। दिल्ली कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसने स्वयं भाजपा के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी और जब उसे भाजपा में कोई पद नहीं मिला तो वह कांग्रेस में लौट आया जो एक समय की महान पार्टी की खराब स्थिति की अपनी कहानी बताता है।

मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं... मैं आखिरी सांस तक इस दल के साथ रहूंगा : पप्पू यादव

पटना, (पंजाब केसरी): बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और आखिरी सांस तक इस दल के साथ रहेंगे। उन्होंने हाल में 2015 में स्थापित अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। यादव को पूर्णिया सीट पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) सांसद संतोष कुमार कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार बीमा भारती के साथ त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ा रहा है।

1990 के दशक में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तीन बार पूर्णिया सीट जीतने वाले यादव ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ''मैं कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक सिपाही हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक (वैचारिक तौर पर) कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेरे खून में है।''

'महागठबंधन' के घटक दलों के बीच हुए सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया सीट राजद के खाते में गई है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने कथित तौर पर पप्पू यादव को इस सीट से नामांकन वापस लेने की सलाह दी थी पर वह पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हैं।

पप्पू यादव ने 'महागठबंधन' में दरार के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया, मैं कभी नहीं चाहता था कि पूर्णिया में पश्चिम बंगाल और केरल की तरह 'इंडिया' गठबंधन के घटक एक-दूसरे से लड़ते दिखें लेकिन लालू प्रसाद ने मेरे साथ अन्याय किया।

उन्होंने कहा-जब भी मैंने चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरा विरोध किया। अपने प्रति उनकी इस नफरत को समझने में मैं असमर्थ रहा हूं। उन्होंने बाधाएं खड़ी की। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा, ''उन्होंने मेरी पत्नी रंजीत रंजन (कांग्रेस राज्यसभा सांसद) के साथ भी ऐसा ही किया है। लेकिन मैंने पूर्णिया के लोगों से वादा किया है कि मैं उनके लिए लड़ूंगा। यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है।''

उन्होंने दावा किया कि उन्हें राजद की ओर से पूर्णिया के बजाए मधेपुरा और सुपौल से चुनाव लडने की पेशकश की गयी पर उन्हें यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। पप्पू यादव ने कहा} मैं अपनी पहचान और विचारधारा से समझौता नहीं कर सकता। पूर्णिया मेरी कर्मभूमि है और मैं इसे आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर भ्रष्टाचार से लड़ने और सीमांचल तथा कोसी क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।

उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा, ''उन्होंने मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। बिहार की राजनीति में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश रची। पूर्णिया इसे कभी नहीं भूलेगा... यहां के मतदाता उन्हें चुनाव में करारा जवाब देंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अपने भविष्य की योजना के बारे में बताते हुए पप्पू यादव ने कहा-मेरी प्रमुखता कुछ प्रमुख उद्योगों को पूर्णिया में लाना है ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

सहमे लोकतंत्र से कुछ सवाल

राजनीति यकीनन एक महंगा शगल है, इसे चलाने के लिए चंदे की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में, यह सवाल कतई नाजायज नहीं है कि जो व्यापारी या कारोबारी घराने चुनावी चंदा देंगे, वे भला राजनीतिज्ञों से लाभ की उम्मीद क्यों नहीं करेंगे? संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस यक्ष-प्रश्न के आगे सहमा-सा क्यों नजर आता है?

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

बोस्फोरस की खाड़ी की शांत लहरों पर फिसलती-सी हमारी जहाजनुमा नौका प्रिंसेस द्वीप के मुहाने पर पहुंचने को थी कि कानों से जोशीले भाषण के बोल टकराते हैं। इस टापू की चिरंतन वीरानी में यह क्या? विस्मित भाव से हम जेटी पर उतरते हैं। सामने द्वीप के मुख्य चौक पर चुनावी सभा चल रही है।

पिछले महीने के आखीर में जब पुनः तुर्किये जाने का मौका मिला, तो इस्तांबुल के लोगों की गर्मजोशी और माहौल में पसरी सदाबहार रोमानियत याद हो आई थी। हालांकि, इस बार माहौल बदला-बदला सा था। चाहे तक्सिम स्क्वॉयर हो या प्रिंसेस द्वीप, आया सोफिया के चारों ओर बिखरी पुरातनता हो या फिर किसी मॉल की आधुनिकता- जोशीले तुर्क चुनावी बहस-मुबाहिसे में मशगूल थे। सड़कें बैनरों और तरह-तरह के साइन बोर्ड से अटी पड़ी थीं। नुक्कड़ सभाओं में जोरदार भाषण हो रहे थे और रेडियो सहित सभी संचार माध्यम चुनाव राग से तर थे। यह हाल तो मेयर के चयन हेतु होने वाले मतदान से पहले था! आम चुनाव होते तो?

हम हिन्दुस्तानी भी तो इस वक्त आम चुनाव से गुजर रहे हैं। क्या कोई उत्तेजना दिख रही है? हमारे चुनावों पर चुनाव आयोग ने यह नीरसता धन का दुरुपयोग रोकने के लिए थोपी थी? क्या धनबल का प्रकोप रुक सका?

इन सवालों का उत्तर देने से पहले मैं आपको 1960 के दशक में ले चलना चाहूंगा। यह वह समय था, जब कांग्रेस को तमाम महारथी चुनावी टक्कर दे रहे थे। राम मनोहर लोहिया उनमें से एक थे। लोहिया जानते थे कि वह सत्ताधारी पार्टी के धनबल से निपट नहीं सकते। उन्होंने इसकी काट के लिए नारा दिया, 'एक नोट एक वोट'। उनके दल के लोग जनसभाओं में शामिल हर व्यक्ति से एक रुपये की मदद की अपील करते थे। यह प्रयोग बाद में तमाम पार्टियों ने किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम और अरविंद केजरीवाल भी मतदाता से जुटाए धन के जरिये सफलता हासिल कर चुके हैं।

कैसी विडंबना है, कांशीराम की उत्तराधिकारी मायावती सत्ता पाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गईं। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं और केजरीवाल कथित शराब घोटाले के आरोप में फिलवक्त सीखचों के पीछे हैं। वे अकेले नहीं हैं। ऐसे तमाम सियासतदां हैं, जो परिवर्तन की हिमायत के साथ तमाम सदनों में दाखिल हुए और देर-सवेर उन्हें इलहाम हो गया कि जुनून, जोश और नारों के सहारे राजनीति के महंगे राजमार्ग पर लंबी दूरी नहीं नापी जा सकती।

यही वजह है कि 1970 और 80 के दशक में ही राजनीति में धन और बाहुबल का प्रकोप जोर पकड़ गया था। सत्ताधीशों को आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संगत अधिक पसंद आने लगी थी। देखते-देखते कोई राजनीतिक दल इस रोग से अछूता न रहा। 'माननीय' होने के बाद आप इन्हें अपराधी नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्हें बाहुबली कहा जाने लगा।

यह नया पनपा मुहावरा कई दास्तानें एक साथ बयां करता है।

कोई आश्चर्य नहीं कि ग्राम पंचायतों से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा में भी ऐसे लोगों की तादाद बढ़ने लगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े बताते हैं कि देश की 17वीं लोकसभा में जहां 159 सदस्य (लगभग 29 प्रतिशत) बेहद गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपी थे, तो वहीं राज्यसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या 18 फीसदी है। एडीआर के ही जून 2023 के एक विश्लेषण में पाया गया था कि 28 राज्यों और दो केंद्रशासित क्षेत्रों के विधानमंडलों में 1,136, यानी करीब 28 प्रतिशत ऐसे 'माननीय' आस्तीनें चढ़ाए बैठे थे। यही हाल धनपतियों का है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश के उच्च सदन (राज्यसभा) में जहां आज 12 प्रतिशत सदस्य सौ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति रखने वाले हैं, तो वहीं आज से पांच साल पहले चुने गए 266 लोकसभा सदस्य पांच करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति के मालिक थे। बताने की जरूरत नहीं, आज भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति रोजाना आय 464 रुपये पर अटकी हुई है।

मतलब साफ है, आम हिन्दुस्तानी की भूमिका महज एक मतदाता तक सीमित होकर रह गई है। इनमें से बहुतों को जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के साथ धन का प्रलोभन किसी प्रत्याशी विशेष के लिए संजीवनी का काम करता है। यह अकारण नहीं है कि पिछले एक दशक में चुनाव आयोग द्वारा जब्त किए गए धन और शराब के आंकड़ों में खासी बढ़ोतरी हुई। साल 2009 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग ने जहां 190 करोड़ रुपये जब्त किए थे, तो 2019 में यह जब्ती 841 करोड़ से भी अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसी तरह, 2014 में जहां एक करोड़ 60 लाख लीटर शराब बरामद की गई थी, तो 2019 में एक करोड़ 86 लाख लीटर जब्त की गई।

यही नहीं, अपने मुल्क में जहां हर कुछ महीने पर कोई न कोई चुनाव होता हो, वहां राजनेताओं और पार्टियों को तमाम तरह से धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया था कि हमें चुनाव के दौरान प्रति ब्लॉक कम से कम दो गाड़ियों और उनके जरिये प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। लोकसभा के एक चुनाव में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पचास के आसपास गाड़ियां कम से कम लगानी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक में एक दफ्तर चलता है, जहां कार्यकर्ताओं के विश्राम और भोजन की व्यवस्था करनी होती है। चुनाव के पहले वाली रात तो गांव-दर-गांव लोगों को 'खिलाने-पिलाने' में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। अपनी अथवा किसी बड़े नेता की चुनावी सभा में भी लाखों रुपये खर्च होते हैं।

एक अन्य 'माननीय' ने बताया कि पहले तो सिर्फ परचे, बैनर और पोस्टर के जरिये काम हो जाता था। अब पोस्टर और बैनर पर रोक लग गई है, मगर सोशल मीडिया पर पूरे पांच साल तमाम लोगों को सक्रिय रखना पड़ता है। वे न केवल हमारा गुणगान करते हैं, बल्कि विपक्षियों पर भी हमला बोलते रहते हैं। इस सब में चुनाव के लिए खर्च की तय राशि से काम नहीं चलता। राजनीति यकीनन एक महंगा शगल है, इसे चलाने के लिए चंदे की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है।

ऐसे में, यह सवाल कतई नाजायज नहीं है कि जो व्यापारी या कारोबारी घराने चुनावी चंदा देंगे, वे भला राजनीतिज्ञों से लाभ की उम्मीद क्यों नहीं करेंगे? संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस यक्ष-प्रश्न के आगे सहमा-सा क्यों नजर आता है?

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

सानिया निश्तर
डॉक्टर, सीनेटर

पाकिस्तान को एक अलग पहचान देती सानिया

पिता अक्सर उनसे कहा करते- 'बेटी, इंसान की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जो दूसरे के जीवन में कुछ फर्क ला सके। जो आपसे कम खुशकिस्मत लोग हैं, उनकी मदद करना और उन्हें अपने काम से आराम व सुकून देना ऊपर वाले का सबसे पसंदीदा अमल है।'

इस्लामी मुल्कों में औरतों के हक-हुकूक को लेकर दुनिया भर में तरह-तरह की सच्ची-झूठी कहानियां कही-सुनी गईं। दुर्योग से तालिबान, बोको हराम और आईएस की ज्यादतियों और ईरानी निजाम की दमनकारी नीतियों ने मुस्लिम देशों की औरतों की उपलब्धियों को नेपथ्य में डाल दिया। दुनिया भर में उनकी छवि एक मजलूम व दबाई-सताई गई आबादी के रूप में मजबूत होती गई। मगर सलाम है उन औरतों को, जो न सिर्फ अपने-अपने मुल्क के कट्टरपंथियों का मुकाबला करती रही हैं; समाज में बेहतर मुकाम पाने के लिए संघर्षरत हैं, बल्कि अपनी जेहनियत से पश्चिमी मीडिया की गलतफहमियां भी दूर कर रही हैं। सानिया निश्तर एक ऐसा ही नाम है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, बल्कि हाल ही में गरीब मुल्कों में टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था 'गैवी' की सीईओ नियुक्त की गई हैं।

करीब 61 साल पहले पेशावर के एक संपन्न परिवार में जन्मी सानिया के पिता सैयद हामिद खुद भी डॉक्टर थे। तरक्कीपसंद माता-पिता की बेटी सानिया को उस जमाने में वे सारी सहूलियतें हासिल थीं, जो आज भी कई संपन्न घरों के बच्चों को नसीब नहीं। वह स्विमिंग कर सकती थीं, गोल्फ खेल सकती थीं, मुकाबलों में शिरकत कर सकती थीं और मुल्क से बाहर पढ़ने के ख्वाब संजो सकती थीं। बचपन से पिता ने बेटी को बस यही सीख दी कि जो भी काम करो, उसको करते हुए तुम्हारी शिद्दत और ईमानदारी में कोई कमी न रहने पाए। वह अक्सर सानिया से कहते- बेटी, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जो दूसरे के जीवन में कुछ फर्क ला सके। जो आपसे कम खुशकिस्मत लोग हैं, उन्हें आराम और सुकून देना ऊपर वाले का सबसे पसंदीदा अमल है।

इन फलसफों का मर्म सानिया को तब समझ में आया, जब एक दिन अचानक डॉक्टर हामिद सबको अलविदा कह गए! वह उस वक्त महज 15 साल की थीं। पिता की मौत से गहरा सदमा लगा था, मगर जीने का मकसद तो वह सानिया को दे ही गए थे। वह अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत से जुट गईं। एक अर्थवान जीवन की चाह उन्हें पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां से 1986 में उन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलते ही अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सानिया के लिए रिश्तों की कतार लग गई थी। 23 साल की सानिया ने गालिब निश्तर के प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी।

शादी के बाद अगले छह साल परिवार और दोनों बच्चों के नाम रहे। इसके बाद सानिया ने खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से अपनी रेजिडेंसी पूरी की और साल 1994 में बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस' से

जुड़ गईं। लोगों का इलाज करते हुए सानिया का यह एहसास पुख्ता होता गया कि स्वास्थ्य-क्षेत्र में यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। अस्पतालों और संसाधनों की कमी के अलावा सेहत के प्रति लोगों की लापरवाही भी एक बड़ा मसला है। सानिया यह भी अच्छी तरह जान गई थीं कि सिर्फ एक अस्पताल तक महदूद रहकर वह गरीब मरीजों के हक में बड़ा बदलाव कभी नहीं ला सकेंगी। इसीलिए उन्होंने साल 1998 में एक गैर-लाभकारी संगठन 'हार्टफाइल' की शुरुआत की। इसका मकसद लोगों में हृदय रोग संबंधी जागरूकता फैलाने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के बारे में सरकार को सलाह देना भी था।

संयोग से कुछ ही वर्षों में सानिया को लंदन के किंग्स कॉलेज से पीएचडी करने का मौका मिला और इस डिग्री ने इस्लामाबाद में उनके सुझावों की अहमियत बढ़ा दी थी। अपने एनजीओ के तहत काम करते हुए उन्हें पता चला कि पाकिस्तान सरकार के पास संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए तो नीतियां हैं, मगर पुराने रोगों के उपचार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। जाहिर है, इसके सबसे ज्यादा शिकार गरीब मरीज ही हो रहे थे। लिहाजा, सानिया ने अपने संगठन के जरिये सरकार पर इसकी खातिर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्हें कामयाबी मिली और साल 2003 में पाकिस्तान सरकार ने गैर-संक्रामक रोगों के उपचार से जुड़ी एक राष्ट्रीय योजना विकसित करने में उनका सहयोग मांगा। सानिया की प्रतिबद्धता को देखते हुए जेनेवा स्थिति वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, डब्ल्यूएचओ जैसी शीर्ष वैश्विक संस्थाओं ने उन्हें अपने बोर्ड या कार्यक्रमों में शामिल किया। वह एक विश्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गईं। साल 2013 में सानिया निश्तर की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया, जब आम चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मीर हजार खान खोसो ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल किया। सानिया के पास विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा व प्रशिक्षण और स्वास्थ्य मंत्रालय आया।

इस हैसियत ने उनके तजुर्बे में काफी इजाफा किया। लिहाजा, साल 2019 में वह इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ गईं। इमरान खान सरकार ने जब पाकिस्तान में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 'एहसास' की शुरुआत की, तो इसकी निगहबानी के लिए उसे सानिया ही सबसे मुफीद लगीं। इस कार्यक्रम को दुनिया भर में सराहा गया था। पाकिस्तान सरकार उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'सितारा-

इमरान सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 'एहसास' की शुरुआत की, तो इसकी सदारत के लिए उसे सानिया ही सबसे मुफीद लगीं। पाकिस्तान सरकार उन्हें 'सितारा-ए-इम्तियाज' से नवाज ही चुकी थी, *बीबीसी* ने 100 प्रभावशाली वैश्विक महिलाओं में शुमार किया।

ए-इम्तियाज' से पहले ही नवाज चुकी थी, *बीबीसी* ने साल 2020 की 100 प्रभावशाली वैश्विक महिलाओं में शुमार किया। मार्च 2021 में पार्टी ने सानिया को खैबर पख्तूनख्वा संसदीय क्षेत्र से सीनेट में भेजा।

पेशावर से निकलकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली सानिया आज न सिर्फ अपने मुल्क, बल्कि उन तमाम इस्लामी देशों की बेटियों के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहती हैं।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

जॉन डेवी
विख्यात शिक्षाविद्

फिजूल की पिटाई से सच्ची पढ़ाई तक

वह उसी कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जहां पढ़ने के लिए भारत से भीमराव आंबेडकर गए थे। पूरे दो साल उन्होंने आंबेडकर को अपने सान्निध्य में रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। स्नेहिल प्रोफेसर की शिक्षा बाबा साहब के बहुत काम आई।

शिक्षा की शरण में जाना मनुष्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो शिक्षा सिलसिला है, पर जिंदगी में सोचने-समझने की शुरुआत के समय ही शिक्षा यदि शुरू हो जाए, तो सोने पर सुहागा है। अपने गुजारे के लिए हर सुबह अखबार बांटने वाला वह किशोर भी सोने पर सुहागे की तलाश में ही स्कूल जाता था। अमेरिका में तब स्कूली व्यवस्था जर्जर थी, मुल्क गृह युद्ध में ही खर्च हो रहा था। मास्टर भी खासे रोष खाए रहते थे। कुछ मास्टर हरदम कोड़ा थामे हाथ साफ करने की फिराक में दिखते थे और कुछ ऐसे बच्चे भी थे, जो रोज पिटने के लिए ही शायद स्कूल आते थे। चवन्नी गलती पर सोलह आना पिटाई मामूली बात थी।

हर बार कोड़े से ज्यादा जुबान बरसती थी। सब मानते थे कि चलो शिक्षक हैं, तो कटु बोल सकते हैं। सीधे मूर्ख भी ठहरा सकते हैं, पर जब पिटाई होती, तब हर कोई तमाशे देखता था। ज्यादातर लोग दूसरे की पिटाई देख मंद-मंद मुस्काते थे, पर उस किशोर को पिटाई की व्यर्थता तब भी समझ में आने लगी थी।

वह सीधा-सादा स्कूली किशोर बहुत बचकर रहता था। स्कूल में अच्छे अनुभव कम और बुरे अनुभव ज्यादा मिलते थे। पढ़ना अच्छा लगता था, नंबर भी अच्छे आते थे, पर स्कूल बिल्कुल नापसंद था। एक दिन तो हद हो गई, एक गरीब लड़के की जमकर पिटाई हो रही थी। शिक्षक बेचारे लड़के को ऐसे पीट रहे थे, मानो गृहयुद्ध लड़ रहे हों। सामंत स्वभाव के शिक्षक अपने अहंकार पर पड़ी किसी मामूली चोट का बदला ले रहे थे, पढ़ाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। वह लड़का भय और अपमान से थर्रा रहा था, उसकी सहमी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कोई सुनवाई नहीं। लड़का बचाव में जब भी मुंह खोलता, तो मार शरीर पर और गहरे पड़ती। उस गरीब लड़के की पिटाई पर तब भी लोग मुस्करा रहे थे, पर यह संवेदनशील किशोर अंदर से रो रहा था। वह कमजोर था, वह चुप रह गया, क्योंकि अगर वह मुंह खोलता, तो वह भी बचने न पाता।

स्कूल की यह त्रासद घटना मानो दिल में बस गई। पिटने वाला बच्चा तो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक, शिक्षा और स्कूल के प्रति जो सहज लगाव होना चाहिए, वह तो कभी नहीं हो पाएगा। दिल में गांठें रह गईं, कभी फिजूल डांट से, तो कभी बेरहम मार से। कौन रोके डांट और कौन रोके पिटाई? चिंतन की धारा बह निकली। शिक्षक शायद इसलिए पीटते थे कि एक ही बार में सुधार देंगे, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने हमेशा के लिए कितना कुछ बिगाड़ दिया। पिटाई से सुधरने की गारंटी नहीं, पर बिगड़ जाना तय है और ऐसे बिगड़े माहौल में न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं। बच्चों को स्कूलों में घसीट-घसीटकर, डरा-धमकाकर लाया जा रहा है। नहीं, शिक्षा का यह स्वरूप गलत है, एक नया स्वरूप गढ़ना होगा।

उस किशोर अर्थात जॉन डेवी ने स्नातक होने के बाद स्कूल में शिक्षक बनना मंजूर किया। बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाना शुरू किया, पर दो वर्ष में ही एहसास हो गया कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ बड़ा करना होगा। स्कूल में पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा। दार्शनिक बनना होगा, तभी बड़े पैमाने पर लोग बात सुनेंगे और सुधार होगा। स्कूल की पक्की नौकरी छोड़कर जॉन डेवी उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में चल पड़े। शिक्षा सुधार के तमाम सुझावों, प्रयासों के साथ उन्होंने देश को प्रभावित किया।

उन्होंने बताया कि 'शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम अनुभव से नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन से सीखते हैं। शिक्षा स्वयं कोई बनी-बनाई चीज नहीं है, बल्कि क्रिया के चयन के माध्यम से निरंतर बनते रहने वाली चीज है।' शिक्षा की दुनिया में उनके नाम का डंका बजने लगा। वह उसी कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जहां पढ़ने के लिए भारत से भीमराव आंबेडकर गए थे। पूरे दो साल जॉन डेवी ने आंबेडकर को अपने सान्निध्य में रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। स्नेहिल स्वभाव के प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा आंबेडकर के बहुत काम आई। आंबेडकर ने बार-बार स्वीकार किया कि उन्हें बनाने में जॉन डेवी का बहुत योगदान है। जब भी आंबेडकर याद किए जाते हैं, जॉन डेवी भी याद आते हैं।

जॉन डेवी (1859-1952) कोड़े मारने वाले उस शिक्षक को भूल न पाए थे। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किए, पर अभी भी उनका सपना साकार नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे- सारे लोग अभी भी पूरा शिक्षित-जागरूक नहीं हुए हैं। शिक्षा अभी भी पूरी स्नेहिल नहीं हुई है। एक दिन आएगा, जब दुनिया के सभी स्कूलों में शिक्षक कक्षा में आते ही सीधे पढ़ाने नहीं लगेंगे, बच्चों को कुछ करने के लिए देंगे और बच्चे कुछ-कुछ करते हुए ही सच्ची शिक्षा पाएंगे।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

आखिर किसके चरण पखारूं

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

किस्सा कुछ पुराना है। मेरे प्रकाशक मित्र ने एक दिन पूछा, सर आपकी नई किताब का समर्पण पेज खाली जा रहा है। किसी को समर्पित करना हो, तो बताएं? मैंने कहा, इस बार मैं किसी को भी समर्पित नहीं करने वाला। मित्र ने सुझाया, सब समर्पण करते हैं, आप भी कर दीजिए। पेज भी खाली न जाएगा और जिसका नाम आएगा, वह भी खुश हो जाएगा।

मैंने कहा, मुझे इस समर्पण शब्द से ही चिढ़ है। इससे मध्यकालीनता की बू आती है। यह 'फ्यूडल कल्चर' का हिस्सा है। यह शब्द भक्तिकालीन परंपरा का है। तब देवता थे, उनके भक्त थे। उनमें अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव था। वे सब कुछ समर्पित करके चलते थे। अब न वैसे भक्त हैं और न उनके इष्ट हैं। आज के अधिकांश इष्ट एकदम भ्रष्ट हैं। बताइए, किसे पूजूं? किसको नैवेद्य चढ़ाऊं? इसलिए इस बार मैं समर्पण नहीं करने वाला।

प्रकाशक मित्र ने टोका, पर पहले तो आप समर्पण पेज पर समर्पण करते रहे हैं? मैंने कहा- पता नहीं क्यों ऐसा करता रहा? सब करते रहे, तो नकल में अपन भी करते रहे। पर ऐसे समर्पण से हासिल क्या हुआ? कुछ दुश्मन जरूर बना लिए। होम करते हाथ जला लिया। अब नहीं।

मित्र बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? जिसका नाम लेंगे, वह तो धन्य हो जाएगा। दस जगह बताएगा, तो लोग किताब खरीदेंगे, और नहीं तो उसके नाते-रिश्तेदार ही खरीदेंगे। किताब का मार्केट बन जाएगा। मुझसे रहा न गया- किस मार्केट की बात करते हो भाई? समर्पण से कोई मार्केट नहीं बना करता, हां! कुछ दुश्मन जरूर बन जाते हैं। जिस जमाने में कोई दोस्त न बनता हो, उसमें और दुश्मन क्यों बनाऊं?

मित्र ने फिर टोका, आप भी अजीब बात करते हैं? लोग तो चाहते हैं कि कोई उनको अपनी किताब समर्पित करे और उनका भी नाम साहित्य में आए। लोगों ने तो किताबें समर्पित कर-करके करियर बना लिए। एक ने एक ही किताब लिखी, पर उसे ऐसे महामना को समर्पित किया कि प्रोफेसर हो गया। एक अन्य ने अपनी किताब खास साहित्य-संस्कृति के मर्मज्ञ को समर्पित किया और बदले में उसे कई किताबें लिखने का 'कांट्रेक्ट' मिल गया। सही इष्ट को अर्पित करेंगे, तो उसका आशीष मिलेगा ही!

मैंने कहा, सब बकवास है। दूसरों की देखा-देखी मैंने भी शुरू में समर्पणबाजी की थी। अपनी पहली किताब जिसे समर्पित की, उसने मुझे कुछ इस तरह से देखा, जैसे मैंने समर्पण न किया हो, बल्कि उसने मुझ पर एहसान किया हो। फिर मीडिया पर लिखी अपनी किताब एक मीडिया महापुरुष को समर्पित की, तो उसके नखरे ही न मिले। वह अंग्रेजीदां, अपन हिंदी वाला, जब उनको किताब देने गया, तो फोन पर ही कहलवा दिया- सर बाहर गए हैं, आप गेट पर छोड़ जाइए। तीसरी बार जब हिंदी के एक बड़े मठाधीश को किताब समर्पित की, तो जलने वालों ने कहा- यह... भी कुछ चाहता है, लेकिन न इस ...ने कुछ चाहा, न उस ...ने ही कुछ दिया।

मित्र नहीं माना। बोला, सब एक जैसे नहीं होते। सही बंदे को आप समर्पित करें, तो भूत-भविष्य-वर्तमान, सब सुरक्षित हो जाता है। इसलिए सोच-समझकर कीजिए। सोचकर हमें बताइए। अभी किताब आने में टाइम है।

मैंने कहा, यार यह बता किसे समर्पित करूं? साहित्यशास्त्र के अनुसार, अगर 'शाहे-वक्त' को करता हूं, तो 'शाहे-विपक्ष' नाराज। इधर कुआं, उधर खाई... बताओ किसमें गिरूं? मित्र का सुझाव आया, नेताओं को नहीं, अपने फैमिली मेंबरों को ही समर्पित कर दीजिए।

यह कभी नहीं कर सकता। किया, तो लोग कहेंगे कि यह साहित्य में 'डायनेस्टी' ला रहा है। वंशवादी है, परिवारवादी है। अगर किसी स्वर्गीय को कर देता हूं, तो नारकीय नाराज और किसी नारकीय को करता हूं, तो हुक्का-पानी बंद! करूं तो क्या करूं? किसके चरण पखारूं?

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

ईश्वर भक्त के मन की शुद्धता परखता है

आतंक को जवाब

एक ऐसे समय जब पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने-पोसने में लगा हुआ है और जब-तब कश्मीर में उनकी घुसपैठ कराने की भी कोशिश करता रहता है, तब ऐसी किसी दो टूक बात की आवश्यकता थी कि आतंकियों को जवाब देने का कोई नियम नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी किसी नियम को नहीं मानते। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बयान देते हुए इसका भी उल्लेख किया कि किस तरह मुंबई में भीषण आतंकी हमले के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर तमाम विचार-विमर्श के बाद भी इस नतीजे पर पहुंची थी कि उसके विरुद्ध कोई कदम न उठाना ही बेहतर है। इस नतीजे पर पहुंचकर मनमोहन सरकार ने न केवल भारत की कमजोरी उजागर की थी, बल्कि पाकिस्तान के दुस्साहस को बढ़ाने का भी काम किया था। इसके नतीजे अच्छे नहीं हुए और भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले झेलने पड़े। पाकिस्तान के होश ठिकाने तब आए, जब पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इसके पहले भारतीय सेना सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुकी थी। यह सही है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते पाकिस्तान के दुस्साहस का दमन हुआ है, लेकिन उसने अभी अपनी जमीन पर चल रहे आतंक के उन अड्डों को बंद नहीं किया है, जहां जिहादी तैयार होते हैं और जो भारतीय सीमा में घुसपैठ की करते रहते हैं। कश्मीर में अभी भी आतंकी जब-तब सिर उठाते रहते हैं। ऐसे में उसे समय-समय पर चेताया जाना आवश्यक है।

यह महत्वपूर्ण है कि विदेश मंत्री के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ शब्दों में यह कह चुके हैं कि यदि आतंकी भारत में कोई हमला करके सीमा पार चले जाते हैं तो वहां भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहले रक्षा मंत्री और अब विदेश मंत्री की इन खरी बातों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि हाल में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने यह दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों को ठिकाने लगाया है। भारत आधिकारिक रूप से तो ऐसे किसी दावे की पुष्टि करने से रहा, लेकिन इससे बेहतर और कुछ नहीं कि पाकिस्तान यह समझने लगा है कि आतंकवाद के मामले में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की नीति बदल चुकी है और यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान ने ब्रिटिश समाचार पत्र के दावे का उल्लेख करते हुए अपना रोना भी रोया है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि विश्व को यह अच्छी तरह पता है कि वह आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का काम करता है। ऐसे में भारत के लिए यही उचित है कि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखे।

प्रशासन की नाकामी

पंजाब में चंडीगढ़-मोहाली मार्ग को बाधित कर कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से लगाए धरने को लेकर हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उसे पुलिस-प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। यह वाकई हैरानीजनक है कि कोर्ट में पिछले वर्ष आश्वासन देने के बावजूद धरना हटाया नहीं गया। एक वर्ष से ज्यादा समय तक सड़क को बाधित करना और पुलिस-प्रशासन का मूकदर्शक बने रहना कई सवाल खड़े करता है। हर किसी को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। आखिर आम जनता के अधिकारों की बात कौन करेगा, इसे कौन देखेगा। चंडीगढ़-मोहाली मार्ग ही क्यों, राज्य में कुछ अन्य मार्ग भी बाधित किए गए हैं और वहां लंबे समय से धरना दिया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को बदले रूट से जाना पड़ रहा है और इसमें उनका समय तो ज्यादा लग ही रहा है, ईंधन की खपत भी अधिक हो रही है। ऐसे मामलों में पुलिस-प्रशासन को सक्रियता दिखानी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। कई बार तो राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर भी निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को हमेशा कानून-व्यवस्था को हर हाल में बहाल रखने के बारे में सोचना चाहिए। अधिकारी यदि इच्छाशक्ति दिखाएं और उचित तरीके से पहले करें तो कोई कारण नहीं कि समस्या का समाधान न हो सके। किसी को भी मनमानी करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

सड़क पर धरना देकर एक वर्ष से ज्यादा समय से यातायात बाधित करना कतई ठीक नहीं है। किसी को भी मनमानी करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए

लोकतंत्र-संविधान के खात्मे का हौवा

संजय गुप्त

यदि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं तो इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह संविधान और लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं?

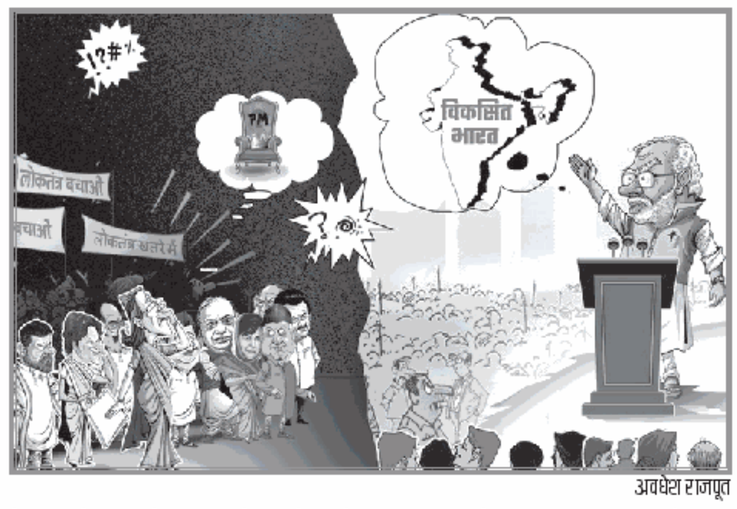

अवधेश राजपूत

राहुल गांधी अब इस पर और अधिक जोर देने में लग गए हैं कि यदि मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान भी नहीं बचेगा। वह अपनी सभाओं में बार-बार कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हैं। लोकतंत्र और संविधान के खतरे में होने के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया कि क्या जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? उन्होंने कांग्रेस से यह प्रश्न भी किया कि यदि संविधान का अनुच्छेद 370 इतना ही अच्छा था तो उसे सारे देश में क्यों नहीं लागू किया गया? कांग्रेस के पास इसका शायद ही कोई जवाब हो।

1947 में जब भारत को आजादी मिली और संविधान सभा गठित हुई तो उसके 299 में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इस समिति में हिंदू महासभा की ओर से प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की, जिसने 1980 में भाजपा का रूप लिया। संविधान सभा में अनुच्छेद 370 का विरोध कई नेताओं ने किया। इनमें बाबा साहब आंबेडकर भी थे। संविधान में कई संशोधन उसके लागू होने के एक वर्ष के अंदर ही कर दिए गए, जिनमें से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने वाला भी था। यह विचित्र है कि आज कांग्रेस ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे में होने का सबसे अधिक शोर मचा रही है। जब संविधान में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने संबंधी अनुच्छेद 356 शामिल किया गया तो उसका विरोध हुआ। आंबेडकर जी ने इस अपेक्षा से इस अनुच्छेद को संविधान का हिस्सा बनाया कि इसके इस्तेमाल की नौबत कम ही आएगी, लेकिन सब जानते हैं कि नेहरू से लेकर नरसिंह राव के समय 356 का किस तरह मनमाना इस्तेमाल हुआ। पिछले वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बताया था कि कांग्रेस की सरकारों ने करीब 90 बार 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को गिराया। इंदिरा गांधी ने तो लगभग 50 बार 356 का इस्तेमाल किया। यह भी किसी से छिपा नहीं कि आपातकाल के दौरान किस तरह संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़े गए।

चूंकि कांग्रेस संविधान खत्म होने का शोर लगातार मचा रही है, इसलिए बीते दिनों प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि यदि आंबेडकर जी आ जाएं तो वह भी संविधान नहीं खत्म कर सकते। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लिए सबसे पवित्र किताब संविधान है और देश इससे ही चलेगा। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रति का नमन करके उसके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की थी। यदि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग चार सौ से अधिक सीटें पा भी जाए तो भी यह याद रहे कि ऐसा पहली बार नहीं होगा। राजीव गांधी के समय अकेले कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थीं। जब कोई दल पूर्ण बहुमत से सत्ता में आता है तो वह अपने एजेंडे को लागू करता ही है। ऐसा कांग्रेस ने भी किया और भाजपा ने भी। यदि मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने और अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं तो क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह संविधान और लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं?

राहुल गांधी इस आधार पर भी लोकतंत्र के खतरे में होने और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किए जाने का आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अपने लोगों को शीर्ष संस्थाओं में नियुक्त कर रही है। यह काम तो हर सरकार करती है। आखिर कांग्रेस या अन्य कोई दल यह अपेक्षा कैसे कर सकता है कि शीर्ष पदों पर नियुक्ति उसके हिसाब से हो? कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं के भगवाकरण का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या जो लोग भारतीयता से ओत-प्रोत हैं और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति शीर्ष पदों पर नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ जांच के आधार पर भी यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खतरा तो राजनीतिक भ्रष्टाचार से है, न कि भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई से। क्या देश में ऐसा कोई कानून है, जो यह कहता हो कि यदि कोई नेता किसी पद पर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ध्यान रहे यह कार्रवाई तभी आगे बढ़ती है, जब अदालतें ऐसे नेताओं को राहत नहीं देतीं। विडंबना यह है कि कांग्रेस के साथ मीडिया का एक हिस्सा भी लोकतंत्र-संविधान के खतरे में होने का हौवा खड़ा कर रहा है। यह हौवा खड़ा कर न्यायपालिका को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है और इसीलिए कुछ दिनों पहले 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह कहा कि एक खास समूह निहित स्वार्थों के चलते न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब तक संविधान में सौ से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। यह स्पष्ट है कि देश की आवश्यकतानुसार आगे भी होंगे। कांग्रेस को यह समझ आए तो अच्छा कि वह संविधान और लोकतंत्र के खत्म होने का जुमला उछालकर अपने पक्ष में कोई ठोस नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रही है। चूंकि वह जनता को लुभाने वाला नैरेटिव खड़ा करने में नाकाम है, इसलिए कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जो कांग्रेस नेता बचे हुए हैं, उनकी मजबूरी है कि वे राहुल गांधी के आरोपों को दोहराएं। यदि कांग्रेस कमजोर हो रही है तो इसका यह अर्थ नहीं कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कांग्रेस की कमजोरी का एक कारण क्षेत्रीय दलों से समझौते के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ना है। अधिकांश क्षेत्रीय दल या तो कांग्रेस से टूट कर निकले हैं या फिर कांग्रेस विरोध की राजनीति से उपजे हैं। आज उनमें से अनेक उसके साथ अवश्य हैं, लेकिन वे उसकी ही जड़ें काट रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस की तरह परिवारवादी हैं और वे अपने दल को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं। ऐसे परिवारवादी दल तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ही हैं।

response@jagran.com

साकार हो रहे बाबा साहब के सपने

असीम अरुण

आंबेडकर जी को याद करते समय यह भी जानने का समय है कि हम कितने समावेशी बन सके हैं?

प्रेरणा के स्रोत बन रहे बाबा साहब के विचार। एएनआइ

आज बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती मनाते समय हमारे पास सामाजिक न्याय की चुनौतियों के विषय में सोचने और नई अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन की बदली स्थिति में आगे के विकल्प तलाशने के बारे में सोचने का भी अवसर है। आंबेडकर जी द्वारा संविधान में सामाजिक न्याय का जो खाका बनाया गया, वह उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित था। उस समय सामाजिक स्तर पर भेदभाव की स्थिति यह थी कि जाति के आधार अस्पृश्यता और तिरस्कार लोगों के सामान्य व्यवहार में शामिल था। अधिकतर शिक्षा सरकारी क्षेत्र में थी और आर्थिक अवसर भी सरकारी नौकरियों में अधिक थे। इनमें वंचित तबकों को भागीदारी दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ तो मिला, पर असमानता पूरी तरह दूर नहीं हो सकी, क्योंकि आरक्षण आधारित अवसरों का लाभ सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिल सका। प्रारंभ में सामाजिक न्याय के लाभ की पात्र केवल अनुसूचित जातियां और जनजातियां थीं। बाद में अन्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण के दायरे मे लाया गया। अब ट्रांस-जेंडर के कल्याण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष में बाबा साहब के सिद्धांतों को संजोते हुए आगे का रास्ता तय करने की जरूरत है। इस पर शोध की आवश्यकता है कि सामाजिक भेदभाव की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका आकलन करने की भी आवश्यकता है कि क्या किरायेदार तय करते समय भेदभाव होता है? क्या महिलाओं को उसी काम के लिए बराबर वेतन मिलता है, जो काम पुरुष करते हैं? ट्रांस-जेंडर लोग यह तो महसूस नहीं करते कि बगल में बैठने वाले लोग उनसे हिचकते-कतराते हैं? यह देखने का भी अवसर है कि अलग दिखने या भिन्न कपड़े पहनने वालों को स्वीकारा जाता है या नहीं? जिस रूप में बाबा साहब ने अस्पृश्यता का अनुभव किया था, वह तो काफी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन सीवर में घुसकर सफाई करने जैसी कुव्यवस्था आज भी मौजूद है और इसे खत्म करना एक चुनौती बना हुई है। यह भी जानने-समझने का समय है कि हम कितने समावेशी बन सके हैं? रोटी-बेटी के रिश्ते बढ़ाने में हम कहां पहुंचे हैं? विविधता स्वीकारने और बराबरी का स्थान देने में हम कितने सफल हुए और इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे?

वर्तमान समय कुछ रोचक परिवर्तनों का अनुसरण करने और उनका अध्ययन करने का है। कई देशों में 'एफरमेटिव एक्शन' यानी सकारात्मक पहल के जरिये विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कारण हमें अमेरिका के विभिन्न संस्थानों और यहां तक कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में महिलाएं या अश्वेत दिखते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिनिधित्व देने की विस्तृत नीति है। यह नीति अन्य पश्चिमी देशों में भी है। इन देशों में शिक्षण संस्थान और अन्य प्रतिष्ठानों में भी अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कुछ इसी राह पर चलते हुए कुछ भारतीय कंपनियों ने भी वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सकारात्मक नीतियां बनाई हैं। टाटा की अनेक कंपनियों ने नीति बना कर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों से कच्चा माल खरीदने और शिक्षा के विशेष प्रबंध कर अवसर की समानता बनाने की कोशिश की है। अब बजाज, महिंद्रा जैसी कंपनियां भी इसी राह पर बढ़ रही हैं। देश के अनेक महंगे प्राइवेट स्कूल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। कई तो उन्हें ठीक वही शिक्षा और सुविधाएं दे रहे हैं, जो मोटी फीस देने वाले छात्रों को मिल रही हैं। ऐसे अनेक प्रयास शिक्षा अधिकार कानून के अंतर्गत हमारे देश में हो रहे हैं।

केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी सामाजिक न्याय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले वर्षों में डिजिटल तकनीक, आधार कार्ड आदि का प्रयोग कर पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार की आशंकाओं को समाप्त किया जाएगा, बल्कि तकनीक का बेहतर प्रयोग कर लाभार्थियों को आसान और पारदर्शी व्यवस्था दी जाएगी। योगी सरकार द्वारा संचालित कक्षा छह से 12 तक के आश्रम पद्धति के आवासीय स्कूलों को सशक्त किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों से सहयोग और पार्टनरशिप विकसित की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आंबेडकर जी की कल्पना के अनुसार अवसर की समानता देने के लिए योगी सरकार द्वारा अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इसमें आनलाइन शिक्षा और क्लास-रूम शिक्षा का एक हाइब्रिड माडल बनाया गया है, जिसमें हर छात्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि बाबा साहब के विचारों के अनुरूप अवसर की समानता सचमुच बनाई जा सके।

गणतंत्र की अब तक की यात्रा में बहुत कुछ बदला है और अभी काफी कुछ हमें मिलकर बदलना है। सरकारें विकास की योजनाएं बनाती रहेंगी, पर समाज में एक-दूसरे की मानवीय स्वीकार्यता विकसित करने की भी जरूरत है। इसमें साहित्य, सिनेमा, मीडिया, इंटरनेट की भी भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बनेगी, जिसमें समाज और सरकार की पार्टनरशिप होगी और बाबा साहब की परिकल्पना के अनुसार हम अवसर की समानता वाले एक समरस एवं विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ेंगे।

(लेखक पूर्व आइपीएस और उप्र सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शक्ति की उपासना

शक्ति की उपासना भगवान भी करते हैं, देवता भी करते हैं और संत-महात्मा भी करते हैं। शक्ति की पूजा-अर्चना सभी मानव करते हैं, सभी विवेकवान करते हैं, सभी बुद्धिमान करते हैं और सभी चरित्रवान करते हैं। शक्ति की आराधना सैनिक करते हैं, सेनानायक करते हैं, व्यापारी करते हैं, श्रमिक करते हैं, छात्र करते हैं और राष्ट्रभक्त करते हैं। इस शक्ति की भक्ति प्रकृति का अभिनंदन है, नमन है और स्वागत है। शक्ति की स्तुति से मानव जीवन का कल्याण पथ प्रशस्त होता है। इस शक्ति का रहस्य बहुत गहरा है, जिसकी थाह नहीं है। शक्ति वस्तुतः मां स्वरूपा है। जिस प्रकार प्रकृति मां चराचर जगत की सृजक है, उसी तरह मातृशक्ति जीव की सर्जना है। इसलिए परमेश्वरी भी परमेश्वर की शक्ति है। मानव के अंदर शक्ति का प्रवाह होता है, वहीं शरीर के बाहर शक्ति का संचालन होता है। शक्ति के प्रवाह और संचालन का केंद्र हमारा आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है।

अपने आत्मा को शक्ति जानिए, शरीर को नहीं। फिर भी आत्मा की पूजा कोई नहीं करता, जबकि सब शरीर की पूजा करते हैं। कहा गया है कि जो शक्ति को नहीं पूजता, वह मृतक के समान है। इसलिए जीवन में शक्ति को धारण करना मानव का परम कर्तव्य भी है। प्राणी मात्र शक्ति के स्रोत, ऊर्जा के उद्गम और चेतना के प्रवाह से स्थिर है। शक्ति की उपस्थिति से ही धरती पर जीवन का अस्तित्व है। शक्ति है तो हम हैं, यह जगत है, सूर्य है, चंद्रमा है और तारामंडल है। कृषि, जीविका, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य और विद्या का हर अंश शक्ति का रूपांतरण ही है। संपूर्ण सकारात्मक कर्मभूमि में शक्ति का केंद्र रहता है, जो योग रूप में प्रगट होता है। माया भी शक्ति की ही छाया है और काया शक्ति की दाया मानिए। जब ज्ञान रूपेण माता समक्ष हों, तब कुछ भी रहस्यमय नहीं है। शक्ति के माता रूप को भजने से मानव को सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

डूब रहा है उल्कापिंडों का खजाना

मुकुल व्यास

अंटार्कटिका पर लाखों वर्षों से उल्कापिंडों की बमबारी होती रही है। इनमें से अधिकांश अंतरिक्ष चट्टानें बर्फ में डूब चुकी हैं

अंटार्कटिका में अंतरिक्ष से गिरने वाली शिलाओं का बहुमूल्य खजाना है। ये शिलाएं हमें उन परिस्थितियों के बारे में भी बताती हैं, जो सौरमंडल के शुरुआती विकास के समय मौजूद थीं। एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप हर साल 5,000 उल्कापिंड अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे डूब सकते हैं, जिससे विज्ञानी सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो सकते हैं। हजारों प्राचीन उल्कापिंड इस समय अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर या उसके ठीक नीचे बिखरे हुए हैं। नए अध्ययन से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश अंतरिक्ष शिलाएं अगले कुछ दशकों में हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण वे बर्फ में और अधिक नीचे धंस जाएंगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले कि वे हमेशा के लिए गायब हो जाएं, हमें उन्हें ढूंढ़ने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की जरूरत है।

अंटार्कटिका पर लाखों वर्षों से उल्कापिंडों की बमबारी होती रही है। इनमें से अधिकांश अंतरिक्ष चट्टानें पहले ही बर्फ में गहराई तक डूब चुकी हैं, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा जा सकेगा। अंटार्कटिका के नीले बर्फ क्षेत्र उल्कापिंडों की तलाश के लिए दुनिया में सबसे अच्छे स्थानों में गिने जाते हैं। अंटार्कटिका में अब तक लगभग 50,000 उल्कापिंड खोजे जा चुके हैं, जो दुनिया भर में अब तक एकत्र किए गए ज्ञात उल्कापिंडों का लगभग 60 प्रतिशत हैं। इनमें से अधिकांश अंतरिक्ष चट्टानों का व्यास एक इंच से भी कम है, लेकिन कुछ बड़ी हैं। शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में पिछले साल जनवरी में एक उल्कापिंड की खोज की जिसका वजन 7.7 किलोग्राम था, जो महाद्वीप पर अब तक पाई गई सबसे भारी अंतरिक्ष चट्टानों में से एक है।

इन अंतरिक्ष चट्टानों का विश्लेषण करने से शोधकर्ताओं को सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिल सकती है। अंटार्कटिका के उल्कापिंड विशेष रूप से उपयोगी हैं, क्योंकि वे बर्फ में अच्छी तरह से संरक्षित हैं। अन्य क्षेत्रों में गिरने वाले अधिकांश उल्कापिंड जमीन से टकराने के बाद जल्दी ही खनिजों, रोगाणुओं या लोगों से दूषित हो जाते हैं। अनुमान है कि अंटार्कटिका में नीली बर्फ वाले क्षेत्रों की सतह पर या उसके आस-पास 8,50,000 तक उल्कापिंड हो सकते हैं। जैसे-जैसे आने वाले दशकों में तापमान और बढ़ेगा और ज्यादा उल्कापिंड डूबने लगेंगे। शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी और अतिरिक्त गर्मी के बिना सदी के अंत तक लगभग एक चौथाई उल्कापिंड नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक गर्माहट वाले परिदृश्यों में तीन-चौथाई उल्कापिंडों का नुकसान हो सकता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

अपनी-अपनी डफली

लोकसभा चुनाव के लिए आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस समेत अलग-अलग दलों की ओर से चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम पर यह कहकर चुप्पी साध ली है कि वर्तमान सरकार में एक कमेटी पहले से बनी है उसे देखने के बाद कोई निर्णय लेंगे, लेकिन राजद ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम का वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ-साथ पूरे देश में स्कूलों एवं अस्पतालों को लेकर दिल्ली माडल लागू करने की बात की है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुडुचेरी को तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया है, पर दिल्ली को छोड़ दिया गया है। कांग्रेस की ओर से एमएसपी की गारंटी की बात तो कही गई है, लेकिन घोषणा पत्र समिति के एक सदस्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी तय नहीं कि कितनी फसलों पर देंगे, वहीं राजद ने 10 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वादा कर दिया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के लिए तो विशेष पैकेज की बात कही है, लेकिन बिहार को छोड़ दिया है, जिसकी बात राजद की ओर से की जा रही है। चुनावों में पासा फेंकने तक तो ठीक है, लेकिन एक मंच पर आकर अगर इन दलों के नेता अलग-अलग वादे करने लगें तो फिर क्या होगा?

एक साथ रहने का अधिकार

यूं तो पति और पत्नी की पोस्टिंग सामान्यतया एक ही जिले में करने के अनुरोध को मान लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो टिप्पणी की, उसके आधार पर कहा जा रहा है अब वह इसका अधिकार ही देने जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं। पति कोर्ट से मांग कर रहा था कि उसका ट्रांसफर उसकी पत्नी के जिले में कर दिया जाए। उस पर न्यायाधीश महोदय ने कहा कि पति-पत्नी को अलग रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यानी जीवनसाथी के साथ रहना राइट टू लिव टुगेदर के तहत आता है।

आधा कोटा

चुनावी राजनीति में तरह-तरह के समीकरण बनते रहते हैं। बिहार में लोकसभा की दो सीटें आजकल ऐसे ही समीकरण को लेकर चर्चा में हैं। राजनीति में जातीय हस्तक्षेप रखने वाले बिहार में टिकट बंटवारे में जातियों का कोटा अहम होता है। राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए छह सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर सामान्य जाति के प्रत्याशी नहीं उतारे जा सकते हैं, किंतु जातीय कोटा यहां भी निकाल लिया गया है। राजद ने आरक्षित सीट जमुई से अर्चना रविदास को टिकट दिया है, जिनकी शादी यादव जाति के मुकेश यादव से हुई है। लालू प्रसाद यादव ने आठ यादवों को राजद का टिकट दिया है, लेकिन लोग अर्चना को भी आधा यादव मानकर राजद में यादव कोटे की गिनती साढ़े आठ कर रहे हैं। अर्चना के पति मुकेश राजद के नेता हैं। इसी तरह चिराग पासवान ने समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को लोजपा (आर) का उम्मीदवार बनाया है। उन्हें भूमिहार कोटे में गिना जा रहा है, क्योंकि उनके पति शायन कुणाल की जाति भूमिहार है। बिहार में चर्चा हो रही है कि आरक्षित सीटों से भी यादव एवं भूमिहार के लिए आधा-आधा कोटा निकल आया है। लालू और चिराग की पार्टियों को इस कोटे के सहारे वोट की भी अपेक्षा है।

अब वह हमारे मंत्री कहां

हाल में एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत में किसी ने उन्हें यह बताया कि आपके मंत्री चुनाव में हार भी सकते हैं तो उन्होंने तपाक से कहा, अब वह हमारे मंत्री कहां हैं। उन्होंने छूटते ही यह भी कहा कि नई सरकार में उनके मंत्रालय का मंत्री कौन बनेगा, किसको पता। अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी कमोबेश अपने-अपने मंत्री के लिए यही राय रखते हैं। हालांकि ये अधिकारी मंत्री बदलने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने की नहीं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(10) रविवार, 14 अप्रैल, 2024 : चैत्र शुक्ल - 6 वि. 2081

ईश्वर भक्त के मन की शुद्धता परखता है

आतंक को जवाब

एक ऐसे समय जब पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने-पोसने में लगा हुआ है और जब-तब कश्मीर में उनकी घुसपैठ कराने की भी कोशिश करता रहता है, तब ऐसी किसी दो टूक बात की आवश्यकता थी कि आतंकियों को जवाब देने का कोई नियम नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी किसी नियम को नहीं मानते। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बयान देते हुए इसका भी उल्लेख किया कि किस तरह मुंबई में भीषण आतंकी हमले के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर तमाम विचार-विमर्श के बाद भी इस नतीजे पर पहुंची थी कि उसके विरुद्ध कोई कदम न उठाना ही बेहतर है। इस नतीजे पर पहुंचकर मनमोहन सरकार ने न केवल भारत की कमजोरी उजागर की थी, बल्कि पाकिस्तान के दुस्साहस को बढ़ाने का भी काम किया था। इसके नतीजे अच्छे नहीं हुए और भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले झेलने पड़े। पाकिस्तान के होश ठिकाने तब आए, जब पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इसके पहले भारतीय सेना सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुकी थी। यह सही है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते पाकिस्तान के दुस्साहस का दमन हुआ है, लेकिन उसने अभी अपनी जमीन पर चल रहे आतंक के उन अड्डों को बंद नहीं किया है, जहां जिहादी तैयार होते हैं और जो भारतीय सीमा में घुसपैठ की करते रहते हैं। कश्मीर में अभी भी आतंकी जब-तब सिर उठाते रहते हैं। ऐसे में उसे समय-समय पर चेताया जाना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि विदेश मंत्री के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ शब्दों में यह कह चुके हैं कि यदि आतंकी भारत में कोई हमला करके सीमा पार चले जाते हैं तो वहां भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहले रक्षा मंत्री और अब विदेश मंत्री की इन खरी बातों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि हाल में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने यह दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों को ठिकाने लगाया है। भारत आधिकारिक रूप से तो ऐसे किसी दावे की पुष्टि करने से रहा, लेकिन इससे बेहतर और कुछ नहीं कि पाकिस्तान यह समझने लगा है कि आतंकवाद के मामले में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की नीति बदल चुकी है और यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान ने ब्रिटिश समाचार पत्र के दावे का उल्लेख करते हुए अपना रोना भी रोया है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि विश्व को यह अच्छी तरह पता है कि वह आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का काम करता है। ऐसे में भारत के लिए यही उचित है कि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखे।

आग का खतरा

गर्मी में आग से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है, ताकि जान-माल की क्षति न हो। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें आग से भारी नुकसान हुआ है। शनिवार को भी दरभंगा के बहादुरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई, हालांकि उस पर काबू पा लिया गया। हाल ही में सासाराम में झोपड़ी में आग लगने से सात लोगों का निधन हो गया था। भागलपुर जिले के नवगछिया में भी आग से झुलसकर एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। पटना के जक्कनपुर मोहल्ले और पटना सिटी में भी आग से भारी नुकसान हुआ था। यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। अग्निशमन विभाग की ओर से इसके लिए अभियान भी चलाया जाता है। स्थानीय प्रशासन, नगर निकाय और ग्राम पंचायत के स्तर पर भी लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि अधिकतर घटनाएं शार्ट सर्किट के कारण होती हैं। जगह-जगह बिजली के तार मकड़जाल की तरह लटक रहे हैं, जो कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। पटना में कोर्ट परिसर में भी आग से अधिवक्ता समेत लिपिक को जान से हाथ धोना पड़ा था। जहां भी इस तरह की गड़बड़ी है, उसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। स्लम बस्तियों में विशेष रूप से इस तरह की घटना का खतरा बना रहता है, जहां बिजली के तार जैसे-तैसे घरों तक ले जाए जाते हैं। मार्केटिंग काम्पलेक्स, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, कार्यालय आदि में भी इसकी समय-समय पर जांच की जानी चाहिए कि वहां आग से सुरक्षा के लिए मानक के अनुरूप उपाय किए गए हैं या नहीं। लोगों को भी इसके प्रति स्वयं जागरूकता बरतनी होगी, क्योंकि एक चिंगारी कब विकराल रूप धारण कर ले, कहा नहीं जा सकता।

थोड़ी सी सावधानी से रोकी जा सकतीं अगलगी की घटनाएं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टेस्ला के भारतीय बाजार में आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है?

आज का सवाल
क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए?

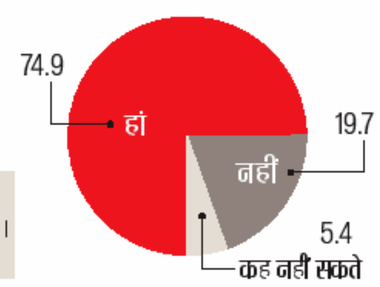

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

लोकतंत्र-संविधान के खात्मे का हौवा

संजय गुप्त

यदि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं तो इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह संविधान और लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं?

राहुल गांधी अब इस पर और अधिक जोर देने में लग गए हैं कि यदि मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान भी नहीं बचेगा। वह अपनी सभाओं में बार-बार कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हैं। लोकतंत्र और संविधान के खतरे में होने के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया कि क्या जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? उन्होंने कांग्रेस से यह प्रश्न भी किया कि यदि संविधान का अनुच्छेद 370 इतना ही अच्छा था तो उसे सारे देश में क्यों नहीं लागू किया गया? कांग्रेस के पास इसका शायद ही कोई जवाब हो।

1947 में जब भारत को आजादी मिली और संविधान सभा गठित हुई तो उसके 299 में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इस समिति में हिंदू महासभा की ओर से प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की, जिसने 1980 में भाजपा का रूप लिया। संविधान सभा में अनुच्छेद 370 का विरोध कई नेताओं ने किया। इनमें बाबा साहब आंबेडकर भी थे। संविधान में कई संशोधन उसके लागू होने के एक वर्ष के अंदर ही कर दिए गए, जिनमें से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने वाला भी था। यह विचित्र है कि आज कांग्रेस ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे में होने का सबसे अधिक शोर मचा रही है। जब संविधान में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने संबंधी अनुच्छेद 356 शामिल किया गया तो उसका विरोध हुआ। आंबेडकर जी ने इस अपेक्षा से इस अनुच्छेद को संविधान का हिस्सा बनाया कि इसके इस्तेमाल की नौबत कम ही आएगी, लेकिन सब जानते हैं कि नेहरू से लेकर नरसिंह राव के समय 356 का किस तरह मनमाना इस्तेमाल हुआ। पिछले वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बताया था कि कांग्रेस की सरकारों ने करीब 90 बार 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को गिराया। इंदिरा गांधी ने तो लगभग 50 बार 356 का इस्तेमाल किया। यह भी किसी से छिपा नहीं कि आपातकाल के दौरान किस तरह संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़े गए।

चूंकि कांग्रेस संविधान खत्म होने का शोर लगातार मचा रही है, इसलिए बीते दिनों प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि यदि आंबेडकर जी आ जाएं तो वह भी संविधान नहीं खत्म कर सकते। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लिए सबसे पवित्र किताब संविधान है और देश इससे ही चलेगा। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकल की शुरुआत में संसद के केंद्रीय

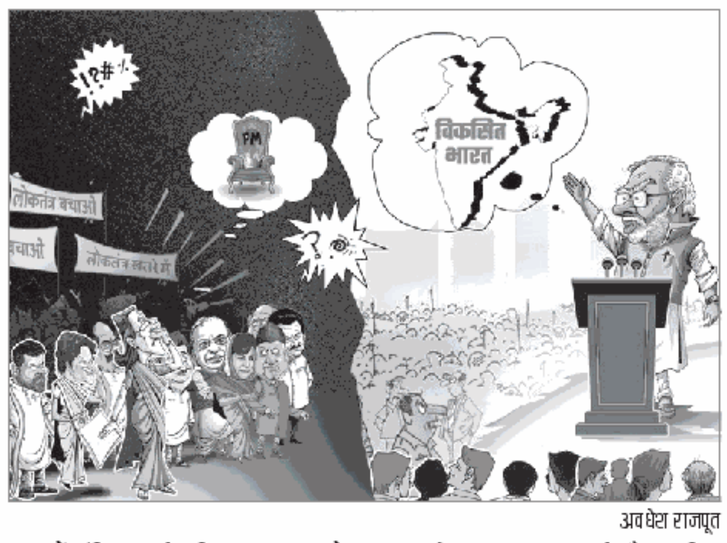

अवधेश राजपूत

कक्ष में संविधान की प्रति का नमन करके उसके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की थी। यदि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग चार सौ से अधिक सीटें पा भी जाए तो भी यह याद रहे कि ऐसा पहली बार नहीं होगा। राजीव गांधी के समय अकेले कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थीं। जब कोई दल पूर्ण बहुमत से सत्ता में आता है तो वह अपने एजेंडे को लागू करता ही है। ऐसा कांग्रेस ने भी किया और भाजपा ने भी। यदि मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने और अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं तो क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह संविधान और लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं?

राहुल गांधी इस आधार पर भी लोकतंत्र के खतरे में होने और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किए जाने का आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अपने लोगों को शीर्ष संस्थाओं में नियुक्त कर रही है। यह काम तो हर सरकार करती है। आखिर कांग्रेस या अन्य कोई दल यह अपेक्षा कैसे कर सकता है कि शीर्ष पदों पर नियुक्ति उसके हिसाब से हो? कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं के भगवाकरण का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या जो लोग भारतीयता से ओत-प्रोत हैं और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति शीर्ष पदों पर नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ जांच के आधार पर भी यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खतरा तो राजनीतिक भ्रष्टाचार से है, न कि भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई से। क्या देश में ऐसा कोई कानून है, जो यह कहता हो कि यदि कोई नेता किसी पद पर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ध्यान रहे यह कार्रवाई तभी आगे बढ़ती है, जब अदालतें ऐसे नेताओं को राहत नहीं देतीं। विडंबना यह है कि कांग्रेस के साथ मीडिया का एक हिस्सा भी लोकतंत्र-संविधान के खतरे में होने का हौवा खड़ा कर रहा है। यह हौवा खड़ा कर न्यायपालिका को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है और इसीलिए कुछ दिनों पहले 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह कहा कि एक खास समूह निहित स्वार्थों के चलते न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब तक संविधान में सौ से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। यह स्पष्ट है कि देश की आवश्यकतानुसार आगे भी होंगे। कांग्रेस को यह समझ आए तो अच्छा कि वह संविधान और लोकतंत्र के खत्म होने का जुमला उछालकर अपने पक्ष में कोई ठोस नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रही है। चूंकि वह जनता को लुभाने वाला नैरेटिव खड़ा करने में नाकाम है, इसलिए कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जो कांग्रेस नेता बचे हुए हैं, उनकी मजबूरी है कि वे राहुल गांधी के आरोपों को दोहराएं। यदि कांग्रेस कमजोर हो रही है तो इसका यह अर्थ नहीं कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कांग्रेस की कमजोरी का एक कारण क्षेत्रीय दलों से समझौते के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ना है। अधिकांश क्षेत्रीय दल या तो कांग्रेस से टूट कर निकले हैं या फिर कांग्रेस विरोध की राजनीति से उपजे हैं। आज उनमें से अनेक उसके साथ अवश्य हैं, लेकिन वे उसकी ही जड़ें काट रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस की तरह परिवारवादी हैं और वे अपने दल को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं। ऐसे परिवारवादी दल तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ही हैं।

response@jagran.com

साकार हो रहे बाबा साहब के सपने

असीम अरुण

आंबेडकर जी को याद करते समय यह भी जानने का समय है कि हम कितने समावेशी बन सके हैं?

आज बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती मनाते समय हमारे पास सामाजिक न्याय की चुनौतियों के विषय में सोचने और नई अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन की बदली स्थिति में आगे के विकल्प तलाशने के बारे में सोचने का भी अवसर है। आंबेडकर जी द्वारा संविधान में सामाजिक न्याय का जो खाका बनाया गया, वह उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित था। उस समय सामाजिक स्तर पर भेदभाव की स्थिति यह थी कि जाति के आधार अस्पृश्यता और तिरस्कार लोगों के सामान्य व्यवहार में शामिल था। अधिकतर शिक्षा सरकारी क्षेत्र में थी और आर्थिक अवसर भी सरकारी नौकरियों में अधिक थे। इनमें वंचित तबकों को भागीदारी दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ तो मिला, पर असमानता पूरी तरह दूर नहीं हो सकी, क्योंकि आरक्षण आधारित अवसरों का लाभ सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को सामान रूप से नहीं मिल सका। प्रारंभ में सामाजिक न्याय के लाभ के पात्र केवल अनुसूचित जातियां और जनजातियां थीं। बाद में अन्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण के दायरे मे लाया गया। अब ट्रांस-जेंडर के कल्याण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष में बाबा साहब के सिद्धांतों को संजोते हुए आगे का रास्ता तय करने की जरूरत है। इस पर शोध की आवश्यकता है कि सामाजिक भेदभाव की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका आकलन करने की भी आवश्यकता है कि क्या किरायेदार तय करते समय भेदभाव होता है? क्या महिलाओं को उसी काम के लिए बराबर वेतन मिलता है, जो काम पुरुष करते हैं? ट्रांस-जेंडर लोग यह तो महसूस नहीं करते कि बगल में बैठने वाले लोग उनसे हिचकते-कतराते हैं? यह देखने का भी अवसर है कि अलग दिखने या भिन्न कपड़े पहनने वालों को स्वीकारा जाता है या नहीं? जिस रूप में बाबा साहब ने अस्पृश्यता का अनुभव किया था, वह तो काफी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन सीवर में घुसकर सफाई करने जैसी कुव्यवस्था आज भी मौजूद है और इसे खत्म करना एक चुनौती बना हुई है। आज यह भी जानने-समझने

प्रेरणा के स्रोत बन रहे बाबा साहब के विचार ● एएनआइ

का समय है कि हम कितने समावेशी बन सके हैं? रोटी-बेटी के रिश्ते बढ़ाने में हम कहां तक पहुंचे हैं? एक-दूसरे की विविधता स्वीकारने और बराबरी का स्थान देने में हम कितने सफल हुए और इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे?

वर्तमान समय कुछ रोचक परिवर्तनों का अनुसरण करने और उनका अध्ययन करने का है। कई देशों में 'एफरमेटिव एक्शन' यानी सकारात्मक पहल के जरिये विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कारण हमें अमेरिका के विभिन्न संस्थानों और यहां तक कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में महिलाएं या अश्वेत दिखते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिनिधित्व देने की विस्तृत नीति है। यह नीति अन्य पश्चिमी देशों में भी है। इन देशों में शिक्षण संस्थान और अन्य प्रतिष्ठानों में भी अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कुछ इसी राह पर चलते हुए कुछ भारतीय कंपनियों ने भी वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सकारात्मक नीतियां बनाई हैं। टाटा की अनेक कंपनियों ने नीति बना कर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों से कच्चा माल खरीदने और शिक्षा के विशेष प्रबंध कर अवसर की समानता बनाने की कोशिश की है। अब बजाज, महिंद्रा जैसी कंपनियां भी इसी राह पर बढ़ रही हैं। देश के अनेक महंगे प्राइवेट स्कूल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। कई तो उन्हें ठीक वही शिक्षा और सुविधाएं दे रहे हैं, जो मोटी फीस देने वाले छात्रों को मिल रही हैं। ऐसे अनेक प्रयास शिक्षा अधिकार कानून के अंतर्गत हमारे देश में हो रहे हैं।

केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी सामाजिक न्याय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले वर्षों में डिजिटल तकनीक, आधार कार्ड आदि का प्रयोग कर पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार की आशंकाओं को समाप्त किया जाएगा, बल्कि तकनीक का बेहतर प्रयोग कर लाभार्थियों को आसान और पारदर्शी व्यवस्था दी जाएगी। योगी सरकार द्वारा संचालित कक्षा छह से 12 तक के आश्रम पद्धति के आवासीय स्कूलों को सशक्त किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों से सहयोग और पार्टनरशिप विकसित की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आंबेडकर जी की कल्पना के अनुसार अवसर की समानता देने के लिए योगी सरकार द्वारा अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इसमें आनलाइन शिक्षा और क्लास-रूम शिक्षा का एक हाइब्रिड माडल बनाया गया है, जिसमें हर छात्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग की भूमिका को कम किया जा सके और बाबा साहब के विचारों के अनुरूप अवसर की समानता सचमुच बनाई जा सके।

गणतंत्र की अब तक की यात्रा में बहुत कुछ बदला है और अभी काफी कुछ हमें मिलकर बदलना है। सरकारें विकास की योजनाएं बनाती रहेंगी, पर समाज में एक-दूसरे की मानवीय स्वीकार्यता विकसित करने की भी जरूरत है। इसमें साहित्य, सिनेमा, मीडिया, इंटरनेट की भी भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बनेगी, जिसमें समाज और सरकार की पार्टनरशिप होगी और बाबा साहब की परिकल्पना के अनुसार हम अवसर की समानता वाले एक समरस एवं विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ेंगे।

(लेखक पूर्व आइपीएस और उप्र सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शक्ति की उपासना

शक्ति की उपासना भगवान भी करते हैं, देवता भी करते हैं और संत-महात्मा भी करते हैं। शक्ति की पूजा-अर्चना सभी मानव करते हैं, सभी विवेकवान करते हैं, सभी बुद्धिमान करते हैं और सभी चरित्रवान करते हैं। शक्ति की आराधना सैनिक करते हैं, सेनानायक करते हैं, व्यापारी करते हैं, श्रमिक करते हैं, छात्र करते हैं और राष्ट्रभक्त करते हैं। इस शक्ति की भक्ति प्रकृति का अभिनंदन है, नमन है और स्वागत है। शक्ति की स्तुति से मानव जीवन का कल्याण पथ प्रशस्त होता है। इस शक्ति का रहस्य बहुत गहरा है, जिसकी थाह नहीं है। शक्ति वस्तुतः मां स्वरूपा है। जिस प्रकार प्रकृति मां चराचर जगत की सृजक है, उसी तरह मातृशक्ति जीव की सर्जना है। इसलिए परमेश्वरी भी परमेश्वर की शक्ति है। मानव के अंदर शक्ति का प्रवाह होता है, वहीं शरीर के बाहर शक्ति का संचालन होता है। शक्ति के प्रवाह और संचालन का केंद्र हमारा आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है।

अपने आत्मा को शक्ति जानिए, शरीर को नहीं। फिर भी आत्मा की पूजा कोई नहीं करता, जबकि सब शरीर की पूजा करते हैं। कहा गया है कि जो शक्ति को नहीं पूजता, वह मृतक के समान है। इसलिए जीवन में शक्ति को धारण करना मानव का परम कर्तव्य भी है। प्राणी मात्र शक्ति के स्रोत, ऊर्जा के उद्गम और चेतना के प्रवाह से स्थिर है। शक्ति की उपस्थिति से ही धरती पर जीवन का अस्तित्व है। शक्ति है तो हम हैं, यह जगत है, सूर्य है, चंद्रमा है और तारामंडल है।

कृषि, जीविका, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य और विद्या का हर अंश शक्ति का रूपांतरण ही है। संपूर्ण सकारात्मक कर्मभूमि में शक्ति का केंद्र रहता है, जो योग रूप में प्रगट होता है। माया भी शक्ति की ही छाया है और काया शक्ति की दया मानिए। जब ज्ञान रूपेण माता समक्ष हों, तब कुछ भी रहस्यमय नहीं है। यह लोक परलोक शक्ति का दर्शन है। शक्ति के माता रूप को भजने से मानव को सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

अपनी-अपनी डफली

लोकसभा चुनाव के लिए आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस समेत अलग-अलग दलों की ओर से चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम पर यह कहकर चुप्पी साध ली है कि वर्तमान सरकार में एक कमेटी पहले से बनी है उसे देखने के बाद कोई निर्णय लेंगे, लेकिन राजद ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम का वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ-साथ पूरे देश में स्कूलों एवं अस्पतालों को लेकर दिल्ली माडल लागू करने की बात की है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुडुचेरी को तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया है, पर दिल्ली को छोड़ दिया गया है। कांग्रेस की ओर से एमएसपी की गारंटी की बात तो कही गई है, लेकिन घोषणा पत्र समिति के एक सदस्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी तय नहीं कि कितनी फसलों पर देंगे, वहीं राजद ने 10 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वादा कर दिया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के लिए तो विशेष पैकेज की बात कही है, लेकिन बिहार को छोड़ दिया है, जिसकी बात राजद की ओर से की जा रही है। चुनावों में पासा फेंकने तक तो ठीक है, लेकिन एक मंच पर आकर अगर इन दलों के नेता अलग-अलग वादे करने लगें तो फिर क्या होगा?

राजरंग

एक साथ रहने का अधिकार

यूं तो पति और पत्नि की पोस्टिंग सामान्यतया एक ही जिले में करने के अनुरोध को मान लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो टिप्पणी की, उसके आधार पर कहा जा रहा है अब वह इसका अधिकार ही देने जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं। पति कोर्ट से मांग कर रहा था कि उसका ट्रांसफर उसकी पत्नी के जिले में कर दिया जाए। उस पर न्यायाधीश महोदय ने कहा कि पति-पत्नी को अलग रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यानी जीवनसाथी के साथ रहना राइट टू लिव टुगेदर के तहत आता है।

आधा कोटा

चुनावी राजनीति में तरह-तरह के समीकरण बनते रहते हैं। बिहार में लोकसभा की दो सीटें आजकल ऐसे ही समीकरण को लेकर चर्चा में हैं। राजनीति में जातीय हस्तक्षेप रखने वाले बिहार में टिकट बंटवारे में जातियों का कोटा अहम होता है। राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए छह सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर सामान्य जाति के प्रत्याशी नहीं उतारे जा सकते हैं, किंतु जातीय कोटा यहां भी निकाल लिया गया है। राजद ने आरक्षित सीट जमुई से अर्चना रविदास को टिकट दिया है, जिनकी शादी यादव जाति के मुकेश यादव से हुई है। लालू प्रसाद यादव ने आठ यादवों को राजद का टिकट दिया है, लेकिन लोग अर्चना को भी आधा यादव मानकर राजद में यादव कोटे की गिनती साढ़े आठ कर रहे हैं। अर्चना के पति मुकेश राजद के नेता हैं। इसी तरह चिराग पासवान ने समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को लोजपा (आर) का उम्मीदवार बनाया है। उन्हें भूमिहार कोटे में गिना जा रहा है, क्योंकि उनके पति शायन कुणाल की जाति भूमिहार है। बिहार में चर्चा हो रही है कि आरक्षित सीटों से भी यादव एवं भूमिहार के लिए आधा-आधा कोटा निकल आया है। लालू और चिराग की पार्टियों को इस कोटे के सहारे वोट की भी अपेक्षा है।

अब वह हमारे मंत्री कहां

हाल में एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत में किसी ने उन्हें यह बताया कि आपके मंत्री चुनाव में हार भी सकते हैं तो उन्होंने तपाक से कहा, अब वह हमारे मंत्री कहां हैं। उन्होंने छूटते ही यह भी कहा कि नई सरकार में उनके मंत्रालय का मंत्री कौन बनेगा, किसको पता। अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी कमोबेश अपने-अपने मंत्री के लिए यही राय रखते हैं। हालांकि ये अधिकारी मंत्री बदलने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने की नहीं।

पोस्ट

मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मथीन अहमद ताहा रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के मुख्य आरोपित हैं। हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि हमारे समुदाय में कट्टरपंथीकरण की समस्या है। समस्या को स्वीकार करना ही उसके समाधान का पहला कदम है।

उमर गाजी@OmerGhazi2

अमेरिका-कनाडा में भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या की धमकी देना बोलने की आजादी है, लेकिन यह तब अपराध बन जाता है, जब ऐसी धमकी कोई उनके अपने नागरिकों को देता है।

सुशांत सरीन@sushantsareen

यह सच में अद्भुत भारत है। मैंने तत्काल सेवा के जरिये अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। बीस घंटे बाद मुझे नया पासपोर्ट मिल गया। भारत सरकार को साधुवाद।

सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

आम भारतीयों का एक विचित्र भाग्यवादी चरित्र यह है कि वे खराब स्थिति को भी अपनी नियति मान कर संतोष के साथ जीवन गुजारते हैं और उन्हें उसमें बदलाव की खास जरूरत महसूस नहीं होती। उन्हें किसी से शिकायत भी नहीं होती। इसीलिए बेरोजगारी, महंगाई उनके लिए मुद्दे नहीं हैं!

कमर वहीद नकवी@qwnaqvi

जनपथ

मौसम का भी देखिए बदल रहा है रंग,
इसने भी अपना लिया नेताओं सा ढंग।
नेताओं सा ढंग कभी ये गरजे-बरसे,
कहीं दिखाए बाढ़ कहीं जल को जन तरसे।
इसी चुनावी काल दिखाए यह अपना दम,
बदले रोज मिजाज आजकल कातिल मौसम।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 3

****

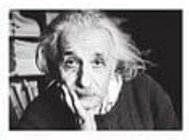

नाभिकीय शक्ति पानी को उबालने का सबसे खतरनाक और नारकीय तरीका है।
- अल्बर्ट आइंस्टीन

रूस के जासूस पूरी दुनिया में कुख्यात रहे हैं। अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इन्हीं रूसी जासूसों की मौजूदगी पर नई चर्चाएं हैं। मगर इससे ज्यादा सनसनीखेज किस्सा है, हिटलर के न्यूक्लियर बम का। कहते हैं कि इस बम की तैयारी से अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बड़ी मदद मिली थी।

हिटलर का वह रहस्य

अमेरिका और रूस के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है। चुनाव की तरफ बढ़ रहे राष्ट्रपति जो बाइडन का दफ्तर इस खबर से सकते में है कि रूस एग्जॉटिक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को तबाह कर देगा।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

22 फरवरी, 2023 को यूक्रेन पर रूस के हमले की पहली बरसी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस अमेरिका के साथ स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित कर रहा है। जनसंहारक हथियारों की होड़ रोकने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच संधियों में यह आखिरी सक्रिय संधि थी, पुतिन ने जिसे लागू करने से मना कर दिया।

इसके ठीक पांच माह बाद अमेरिका ने अपनी अगली पीढ़ी के मिसाइल कार्यक्रम को रफ्तार दी और इसी जनवरी में अत्याधुनिक सेंटिनल मिसाइल के लिए मोटर का परीक्षण सफल हो गया।

चुनाव की तरफ बढ़ रहे राष्ट्रपति जो बाइडन का दफ्तर इस खबर से सकते में है कि रूस एग्जॉटिक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को तबाह कर देगा।

1960 और 1980 के दशक में अमेरिका की राजनीति को चलाने वाले सोवियत हॉक्स यानी रूस से आर-पार करने वाले नेताओं की नई पीढ़ी बाइडन को घेर रही है। संयोग ही है कि विनाशक हथियारों की नई होड़ की खबरें उस वक्त आईं, जब क्रिस्टोफर नोलन की ऑस्कर विजेता भव्य फिल्म *ओपनहाइमर* के जरिये नई पीढ़ी नाभिकीय हथियारों की सियासत और बहस से नया राब्ता कायम कर रही है।

अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में रूस के जासूसों की मौजूदगी पर नई चर्चाएं हैं। मगर इससे ज्यादा सनसनीखेज किस्सा है, हिटलर के न्यूक्लियर बम का। कहते हैं कि इस बम की तैयारी से अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बड़ी मदद मिली थी।

तो संभालिए अपनी सीट टाइम मशीन में, वक्त है बीसवीं सदी का। दूसरे विश्वयुद्ध की मार-काट मची है। आइए चलते हैं, जर्मनी के ऐतिहासिक शहर लिपजिग। बमों की बात शुरू करें, उससे पहले आप लिपजिग में संगीत सुन लीजिए। महान संगीतकार रिचर्ड वैगनर, जोहान सेबेस्टियन बाख, मेंडेलसोहन बार्थोल्डी, शुमान और महलर की अमर धुनें इस शहर की पहचान हैं।

टाइम मशीन
अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ■ हर पखवाड़े

लिपजिग से बर्लिन, जर्मन इतिहास के गढ़ हैम्बर्ग से होते हुए हम कुमेसडर्फ आ गए हैं। बर्लिन के करीब इस कस्बे में नात्जी सेना का एक हथियार डिपो है, जिसमें नात्जी एटम बम की तैयारी चल रही है।

अब आप 1939 के बर्लिन में हैं। नीचे वह बड़ी इमारत है, बर्लिन का कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। यहां जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन यूरेनियम के एटॉमिक न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन बरसा रहे हैं। उन्हें पता चला कि यूआई 235 यानी यूरेनियम का न्यूक्लियस फटता है, तो जबर्दस्त ऊर्जा निकलती है। इन वैज्ञानिकों को न्यूक्लियर फिजन यानी बम का फॉर्मूला मिल गया है।

गौर से देखिए, क्या आप पहचान पा रहे हैं इस शख्सियत को?

ये हैं दुनिया के प्रख्यात भौतिकविद वर्नर हाइजेनबर्ग। वही क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी सिद्धांत वाले वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्हें 1932 में नोबेल पुरस्कार मिला था।

हाइजेनबर्ग कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के प्रमुख हैं और न्यूक्लियर फिजन की तकनीक को प्रयोग में लाने का प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। प्रोजेक्ट का नाम है यूरेनियम क्लब। लिपजिग की टेक्सटाइल केमिकल रिसर्च में यूरेनियम अयस्क से यूरेनियम निकाला गया।

ओरियनबर्ग में हैवी वाटर पर शोध हुआ। कुमेसडर्फ गोटो में यूरेनियम इनरिचमेंट की कोशिश हुई। सही समझे आप, हाइजेनबर्ग की टीम हथियार स्तर के यूरेनियम को तैयार करने की कोशिश कर रही है। उनके पास बम बनाने के साधन नहीं हैं, मगर शोध काफी आगे तक हो गया था।

नात्जी एटम बम पर लिखने वाले कहते हैं कि हाइजेनबर्ग इस परियोजना को गुप्त रूप से चला रहे थे। यूरेनियम क्लब को हिटलर का समर्थन नहीं था। इसी बीच टाइम मशीन में आपको खबर मिलने लगी है कि हिटलर की हार शुरू हो गई है। यूरोप में हिटलर के खिलाफ मित्र सेनाओं की अगुआई करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को हाइजेनबर्ग के यूरेनियम क्लब का पता चल गया है।

अब शुरू होता है, रोमांच का सफर।

हिटलर से जंग के बीच अमेरिका ने एल्सॉस मिशन बनाकर अपने सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों को नात्जी एटम बम की जासूसी पर लगा दिया। अमेरिकी सेना में काउंटर इंटेलिजेंस के मुखिया कर्नल बोरिस पाश इस मिशन के मुखिया बनाए गए।

अब हम दक्षिण-पश्चिम जर्मनी के कस्बे हाइगरलोश में हैं। हिटलर की हार तय देखकर वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग अपनी गोपनीय नाभिकीय प्रयोगशाला को यहां ले आए हैं। वे न्यूक्लियर रिएक्शन का अपना आठवां प्रयोग करना चाहते थे।

यह क्या...

अमेरिकी कर्नल बोरिस पाश ने प्रयोगशाला पर छापा मार दिया है। जर्मन न्यूक्लियर रिएक्टर का शुरुआती मॉडल अमेरिका के हाथ लग गया। वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग गिरफ्तार हो गए हैं।

अमेरिका का एटम बम तब तक लगभग बन गया था। अलबत्ता एल्सॉस मिशन से मिली सूचनाओं ने युद्ध के बाद अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट और बाद के नाभिकीय प्रयोगों को समृद्ध किया। हाइजेनबर्ग को जनवरी, 1946 में ब्रिटिश अधिकारियों ने रिहा कर दिया।

टाइम मशीन के सफर का एक और रोमांचक पड़ाव अभी बाकी है। इसके लिए हम चलते हैं 2013 में। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वैज्ञानिक समुदाय हाइजेनबर्ग के प्रयोग में इस्तेमाल हुए यूरेनियम की तलाश में था। बताते हैं कि वर्नर हाइजेनबर्ग यूरेनियम ने 664 क्यूब्स का इस्तेमाल किया था। इनमें एक क्यूब 2013 में यूनिवर्सिटी मैरीलैंड के वैज्ञानिक टिमोथी कोएथ के पास पहुंचा। *कॉसमॉस* मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि कोएथ को एक पैकेट मिला, जिस पर लिखा था, "Taken from the reactor that Hitler tried to build. Gift of Ninninger."

कोएथ को पता चला कि रॉबर्ट जे निनजिंगर को 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मरे हिल एरिया का प्रॉपर्टी मैनेजर बनाया गया था। क्या इन्हीं निनजिंगर ने पैकेट भेजा था? यह रहस्य आज तक नहीं खुला। हमारी टाइम मशीन अब वाशिंगटन की तरफ बढ़ रही है। आपकी सीट के सामने की स्क्रीन पर दिसंबर, 2022 की एक सुर्खी तैर रही है। जो बाइडन की सरकार ने रॉबर्ट जो ओपनहाइमर पर चल रही जांच को वापस ले लिया। जासूसी के शक में एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1954 से उनकी जांच कर रहा था। 1967 में ओपनहाइमर नहीं रहे। मगर शक की जांच जारी थी। खुफिया दस्तावेजों ने यह तो सिद्ध किया कि अमेरिकी एटम बम के रहस्य रूस को पहुंचाए गए थे। मगर ओपनहाइमर जासूस नहीं थे, जासूसी तो ओपनहाइमर के सहयोगी वैज्ञानिक कार्ल फुक्स ने की थी। कहते हैं, इन्हीं सूचनाओं की मदद से सोवियत रूस ने 29 अगस्त, 1949 के कजाकिस्तान के सेमपलाटिंस्क न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया था।

इसके बाद शुरू हुई न्यूक्लियर हथियारों की होड़।

आज का सफर यहीं तक, फिर मिलते हैं जल्द...

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

ऋषियों ने पृथु को बताया कि प्रकृति का यही नियम है कि राजा न हो तो भूमि में कुछ नहीं उगता। इसीलिए संसार की यह दशा हो रही है। यह सुनकर पृथु ने अस्त्र-शस्त्र उठाया और भूलोक खोदने को तत्पर हो गया।

कैसे मिला 'पृथ्वी' को अपना नाम

ध्रुव के वंशज राजा अंग का पूरी धरती पर शासन था। वह बहुत धार्मिक और वेदों के ज्ञाता थे। परंतु उनका पुत्र वेन अत्यंत उद्दंड था। उसका धर्म, नैतिकता और वैदिक संस्कारों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह बड़ा हुआ, तो अत्याचारी हो गया। ऋषि-मुनियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वेन के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी उद्दंडता बढ़ती गई। आखिरकार, ऋषियों ने निर्णय लिया कि वेन का जीवित रहना समाज के लिए घातक होगा, इसलिए उन्होंने अपने तपोबल से वेन को मार डाला।

धूप आने दो

वेन की मृत्यु से धरती अनाचार से मुक्त तो हो गई, किंतु उसका कोई शासक नहीं रहा। वेन निस्संतान था, इसलिए ऋषियों ने वेन के शव को मथकर संतान उत्पन्न करने का निश्चय किया। ऋषियों ने वेन की दाहिनी जांघ को मथा, तो एक अत्यंत कुरूप प्राणी प्रकट हुआ। उससे निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। फिर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को मथा, तो एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम पृथु रखा गया।

पृथु बड़ा हुआ, तो अत्यंत बलशाली और ओजवान बन गया। उसने अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण कर लिया। परंतु उसका राज्याभिषेक नहीं हो पाया था। एक दिन पृथु को पता लगा कि पृथ्वी ने भोजन देना बंद कर दिया, जिससे समस्त प्राणी-जगत पर संकट के बादल मंडराने लगे।

ऋषियों ने पृथु को बताया कि प्रकृति का यही नियम है कि राजा न हो, तो भूमि में कुछ नहीं उगता। इसीलिए संसार की यह दशा हो रही है। भूलोक ने सबकुछ भीतर छिपा रखा है। यह सुनकर पृथु ने अपना अस्त्र-शस्त्र उठाया और भूलोक को खोदकर उसके भीतर से भोजन निकालने को तत्पर हो गया। भूलोक ने पृथु का क्रोध देखा, तो भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके भागना शुरू कर दिया। परंतु पृथु ने गाय रूपी भूलोक का पीछा नहीं छोड़ा। वह निरंतर गाय को मारने की धमकी देता रहा।

आखिर में गाय ने पृथु से कहा, 'मैं तुम्हारी मां के समान हूं। मुझे मार दोगे, तो मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है।'

पृथु ने कहा, 'आपका कर्तव्य संसार का पोषण करना है। आपकी तरह सब कर्तव्य त्याग देंगे तो ब्रह्मांड का क्या होगा? यदि आप संसार की रक्षा नही करेंगी, तो मैं भी आपकी रक्षा नहीं करूंगा।'

इस पर गाय बोली, 'प्रकृति का नियम है कि राजा न हो, तो मैं भोजन नहीं दे सकती। वेन की मृत्यु के बाद कोई राजा नहीं बना, इसलिए मैंने भोजन देना छोड़ दिया। यदि आप राजा बन जाएंगे, तो मैं फिर से भोजन देने लगूंगी।'

यह सुनकर पृथु ने कहा, 'भोजन के लिए प्रजा का राजा पर निर्भर होना सही बात नहीं है। इसलिए इसका विकल्प खोजना होगा।'

पृथु ने इस समस्या पर गहन सोच-विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में दोबारा भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अभी तक धरती स्वतः भोजन देती थी, परंतु पृथु को महसूस हुआ कि मनुष्य को धरती के गर्भ से स्वयं भोजन प्राप्त करना सीखना होगा। इसका लाभ यह था कि भूलोक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्नादि के अतिरिक्त मनुष्य अपने पुरुषार्थ से भी पृथ्वी से भोजन पैदा कर सकेगा, ताकि भोजन का कभी अभाव न हो।

इस विचार से पृथु को बड़ा संतोष हुआ और उसने तुरंत इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया। कहते हैं, पृथु ने अपने धनुष की नोंक से समस्त धरती को समतल कर दिया और भूमि के समतल होने से सर्वत्र मैदान तैयार होने लगे। इसके बाद पृथु ने खेत-खलिहान बना दिए और यहां से कृषि का आरंभ हुआ। मनुष्य जाति, जो अब तक पशु-पालन और आखेट से काम चलाती थी, अब कृषक की भूमिका में आ गई थी। कृषि का आरंभ हुआ, तो सर्वत्र अन्न और धान की फसलें लहलहाने लगीं।

इस तरह, महाराज पृथु ने अपने श्रम और संकल्प से धरती का स्वरूप बदल दिया। पृथु के इसी योगदान के चलते उनके नाम पर धरती को नाम मिला-पृथ्वी। ■

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।।

अर्थात जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सबकुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं।

- भीष्म पर्व, गीता 5/16
(अर्जुन के प्रति साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का गीतोपदेश)

प्रस्तुति : **विवेक चौरसिया**

वे सूरज को हराने की तैयारी में हैं

क्रिस्टोफर फ्लेवेले
न्यूयॉर्क टाइम्स

प्रचंड गर्मी जिस तरह से हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, कैलिफोर्निया प्रयोग उम्मीद की आखिरी किरण बन गया है।

सुबह नौ बजे से थोड़ा पहले का वक्त रहा होगा। मैथ्यू गैलेली नामक एक इंजीनियर ने, जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में एक सेवामुक्त विमानवाहक पोत के डेक पर बैठा था, एक स्विच को ऑन किया। कुछ ही सेकंड बाद बर्फ बनाने वाली मशीन जैसा दिखने वाला एक उपकरण गड़गड़ाने लगा। मशीन के मुंह से निकले छोटे एरोसोल कणों की एक महीन धुंध हवा में मीलों दूर तक फैल गई। यह बादलों को ताकत देने और सूर्य की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजने के लिए अमेरिका में किए जा रहे एक प्रयोग का पहला आउटडोर परीक्षण था। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो हम अपने ग्रह को ठंडा रख सकेंगे। मनुष्य जिस गति से वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साइड को पंप कर रहे हैं, हम पृथ्वी के तापमान को औद्योगिक समय की तुलना में डेढ़ डिग्री सेल्सियस के सुरक्षित स्तर पर रखने के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की टीम के प्रमुख वैज्ञानिक रॉबर्ट वुड कहते हैं, 'हर साल हमारे पास तापमान बढ़ने के नए रिकॉर्ड होते हैं, जो हमें इनसे निपटने के लिए नए उपायों की खोज के लिए प्रेरित करते हैं।' नए बादल पैदा कर सौर ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में भेजना इन्हीं विचारों में से एक है, जिसमें खतरनाक रसायनों के बजाय समुद्री नमक आधारित एरोसोल उपयोग में लाए जा रहे हैं। हालांकि प्रकृति में हस्तक्षेप का यह विचार इतना विवादास्पद है कि बाइडन प्रशासन ने भी इस कैलिफोर्निया प्रयोग से दूरी बनाई हुई है।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पर्यावरणीय वैज्ञानिक सारा डोहेर्टी कहती हैं कि इस तरह प्राकृतिक तापमान से छेड़छाड़ से समुद्रों का तापमान भी बदलेगा, जिससे समुद्री जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। दरअसल, तापमान कम करने के लिए इस प्रयोग का सुझाव सबसे पहले ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी जॉन लैथम ने दिया था। अपने पुत्र के साथ एक यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि बादल ऊपर की ओर चमकदार और नीचे की तरफ स्याह होते हैं। इस आधार पर उन्होंने टॉमे इफेक्ट नामक वैज्ञानिक संकल्पना रखी, जिसके अनुसार, बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे कण, कम मात्रा वाले बड़े-बड़े कणों की तुलना में सूर्य की ज्यादा रोशनी को परावर्तित कर सकते हैं। सूरज का प्रकाश धरती पर टकरा कर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, लेकिन जब वातावरण में प्रदूषक कण ज्यादा हो जाते हैं, तो वे सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं, जिससे ग्रह गर्म होने लगता है। अब कैलिफोर्निया प्रयोग जिन ऐरोसॉल का प्रयोग कर रहा है, वे इन प्रदूषक कणों से कितना अलग ढंग से व्यवहार करेंगे, प्रयोग की सफलता इसी पर निर्भर करेगी।

©The New York Times 2024

READ & WRITE

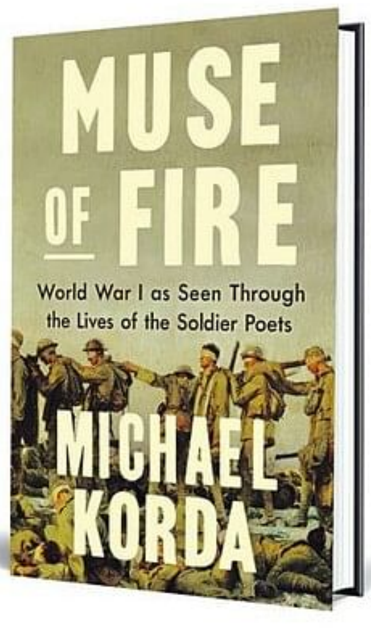

म्यूज ऑफ फायर
वर्ल्ड वार1 एज सीन थ्रू द लाइव्स ऑफ द सोल्जर पोएट्स

लेखक : माइकल कोर्डा

प्रकाशक : लाइवराइट पब्लिशिंग कॉरपोरेशन
मूल्य : 2426 रुपये
हार्डकवर

वे सैनिक जो कवि थे

हिंसा का निषेध करती यह किताब बताती है कि प्रथम विश्वयुद्ध ने कितनी संभावनाशील काव्य प्रतिभाओं को असमय ही रौंद दिया। हिंसा के विरुद्ध लिखी गई इन कवियों की कविताएं इसलिए भी अमर हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ने युद्धभूमि में अपने प्राणों की बलि देकर मानवता का अमिट संदेश दिया है।

खुद भूखी पीढ़ी से जुड़े और *हीरो ऐंड एलोन* जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक माइकल कोर्डा की यह किताब प्रथम विश्वयुद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ कवियों के त्रासद जीवन के जरिये इसमें वह युद्ध की भीषणता के बारे में बताते हैं। मोर्चे पर युद्ध लड़ने आए ये सैनिक वस्तुतः कवि थे और अपने समय के नायक भी। कोर्डा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में कविताओं का सार्वजनिक जीवन में बड़ा प्रभाव था, और ये युद्धकाल में सेंसरशिप के दायरे में भी नहीं आती थीं।

इस किताब में कोर्डा कुल छह युवा कवियों- रुपर्ट ब्रुक, रॉबर्ट ग्रेव्स, विल्फ्रेड ओवन, आइजक रोजेनबर्ग, सिग्फ्राइड सैसून और एलन सीगर का जिक्र करते हैं। इनमें से ज्यादातर कवि समृद्ध वर्ग से आते थे, और कुछ का तो विंस्टन चर्चिल से परिचय भी था। हालांकि रोजेनबर्ग इसके अपवाद थे। रूस के प्रवासी यहूदी परिवार में जन्मे बेहद गरीब रोजेनबर्ग की प्रतिभा की पहचान बेशक बचपन में हो गई थी, लेकिन आर्थिक मजबूरी उन्हें एक सैनिक के रूप में युद्धभूमि में ले गई थी।

लेखक बेहद खूबसूरत और इंग्लैंड के प्रमुख युवा कवि रुपर्ट ब्रुक के बारे में विस्तार से बताते हैं। विक्टोरियन दौर के पाखंड का विरोध करने वाले ब्रुक प्रगतिशील कवि थे, जिनकी शानदार कविताएं मृत्यु से साल भर पहले ही लिखी गई थीं। उनकी मृत्यु हालांकि बीमारी से हुई थी, लेकिन सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि युद्ध की विभीषिका के बीच अगर इनका जीवन नहीं बीतता, तो शायद अंग्रेजी कविता ब्रुक के कारण कुछ और समृद्ध व खूबसूरत होती। पुस्तक में रॉबर्ट ग्रेव्स और सिग्फ्राइड सैसून की दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता से संबंधित ब्योरे भावुक कर देते हैं। ये दोनों युद्ध में शहीद नहीं हुए थे, लेकिन युद्ध ने इनके शेष जीवन पर गहरा असर डाला था।

विल्फ्रेड ओवन की कहानी तो और भी मार्मिक है। महज पच्चीस साल के ओवन न केवल युद्ध में शहीद हुए, बल्कि उनकी मां को उनकी मृत्यु का टेलीग्राम ठीक उस दिन मिला, जिस दिन युद्ध के अंत का ऐलान हुआ। युद्ध-विरोधी कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में आंके गए ओवन की एक कवि के रूप में ख्याति उनकी मृत्यु के बाद ही फैली। दूसरी ओर, पेरिस में रह रहे अमेरिकी कवि एलन सीगर उन अपवाद कवियों में से थे, जिन्होंने युद्ध की अनिवार्यता और उसकी महानता के बारे में लिखा था।

हिंसा का निषेध करती यह किताब बताती है कि प्रथम विश्वयुद्ध के चार साल ने कितनी संभावनाशील काव्य प्रतिभाओं को असमय ही रौंद दिया। हिंसा के विरुद्ध लिखी गई इन कवियों की कविताएं इसलिए भी अमर हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ने युद्धभूमि में अपने प्राणों की बलि देकर मानवता का अमिट संदेश दिया है। आज जब एक से अधिक मोर्चे पर युद्ध और हिंसक संघर्ष मानवता की परीक्षा ले रहे हैं, तब कोर्डा की इस पुस्तक की प्रासंगिकता निस्संदेह और बढ़ जाती है।

अभियान

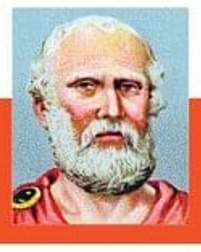

अच्छे से किया गया थोड़ा कार्य बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत सारे काम अपूर्णता से किए जाएं।
- प्लेटो, प्रसिद्ध दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh

■ मिथिलेश बारिया

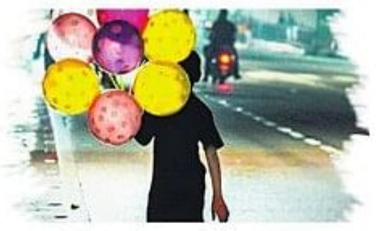

जिस उम्र में उसे गुब्बारों की
जिद करनी चाहिए,
उस उम्र में वो वही गुब्बारे बेच रहा है...

जिस पर लिखें... उन्हें बताया कीजिए,
यूं न अशआर अपने जाया कीजिए...

जिस सड़क के वो झूठे वादे करते रहे,
उसी टूटी सड़क से वो
काफिला लेकर आए हैं...

...और फिर डूब गया टाइटैनिक

आज ही के दिन सन 1912 में टाइटैनिक जहाज एक विशाल हिमखंड से टकराया था। यह हादसा रात 11.40 बजे हुआ था और 15 अप्रैल तड़के जहाज समुद्र में समा गया था। हादसे के वक्त इस जहाज पर करीब 2,200 लोग सवार थे, जिनमें से केवल 705 ही जीवित बच पाए थे। टाइटैनिक का निर्माण करने वाली कंपनी ने दावा किया था कि समुद्र में सबसे खराब स्थिति आने पर भी यह जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन हादसे के बाद जहाज को डूबने में 3 घंटे से भी कम समय लगा था। जहाज के निर्माताओं ने यह भी दावा किया था कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो इसे कम से कम 2-3 दिनों तक तैरना चाहिए। निर्माण के वक्त टाइटैनिक तब तक का सबसे बड़ा जहाज था। यह भारी-भरकम जहाज 230 मीटर लंबा और 25 मंजिल ऊंचा था। 14 अप्रैल की रात को वायरलेस ऑपरेटरों को क्षेत्र के अन्य जहाजों से बर्फ की कई चेतावनियां भी मिली थीं। बावजूद इसके जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। दुर्भाग्य से, जब तक निगरानीकर्ताओं ने विशाल हिमखंड को देखा, तब यह जहाज से केवल एक चौथाई मील से भी कम दूरी पर था, जिससे हिमखंड से इसके टकराव को रोकना एकदम नामुमकिन हो गया था।

झरोखा
14 अप्रैल

■ दिल्ली से किरण रस्तोगी

'हाथी बचाओ दिवस' 16 अप्रैल को है। हाथी बेहद ही शांत और मिलनसार जानवर माना जाता है। सदियों से हमारे साथी रहे हैं हाथी। फिर भी उनका शिकार होता है। क्या पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय जीव पर होने वाले अत्याचार को हम रोक नहीं सकते?

सदियों के साथी, मुसीबत में हाथी

उनके साथ यह अत्याचार क्यों?

हाथी नाम से प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में हमारे हाथ बनने के कारण ही इन्हें 'हाथी' नाम दिया गया होगा। हाथियों की प्रजातियां भी मनुष्यों के लालच के कारण संकट में हैं। हाथीदांत के लालच में प्रतिवर्ष न जाने कितने ही निर्दोष हाथियों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। लाख प्रयासों के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, इसीलिए अब प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को 'हाथी बचाओ दिवस' की मुहिम आरंभ हुई है। सन 2012 से डेविड वाइल्डलाइफ ट्रस्ट, केन्या की ओर से इस संबंध में पहल की गई। आज आवश्यकता है कि संपूर्ण विश्व के पशुप्रेमी सामने आएं और हाथियों पर होने वाले इस अत्याचार को रोकें। हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता मात्र हाथीदांत तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके और भी कई रूप हैं। शिशु हाथियों को उनकी माता से अलग कर दिया जाता है, ताकि हाथी बड़ा होकर सवारी बन सके। उन्हें बहुत ही सीमित भोजन देकर दिन भर बांधकर रखा जाता है। हाथियों के कान के पीछे की सबसे कोमल त्वचा वाले हिस्से पर अंकुश रखकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। 2020 में केरल में एक गर्भवती हथिनी को कुछ शरारती लोगों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था। वह अनानास हथिनी के मुंह में फट गया था। तीन दिन तक वो पानी में खड़ी तड़पती रही और उसकी मौत हो गई थी। जंगलों में आततायियों की भांति घुस चुके मनुष्य से इस जीव को बचाना आवश्यक है। हाथी पृथ्वी पर सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी है। उसकी स्मृति भी अद्भुत होती है। अनेक खूबियों से भरे इस जीव को देखकर एक विश्वास पक्का होता है कि जब इतना विशालकाय प्राणी शाकाहारी हो सकता है तो हम क्यों नहीं? हाथी बचाओ दिवस पर हमको कहना चाहिए - 'हाथी मेरे साथी'।

चिट्ठी 1

■ प्रांजल सक्सेना, बरेली

बीमा पॉलिसी की पूरी जानकारी

बीमा एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक कंपनी एक निर्दिष्ट (निर्देश किया गया) प्रीमियम के भुगतान के बदले में निर्दिष्ट नुकसान, क्षति, बीमारी या मृत्यु के लिए मुआवजे की गारंटी प्रदान करने का वचन देती है। आम आदमी जब जीवन बीमा, टर्म प्लान और मेडीक्लेम आदि लेता है तो वह निश्चित ही अपने खर्चों को कम करके भविष्य के लिए बीमा में निवेश करता है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिसी लेते समय समुचित जानकारी न देने के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। विपत्तियों के समय मदद मिलने के बदले कोई न कोई कारण बताकर बीमा कंपनी उनका पैसा रिलीज नहीं करती है, फिर उपभोक्ता अपने एजेंट और संबंधित कंपनी को कोसने लगता है। स्थिति यह हो जाती है कि पॉलिसी पास होने के बावजूद भी आम नागरिक को अपने करीबी, नाते-रिश्तेदार और दोस्त आदि से पैसा उधार लेकर बिल चुकाना पड़ता है। बीमा देने वाली कंपनियों को भी अपने एजेंट के माध्यम से यह सुनिश्चित करवाना चाहिए कि वह जो बीमा पॉलिसी दे रहा है, उसके फायदे के साथ और नुकसान भी बताता चले। आमजन को भी चाहिए कि कोई भी पॉलिसी खरीदते समय उससे जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करें, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत या परेशानी न आए।

चिट्ठी 2

■ लक्ष्मण पुंडीर, श्रीनगर गढ़वाल

दवा व्यापार में भ्रामक विज्ञापन

स्वास्थ्य वर्धक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के भ्रामक विज्ञापनों से हमें सावधान रहना होगा। दवा बाजार में बिकने वाली अधिकांश अंग्रेजी दवाएं गुणवत्ता और भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में विरोधाभासी हैं। कहना गलत न होगा कि पूरे दवा व्यापार में भ्रामक विज्ञापनों की भरमार है। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे विशिष्ट रोग विशेषज्ञों की कृपा से गुणवत्ता विहीन दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। शुगर जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने का दावा करने वाली दवाएं भी अपने दावे पर खरी नहीं उतर रही हैं। बाजार में बिकने वाली अधिकांश क्रीम, जो चेहरे और त्वचा पर निखार लाने का दावा करती हैं, वे सब असमर्थ हैं। सौंदर्य प्रसाधन और गंभीर रोग निदान हेतु प्रसारित विज्ञापनों की एक बड़ी सूची है, जिसकी ओर अब तक न तो चिकित्सकों की अगुवाई करने वाली संस्था का ध्यान गया है और न ही जागरूक नागरिकों का। उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रति सख्ती अपनाए जाने से जन-मानस में यह उम्मीद बढ़ी है। अब आम आदमी भ्रामक विज्ञापनों को चुनौती देगा। जन-स्वास्थ्य से होने वाले खिलवाड़ को रोकने के लिए अपनी सजग और सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना जरूरी है। इस जोखिम को कम करने के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित स्वास्थ्य अलर्ट, सुरक्षा अलर्ट, उत्पाद अधिसूचनाएं और रिकॉल के बारे में अपडेट रहना महत्वपूर्ण है।

चिट्ठी 3

■ डॉ. सुधाकर आशावादी, मेरठ

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं | जौनपुर से मिथिलेश मौर्या, मेरठ से पारस जैन, बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, जालंधर से राजेश कुमार चौहान, पटना से मुकेश कुमार मनन, सूरत से कांतिलाल मंडोत, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, बरेली से गौरव हिन्दुस्तानी, इंदौर से अमृतलाल मारू 'रवि', मेरठ से रचना रस्तोगी, दिल्ली से रेखा आर्य।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

यह पेड़ है या पानी की बोतल

क्या आपको पता है कि 'बाओबाब' नाम का पेड़ अपने तने में ढेर सारा पानी जमा कर सकता है। कुछ लोग इस पेड़ का इस्तेमाल जेल और डाकघर के रूप में भी करते हैं।

अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के निचले इलाकों में 'बाओबाब' नाम के पेड़ पाए जाते हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार, ये पेड़ विशाल आकार तक बढ़ सकते हैं और 3,000 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। इन पेड़ों को यहां कई नामों से जाना जाता है, जैसे - बोआब, बोआबोआ, तबाल्डी, बॉटल ट्री और उल्टा पेड़ आदि। इस पेड़ की आठ प्रजातियां हैं - छह मेडागास्कर में, एक-एक अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ को सबसे ज्यादा नुकसान सूखा, जलभराव, बिजली, हाथी और काले कवक से होता है। इस पर फूल रात में खिलते हैं। यह पेड़ अपने तने में बड़ी मात्रा में पानी जमा कर सकता है, इसलिए हाथी, एलैंड (दक्षिणी अफ्रीका का एक बड़ा मृग) और अन्य जानवर शुष्क मौसम के दौरान इसकी छाल चबाते हैं।

मनुष्य आश्रय, समारोह, भोजन, दवा, फाइबर और जूस सहित कई उद्देश्यों के लिए बाओबाब पेड़ का उपयोग करते हैं। बबून और वॉर्थोग जैसे जानवर इसके बीज की फली खाते हैं। पक्षी विशाल शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं, उल्लू और ग्राउंड हॉर्नबिल तने के खोखलों में बसेरा करते हैं। मुड़े हुए तने और खोखले आंतरिक भाग अनगिनत सरीसृपों, कीड़ों और चमगादड़ों को भी घर प्रदान करते हैं। टार्टर की क्रीम (खाना पकाने की एक सामग्री) शुरू में अम्लीय बाओबाब बीज के गूदे से बनाई गई थी, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से वाइन बनाने की प्रक्रिया से उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ के भारी-भरकम तने का उपयोग रचनात्मक कार्यों के अलावा जेलों और डाकघरों के रूप में भी किया जाता है।

■ अर्पित सिंह, अंबाला

नसीर भाई ! सुन लो मेरी बात

तस्वीर बड़ी पुरानी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) की ओर से एक नाटक में अभिनेता ओम पुरी (दिवंगत) और नसीरुद्दीन शाह। दोनों एनएसडी के छात्र रहे हैं।

■ गुरुग्राम से अंश सिंह

छायानट

अमिताभ ने सात दिनों तक नहीं धोया मुंह

अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' की शूटिंग गोवा में चल रही थी। हिंदी सिनेमा के जाने-माने मेकअप आर्टिस्ट पंढरी जुकर फिल्म के सभी कलाकारों का मेकअप कर रहे थे। किरदार में ढलने के लिए अमिताभ को उन्होंने दाढ़ी लगाई थी, लेकिन अचानक पंढरी जुकर को किसी काम से 7 दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ा था। तब उन्होंने अमिताभ से पूछा, "अब तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं तो गोवा में नहीं हूं।" अमिताभ ने जवाब दिया, "मैं इस मेकअप को संभालकर रखूंगा।" अमिताभ चेहरे के नीचे पानी डालकर नहाते रहे और उसी लुक के साथ अगले 6 दिन बिना मुंह धोए लगातार शूटिंग की। जब मेकअप आर्टिस्ट वापस आए तो देखा कि अमिताभ के चेहरे पर दाढ़ी सही-सलामत थी। वो कैसे सोए होंगे? कैसे खाना खाया होगा, ये सब सोचकर सब बहुत हैरान थे। तब पंढरी जुकर ने उनको कहा था, "तुम बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारा काम के प्रति यह प्रेम तुम्हें एक दिन सुपरस्टार बनाएगा।"

■ राम वर्मा, कुल्लू

इरादों का घोषणापत्र

उनके सिपहसालार पहले किए गए वायदों को चुनावी जुमला बताकर फारिग हो सकते हैं, लेकिन मेरा वोट उसे जाएगा, जो संघीय मूल्यों की रक्षा करेगा, अपने वायदों को याद रखेगा और संविधान, संसदीय लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वतंत्रता व निजता के आदर्शों को कायम रखेगा।

एक घोषणापत्र उन मुद्दों पर इरादों और विचारों का एक लिखित रूप है, जो लोगों के लिए मायने रखते हैं। इसकी कुछ मिसालें जो ध्यान में आती हैं, वे हैं, अमेरिका में 1776 की स्वतंत्रता घोषणा और 14-15 अगस्त,1947 के दरम्यान जवाहरलाल नेहरू का 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' वाला भाषण। इसी तरह 24 जुलाई, 1991 को डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने यादगार भाषण में, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को ही बदल दिया था, विक्टर ह्यूगो को उद्धृत करते हुए कहा था, 'पृथ्वी की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका समय आ गया हो।' इन बयानों/भाषणों ने नए शासकों के इरादों की स्पष्ट रूप से घोषणा की। दूसरी ओर, यह भी संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान या भाषण उसके असल इरादों को छिपाने वाला हो। ऐसे ही कुछ बयान हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को परेशान करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, 'मैं प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये डालूंगा', 'मैं प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा', 'मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा' इत्यादि। उनके सिपहसालार इन्हें चुनावी जुमला बताते हैं। देश में अखिल भारतीय स्तर वाले दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही हैं। भाजपा ने 30 मार्च को अपनी घोषणापत्र समिति का गठन किया, जबकि कांग्रेस ने पांच अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी किया। काश, मैं अपने इस लेख में दोनों घोषणापत्रों की तुलना कर पाता, लेकिन फिलहाल सिर्फ कांग्रेस का ही घोषणापत्र उपलब्ध है। इसलिए मैं उन प्रमुख कसौटियों का जिक्र करूंगा, जिनके आधार पर पाठकों और मतदाताओं को दोनों राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों की तुलना करनी चाहिए।

भारत का संविधान

कांग्रेस ने कहा, 'हम दोहराते हैं कि भारत का संविधान हमारी कभी न खत्म होने वाली यात्रा में एकमात्र मार्गदर्शक और साथी रहेगा।' लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या भाजपा संविधान का पालन करेगी या इसमें आमूल-चूल संशोधन करेगी। यह सवाल एक राष्ट्र, एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, नागरिकता संशोधन अधिनियम (जो फिलहाल शीर्ष न्यायालय में चुनौती के अधीन) जैसे अस्थिर करने वाले और विभाजनकारी विचारों के संदर्भ में उठा है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह संविधान में निहित संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर सिद्धांतों का पालन करेगी।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, आरक्षण

कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। वह आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन कराएगी। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी का आरक्षण सभी जातियों और समुदायों के लिए खुला रहेगा। कांग्रेस एक विविधता आयोग की भी स्थापना करेगी, जो रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देगा। भाजपा को भी अपने इरादे स्पष्ट करने चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि समानता के मुद्दे पर दोनों दल कहां खड़े हैं।

अल्पसंख्यक

भारत में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसका मानना है कि सभी भारतीयों को समान रूप से मानव अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें किसी धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है और इसमें बहुसंख्यवाद और अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। बहुलतावाद और विविधता भारत के लोकाचार के हिस्से हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर 'तुष्टिकरण' का आरोप लगाया है, जो उसके जग-जाहिर अल्पसंख्यक विरोधी दृष्टिकोण का कोड-नाम है। क्या भाजपा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने और समान नागरिक संहिता पारित करने के अपने दृढ़ संकल्प को फिर से दोहराएगी? चूंकि, धार्मिक अल्पसंख्यक इन दोनों कानूनों को भेदभावपूर्ण मानते हैं, इसलिए उन्हें भाजपा के घोषणापत्र का इंतजार है।

युवा और नौकरियां

असंतोषकारी औसत विकास दर (5.9 फीसदी), स्थिर विनिर्माण क्षेत्र (जीडीपी का 14 फीसदी), कम श्रमबल भागीदारी दर (50 फीसदी) और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी (स्नातकों में 42 फीसदी) के चलते देश का जनसांख्यिकीय लाभांश कम हो रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नौकरियों में 30 लाख रिक्तियों को भरने, अप्रेंटिसशिप के अधिकार संबंधी कानून को पारित करने, कॉरपोरेट्स के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू करने, जो नई नौकरियां पैदा करेगी और स्टार्ट-अप योजना को बढ़ावा देने के लिए एक कोष की स्थापना करने का वादा किया है। इससे जाहिर तौर पर युवा उत्साहित हैं। भाजपा-राजग सरकार के पास युवाओं के लिए नौकरियों की कोई भरोसेमंद योजना कभी रही ही नहीं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल भाजपा इससे ज्यादा आकर्षक योजना पेश कर पाएगी।

महिलाएं

चुनावी प्रक्रिया में महिलाएं सबसे उत्साही भागीदार रही हैं। वे प्रचार के लिए दिए जा रहे भाषणों को सुनती हैं और फिर आपस में बहस करती हैं। यह बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि कांग्रेस के तमाम वादे सही साबित हुए हैं। चाहे वह महालक्ष्मी योजना (प्रत्येक गरीब परिवार को हर साल एक लाख रुपये) हो, मनरेगा के तहत रुपये 400 की दैनिक मजदूरी हो, महिला बैंक का पुनरुद्धार हो या फिर चाहे केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का वादा ही क्यों न हो। क्या भाजपा हिंदुत्व की अपील से आगे बढ़कर ठोस योजनाओं के साथ आएगी, यह देखना है।

संघवाद

सबसे चर्चित मुद्दा है भाजपा का अधिनायकवाद। भाजपा ने संघवाद और भारत के राज्यों का संघ होने की सांविधानिक घोषणा को कमजोर किया है। एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार बेहद संदेहास्पद है। यह सिर्फ एक सरकार, एक पार्टी और एक नेता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में संघवाद पर एक अध्याय में 12 बिंदु हैं, क्या भाजपा इनमें से किसी पर भी सहमत है? इसमें सबसे दूरगामी वादा कुछ क्षेत्रों को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने पर आम सहमति बनाना है। इन 12 बिंदुओं पर ही भाजपा की साख की परख होगी। जहां तक मेरा मानना है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा संविधान, संसदीय लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वतंत्रता व निजता और सांविधानिक नैतिकता के प्रति चुनाव लड़ने वाले दलों की प्रतिबद्धता है। मेरा वोट उसको जाएगा, जो इन सिद्धांतों की शपथ लेगा और इन्हें कायम रखेगा।

Licensed by
The Indian Express Limited

बाबा साहब ने देखा था जो सपना

14 अप्रैल दलितों, पिछड़ों, महिलाओं तथा दुनिया के अन्य वंचित वर्गों के लिए एक महापर्व का दिन होता है। 1891 में 14 अप्रैल के दिन इंदौर की महू छावनी में सूबेदार राम जी सकपाल और माता भीमा बाई के घर डॉ. भीमराव राव आंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉ. आंबेडकर ने 1924 में अखिल भारतीय 'दलित महासभा' नाम से एक सामाजिक संगठन तैयार किया और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। फिर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वैसे तो दलित महासभा के नाम की वजह से यह आभास होता है कि शुद्ध रूप से यह दलितों का संगठन होगा, लेकिन इस संगठन के दो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज से और अन्य कई जाति के लोग इसके पदाधिकारी थे। कालांतर में जब यह संगठन अपने कार्यों एवं उद्देश्यों में सफल होने लगा तो कई गैर ब्राह्मण लोगों ने बाबा साहब से मिलकर यह अनुरोध किया कि वे लोग इस सामाजिक संगठन के बैनर तले सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, बशर्ते दोनों ब्राह्मण उपाध्यक्षों को संगठन से निकाल दिया जाए। बाबा साहब ने उनके प्रस्ताव को सम्मान तो दिया, लेकिन ब्राह्मण उपाध्यक्षों को निकालने की शर्त को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उनका संघर्ष देश में व्याप्त ब्राह्मणवाद से है, न कि ब्राह्मणों से। हम यह भी बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवनकाल में अपने विचारों के चलते अनेक कठिनाइयों का सामना किया तो भी भारत के संविधान की रचना करते हुए उन्होंने किसी ब्राह्मण, सवर्ण या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध बदले की भावना से कोई कार्य नहीं किया। बाबा साहब का कट्टर अनुयायी होने के कारण मेरा भी यह मानना है कि अछूत, पिछड़े या गरीब परिवार में पैदा होने को पूर्व जन्मों का दुष्परिणाम तथा ब्राह्मण या अन्य उच्च कुल में पैदा होने को अच्छे कर्मों का फल बताना सरासर गलत है। इसलिए बाबा साहब को याद करते हुए हमें दलितों, कमजोर वर्ग की महिलाओं एवं अन्य वंचित लोगों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का यही सपना था।

आंबेडकर स्मरण

राम समुझ

खुला आकाश

डॉ. भीमराव राव आंबेडकर द्वारा किए गए सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बड़े आदर से उन्हें 'बाबा साहब' के नाम से पुकारने लगे।

https://t.me/AINewsPaperPdf

लोकसभा के पहले चरण का चुनाव करीब है, प्रचार अभियान चरम पर है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान माहौल बेहद नीरस प्रतीत हो रहा है। न ही सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही बातों में नवीनता है, फ्यूचर रोडमैप है और न ही सत्ता पक्ष अपने दस वर्ष के काम के भरोसे के साथ जनता से संवाद कर पा रहा है, न ही विपक्ष नए भारत के निर्माण के लिए कोई आकर्षक विकास मॉडल पेश कर पा रहा है। यहां तक कि विपक्ष गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, टिकाऊ अर्थव्यवस्था जैसे जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पा रहा है। इस चुनाव के प्रचार अभियान को देखें तो राष्ट्रवाद, सनातन, शक्ति, गारंटी, भ्रष्टाचार, संविधान, लोकतंत्र आदि मुद्दों पर ही सत्ता पक्ष व विपक्ष का संवाद केंद्रित है। जनसरोकार के मुद्दे खामोश हैं। यह जरूर है कि चुनाव प्रचार अभियान में भाजपा सभी दलों से बहुत आगे है। चुनावी रैली से लेकर डिजिटल और ओपिनियन बिल्डिंग के हर हथकंडे को भाजपा अपना रही है, जबकि कांग्रेस मोदी व भाजपा विरोध से आगे नहीं निकल रही है। मिशन 2024 के लिए चुनावी मुद्दों का विश्लेषण करता आजकल का यह अंक...

इस चुनाव में गंभीर मुद्दे खामोश क्यों

विश्लेषण

सुशील राजेश

वरिष्ठ पत्रकार

राहुल गांधी ने 'गरीबी मिटाओ' का एक फॉर्मूला दिया है। उनके मुताबिक, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपये सालाना जमा कराए जाएंगे। क्या कांग्रेस ने ऐसी योजना के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है? गरीबी-रेखा की परिभाषा तक निश्चित नहीं है। देश में गरीबी की स्थिति क्या है, उसे लेकर भी विरोधाभास हैं। गरीबी ही देश का बुनियादी मुद्दा नहीं है। इसके अलावा, बेरोज़गारी, महंगाई, किसानी, महिला अपराध, शहरीकरण, युवा आक्रोश, पर्यावरण आदि कितने ही मुद्दे हैं, जो आम चुनाव में गूंजने चाहिए थे। जनादेश का आधार भी यही मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन इन्हें प्रासंगिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'गरीबी मिटाओ' का एक फॉर्मूला दिया है। उनके मुताबिक, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपये सालाना जमा कराए जाएंगे। वह गरीब परिवार किसान, मजदूर या किसी का भी हो सकता है, उस परिवार की महिला को 8500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद तब तक जारी रहेगी, जब तक वह परिवार गरीबी-रेखा से बाहर नहीं आ जाता। क्या कांग्रेस ने ऐसी योजना के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है? सबसे अहम सवाल तो गरीबों की संख्या का है। दरअसल ऐसे गरीबों की देश में कितनी संख्या है, यह न तो कांग्रेस को पता है और न ही सरकार यह डाटा साझा करना चाहती है। गरीबी-रेखा की परिभाषा तक निश्चित नहीं है। देश में गरीबी की स्थिति क्या है, उसे लेकर भी विरोधाभास हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर आर्थिक असमानता के यथार्थ को दोहराया है। देश के 22 सबसे अमीर भारतीयों के पास इतना धन है, जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। राहुल गांधी के अनुसार, मोदी सरकार ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ किए हैं। यह देश के महज 25-30 धन्नासेठों की इतनी राशि है, जितनी 24 साल तक मनरेगा के जरिये मजदूरों को दी सकती थी। राहुल यह चुनाव देश के गरीबों और 22-25 अरबपतियों के बीच की लड़ाई मानते हैं। यह वामपंथी सोच का विश्लेषण है। पर असल मुद्दे ये ही नहीं हैं।

गरीबी ही बुनियादी मुद्दा नहीं

सिर्फ गरीबी ही देश का बुनियादी मुद्दा नहीं है। इसके अलावा, बेरोज़गारी, महंगाई, किसानी, महिला अपराध, शहरीकरण, युवा आक्रोश, पर्यावरण आदि कितने ही मुद्दे हैं, जो आम चुनाव में गूंजने चाहिए थे। जनादेश का आधार भी यही मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन इन्हें प्रासंगिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष की तो मूल चिन्ता है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन मुद्दों की हिन्दूवादी व्याख्या कर रहे हैं, जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की गलतियों से पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री के पास गिनाने को ढेरों काम हैं, जो उनकी 10 साला सरकार के दौरान किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई के नाम उन संदर्भों में लेते हैं, जो सरकार के पक्ष के हों। गरीबी के मद्देनजर यदि अरबपतियों के पास बेइंतहा आर्थिक संसाधन हैं, तो उनकी कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं और करोड़ों रुपये के कर भी अदा करती हैं। बहरहाल राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस देश से खटाखट गरीबी को मिटा देना चाहती है। हमारी जो गारंटी है, उसके जरिए हम एक ही झटके में गरीबी समाप्त कर देना चाहते हैं। यह सिर्फ चुनावी जुमला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में जनादेश के आसार रत्ती भर भी नहीं हैं। यह एहसास राहुल गांधी को भी है।

गरीबी पारिभाषित नहीं

राहुल गांधी की दादी एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था और प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता था। उसके बाद की कांग्रेस सरकारों में भी 'गरीबी' एक बुनियादी एजेंडा रहा, लेकिन एक समय आया था, जब 'योजना आयोग' (अब नीति आयोग) भी मानता था कि करीब 30 करोड़ भारतीय गरीबी-रेखा के नीचे जीने को अभिशप्त हैं। समितियां बनाई गईं, फॉर्मूले तय किए गए, लेकिन सही डाटा देश के सामने पेश नहीं किया जा सका। यूपीए सरकार के दौरान मोंटेक सिंह आहलूवालिया 'योजना आयोग' के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि जो व्यक्ति 32 रुपये और 27 रुपये क्रमशः शहर और गांव में रोज़ाना कमाता है, तो वह गरीबी-रेखा के नीचे नहीं है। कितना हास्यास्पद फॉर्मूला था? फिर भी गरीबी-रेखा को पारिभाषित नहीं किया गया। चूंकि अब प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंचों पर बार-बार दोहरा रहे हैं कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को 'गरीबी' से बाहर निकाला है। यानी प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं कि देश में 25 करोड़ गरीब रहे हैं, जिन्हें उस रेखा से उबारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ही देश के सामने है, अलबत्ता कोई बिन्दुवार और क्षेत्रवार आंकड़े देश के सामने नहीं रखे गए हैं। इसी दौर में आरएसएस के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबले ने एक आर्थिक आकलन सार्वजनिक किया था। उसके मुताबिक, देश में 23 करोड़ से अधिक भारतीय ऐसे हैं, जो 375 रुपये रोज़ाना की कमाई करने में भी असमर्थ हैं। वे भी गरीबी-रेखा के नीचे की आबादी हैं। सवाल है कि देश में कितने लोग गरीब हैं, जिन्हें आर्थिक मदद देकर उबारने की जरूरत है? प्रधानमंत्री मोदी देश में 81 करोड़ से अधिक लोगों को 'मुफ्त अनाज' बांट रहे हैं। जिन्हें हर माह 5 किलो अनाज की दरकार है और अभी यह योजना 5 और साल चलेगी। यदि ऐसे लोग गरीब नहीं हैं, तो उन्हें किस वर्ग में रखा जाएगा? मुफ्तखोरी की कई योजनाएं हैं और नकदी भी बांटी जा रहा है। ऐसा लगता है 90 फीसदी भारत गरीब है। सिर्फ धन्नासेठ और उनके सम्पन्न सलाहकार ही 'अमीर' हैं।

क्षेत्रवार गरीबों की संख्या

समाजशास्त्रीय और अर्थशास्त्र के आधार पर हमारा विश्लेषण एकांगी और गलत हो सकता है, लेकिन यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। वह अपनी सरकार के संबद्ध विभागों को आदेश दें कि वे गरीबी की परिभाषा स्पष्ट करें और क्षेत्रवार गरीबों की संख्या बताएं। उनके आधार भी स्पष्ट किए जाएं कि वे गरीबी-रेखा के नीचे क्यों हैं? गरीबी महज चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि एक अहम मानवीय सरोकार भी है। बीते दिनों भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की 'भारत रोज़गार रपट, 2024' को पेश किए जाने के अवसर पर कहा था कि सरकार बेरोज़गारी जैसी सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। फरवरी, 2024 में जो डाटा सामने आया था, उसके आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर 2023-24 में 7.6 फीसदी होगी। पहले 7.3 फीसदी का अनुमान लगाया गया था। भारतीय मौद्रिक समिति का भी आकलन है कि 2024-25 में भी विकास दर 7 फीसदी होगी। तो क्या विकास गरीबी नहीं कम कर पा रहा है?

83 फीसदी युवा बेरोज़गार

यदि हम इस विकास दर को सुनकर, पढ़कर गदगद होते हैं, तो कमोबेश यह हमारा सरोकार है। आर्थिक बढ़ोतरी के बावजूद श्रम बाज़ार, श्रम बल, रोज़गार आदि को लेकर चिन्ताएं बहुत हैं। आईएलओ की रपट में भारत में कुल 83 फीसदी युवा बेरोज़गार हैं। देश के कुल बेरोज़गारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी जो 2000 में 54.2 फीसदी थी, वह बढ़कर 2022 में 65.7 फीसदी हो गई थी। कृषि जैसे क्षेत्र में बेरोज़गारी बढ़ी है। मैन्यूफैक्चरिंग में भी रोज़गार की हिस्सेदारी स्थिर है। आईएलओ की रपट पर गौर करें, तो क्या औसत भारतीय बेरोज़गार है? क्या यह किसी सरकार, राजनीतिक दल और चुनाव का चिंतित मुद्दा नहीं होना चाहिए? जब युवा देश के भविष्य हैं, तो इन्हें नियोजित करने का दायित्व भी सरकार का ही है।

रोज़गार पैदा करने होंगे

यदि देश में युवा आक्रोश के हालात हैं, तो उनके लिए गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, खाली जेब आदि जिम्मेदार हैं। बेशक युवा बेरोज़गारी 2022-23 में कुछ कम हुई है, लेकिन यह भी तथ्य है कि औसतन हर साल 70-80 लाख नए कामगार श्रम बाज़ार में प्रवेश करते हैं। ये रोज़गार स्थायी नहीं हैं। यह बेरोज़गारी शहरी इलाकों के पढ़े-लिखे युवाओं में अधिक है। यदि इस वर्ग को देश के जनसंख्याई लाभांश में तबदील करना है, तो हर किस्म के, अधिकाधिक रोज़गार पैदा करने होंगे। इन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने होंगे।

शिक्षा नीति पर सवाल

उद्योग और सेवा-क्षेत्र में हुनरमंद रोज़गार बढ़ा है, लेकिन यह देश के श्रम-बाज़ार की जरूरतों के बिल्कुल विपरीत है। यदि नौकरी चपरासी की निकलती है, जिसके लिए शैक्षिक पात्रता 5वीं पास अपेक्षित है, लेकिन 3700 पीएच.डी. धारक बेरोज़गार भी आवेदन करते हैं, तो यह हमारी शिक्षा नीति पर भी सवाल है। क्या ऐसी व्यवस्था को विडंबना न माना जाए? विडंबना की स्थितियों की चर्चा चुनाव के दौरान नहीं होनी चाहिए? देश की कामकाजी उम्र की आबादी 63 फीसदी है। चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष के नेता राम मंदिर, सनातन, राष्ट्रवाद, मटन, मछली, आतंकवाद को घर में घुसकर मारना और सरकारी परियोजनाओं पर ही चुनाव प्रचार करते रहे हैं और विपक्ष का फोकस संविधान, लोकतंत्र को बचाने और सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने पर ही है। संविधान और लोकतंत्र को क्या खतरे हैं? यदि चुनाव हो रहे हैं और कई राज्यों में विपक्ष की भी सरकारें हैं, तो संविधान और लोकतंत्र को क्या चुनौतियां हैं? गरीबी और बेरोज़गारी देश में रहेगी, तो क्या देश प्रगति कर सकता है? रोज़गार मुहैया कराना सरकार के ही बुनियादी दायित्व हैं। यदि ऐसा नहीं होगा, तो देश में विविध अपराध पनपेंगे, अराजकता बढ़ेगी। लिहाजा हमारे राजनीतिक दलों को सबसे पहले चिन्तन करना चाहिए कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए? इस बार चुनावों में गंभीर जन मुद्दे खामोश क्यों हैं?

चुनाव प्रचार के बदल रहे तरीके

प्रचार ट्रेंड

डॉ. भारत

विधि व्याख्याता व चुनाव विश्लेषक

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिन-प्रति-दिन चुनाव प्रचार भी ज़ोर पकड़ रहा है। बदलते वक्त के साथ चुनाव प्रचार अभियान के साधन-संसाधन भी बदल रहे हैं। मौजूदा चुनाव में यह बदलाव साफ नज़र आ रहा है। इसे चुनाव आयोग की सख्ती का असर कहें या मतदाताओं की व्यस्त दिनचर्या या हर स्तर पर बढ़ती समझ व जागरूकता, जो भी हो, लेकिन अब चुनाव के दौरान वह रंग नजर नहीं आता, जो दशकों पहले तक दिखता था। अतीत पर नजर डालें तो धुआंधार नारेबाज़ी और प्लास्टिक व कागज़ के बिल्लों के लिए लपकते बच्चों वाली चुनाव प्रचार की तस्वीर जीवंत हो उठती है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रचार वाहनों, ऑटो व रिक्शा में लगे लाउडस्पीकरों के शोर से सड़कें गूंजने लगती थीं। सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ दीवारों को भी नारों से रंग दिया जाता था। प्रचार के लिए जगह-जगह झंडे लटकाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है।

चुनाव प्रचार के तरीके बदले

उपरोक्त पंक्ति वर्तमान चुनावी परिदृश्य को सही मायने में बयान करती है। इसमें कोई शक नहीं कि मतदाताओं तक अपनी विचारधारा व घोषणा-पत्र को पहुंचाने के लिए सभी राजनीतिक दल अथक प्रयास कर चुनावी मुहिम को गति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आज विज्ञान की उन्नति और सूचना-प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण के दौर में चुनाव प्रचार के तौर-तरीकों में भारी बदलाव आ गया है।

जनसंचार का दो-चरणीय सिद्धांत

आज राजनीतिक दलों के प्रचार के पीछे जनसंचार का एक सिद्धांत काम कर रहा है। इसके मुताबिक, लोग जानकारी व विचारों के लिए सीधे जनसंचार के किसी स्रोत पर कम ही निर्भर रहते हैं और अपनी जानकारी समाज के ही किसी और व्यक्ति से लेते हैं। वह व्यक्ति 'विचार नेता' (ओपिनियन लीडर) होता है, जिसकी बात सुनी और कई बार मानी भी जाती है। इसे 'दो-चरणीय सिद्धांत' कहते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मीडिया ने कुछ कहा या दिखाया और लोगों ने उसे मान लिया। यह टूल अपनाया जा रहा है।

प्रिंटिंग-प्रेस बनाम ऑनलाइन-कंटेंट

प्रचार सामग्री झंडे, बिल्ले, टोपी, बैनर, गमछे आदि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। बीते समय तक समाज के साक्षर वर्ग हेतु चुनाव-प्रचार काफी हद तक प्रिंटिंग-प्रेस में तैयार किए हुए पर्चों-इश्तिहार, पोस्टर, हैंडबिल या कार्ड पर निर्भर था। चुनाव दर चुनाव ऑनलाइन कंटेंट, रील, छोटे-वीडियो और वॉट्सअप मैसेज तैयार करने वालों की चांदी हो गई है तो प्रिंटिंग-प्रेस वालों के पास अब मामूली फ्लैक्स-बैनरों का ही काम रह गया है। 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर' आज चुनावी परिदृय में हावी हो गए हैं।

दूरदर्शन बनाम सोशल मीडिया

पहले दूरदर्शन टेलीविज़न पर राजनीतिक दलों को उनकी प्रस्तावित नीतियों और कार्यक्रमों को

प्रसारित करने के लिए निर्धारित समय आवंटित किया जाता था। सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण के आधुनिक समय में 'संवाद' के लिए सोशल मीडिया अब एक ज़रूरी साधन के रूप में उभरा चुका है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक लामबंदी के नए तरीक़े ईज़ाद किए हैं। राजनीतिक दल सोशल मीडिया के ज़रिये मतदाताओं को लुभाने के विभिन्न तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों की सक्रियता में भारी उछाल दर्ज़ किया गया है।

रैली में वर्चुअल जुड़ाव

पारंपरिक चुनावी रैली को काफी हद तक वर्चुअल प्रचार ने धूमिल कर दिया है। चुनावों में वर्चुअल प्रचार का प्रयोग करते हुए अब जनता से वीडियो लिंक के माध्यम से चर्चा करना व 3डी रैलियों के साथ जुड़ाव अब आम सी बात हो गई है। इसके जरिये राजनीतिक दल बहुत कम समय में अपने राजनीतिक संदेश को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। मोबाइल संचार का एक सबसे मजबूत माध्यम बन कर उभरा है। राजनीतिक दलों ने इसकी अहमियत को समझा और अपने चुनाव प्रचार के लिए ऐप का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐप के जरिये राजनीतिक कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं से सीधे जुड़ने का अनोखा तरीका इज़ाफ़ा हुआ है। हर छोटी-बड़ी राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी ऐप पर अपडेट की जाती है।

निगरानी समितियां

जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक स्तर पर एक सोशल मीडिया विशेषज्ञ भी इस समिति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए इस समिति से पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार, राजनीतिक विज्ञापन दाताओं के लिए एक तंत्र विकसित करना होता है। यह तंत्र चुनावी विज्ञापन के संबंध में कानून सम्मत नियम जारी करता है।

आचार संहिता का दायरा बढ़ा

अब आधुनिक चुनाव अभियान को भी 'आदर्श आचार संहिता' के दायरे में लाया गया है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्रचार पर भी निगरानी रख रहा है। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय दिए जाने वाले हलफनामे में अपनी ई-मेल और अन्य अधिकृत सोशल मीडिया एकाउंट्स की जानकारी देनी होती है। सोशल मीडिया अभियान पर खर्च का पूरा विवरण रखना होगा। इसमें कंटेंट के रचनात्मक विकास पर अभियान-संबंधी व्यय और सोशल मीडिया खातों को चलाने के लिए रखी गई टीम का पारिश्रमिक व उनके भुगतान को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी चुनाव के मद्देनज़र कंटेंट की निगरानी रखनी आवश्यक है।

'सुलगते' सवाल

सोशल मीडिया कई रास्ते तो खोल रहा है, परन्तु ढेरों सवाल भी खड़े कर रहा है। उदाहरणार्थ-क्या जो दल सोशल मीडिया में आगे रहेगा, उसके चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी? क्या सोशल मीडिया में बनाई हवा मतदाताओं के मत-व्यवहार को प्रभावित करती है? क्या सोशल मीडिया के जरिये चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रचार-प्रसार पर निर्भरता अच्छी है, लेकिन दूर-दराज के इलाकों का क्या? जिस प्रकार चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार प्रचार भी अभिन्न अंग है। जिसके बिना चुनाव अधूरा है और इसलिए, चुनाव में प्रचार का महत्व कहीं अधिक है। निष्कर्षतः चुनाव में पारदर्शिता और बराबरी के अवसर बनाए रखने के लिए डिजिटल माध्यम पर नियंत्रण समय की ज़रूरत है।

चुनावतंत्र में आंबेडकर के 'जन' कहां?

जयंती विशेष

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

शिक्षाविद् व विश्लेषक

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव उत्सव की तरह है। यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे संसार में आदर के साथ देखी जा रही है। इसे भारत के लिए हम एक सुखद अनुभूति के रूप में देख सकते हैं। इस सुखद में दुखद यह है कि जिसे पूरी पृथ्वी पर प्रतिष्ठा मिल रही है उसी लोकतंत्र में रहने वाले ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक गरीबी, भुखमरी और वंचना के शिकार हैं। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ऐसे ही लोगों के लिए संघर्ष किया था, किन्तु उनके संघर्ष को इतना कमजोर बना दिया गया कि अब डॉ. आंबेडकर के जीवन-दर्शन व मूल्यों को छोड़कर अपने फायदे के लिए जीने वाले मनुष्य समाज की संरचना हो गई है। जन-मन के आंबेडकर का जनतंत्र में जन इतना कमजोर हो गया है कि उसकी आवाज़ अब मौन की ओर बढ़ने लगी है।

लोकतंत्र में बड़ा वैक्यूम

यह जन-मन के आंबेडकर का जनतंत्र में जन डीएस फोर, बामसेफ जैसे धड़े के उभार के साथ देखा गया था। यह समय के साथ बहुजन समाज के रूप में खुद को पारिभाषित किया। बहुजन समाज पार्टी का उभार और मायावती के आगाज से भारत में यह विश्वास हो गया था कि अब आंबेडकर के जन देश के जनतंत्र को आगे ले जाएंगे। मायावती का राजनीति में बढ़ता कद भारतीय राजनीति में भूचाल था, लेकिन जो मायावती कई बार एक बड़े सूबे की राजनीति करती रहीं, उनका निर्बल हो जाना, आज भारतीय लोकतंत्र में बड़ा वैक्यूम ला दिया है। यह जो मायावती का निर्बल मन है, इसका आज कोई उत्तर भारतीय राजनीति में नहीं मिल रहा है। कांशीराम के बाद मायावती ने जो अपना कद बनाया था, उस पर जो ग्रहण लगा इससे काफी अब सवाल खड़े हो गए हैं, इसे तो मानना पड़ेगा।

जन की ताकत

वैसे, जनतंत्र में जन की अपनी ताकत होती है। जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी तो भारत की निवर्तमान ताकत में जन विद्यमान हो, ऐसी कोशिश पूरी संविधात्री सभा ने किया। अब हमारे भारतीय लोकतंत्र की ताकत कौन है, इसका भी विश्लेषण हो रहा है। कौन होम चढ़ा, किसने मलाई खाई और कौन कितना विकास करके देश की मुख्यधारा का हिस्सा बना, यह किसी से छुपा नहीं है। डॉ. आंबेडकर का स्मरण करें उन्होंने प्रारूप सभा में कहा था कि जिस रूप में प्रारूप संविधान तैयार किया गया है उसमें देश के शासन के लिए केवल तंत्र की व्यवस्था की गई है। यह किसी खास बल को सत्तारूढ़ करने का उपाय नहीं है जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। यदि व्यवस्था को लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरना है तो यह जनता पर छोड़ दिया जाए कि वह किसे चुनकर सत्ता में लाए, लेकिन जो भी सत्ता में आएगा वह अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। भला हो इस देश का कि इस देश में इतनी आत्मशक्ति है जन में और जन के प्रतिरोध में कि बहुत कुछ धारा के विपरीत होने के बावजूद आंबेडकर का आम आदमी अभी लड़

रहा है व्यवस्था से, उसने इस भारतीय लोकतंत्र में अपने आप को मौजूदा हालत से लड़ने के काबिल बचा रखा है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सत्ता में जो कोई आया वह आंबेडकर के 'जन' जिसे डॉ. आंबेडकर खुद सशक्त होकर अपने पांव पर देखना चाहते थे उन्होंने किस स्तर पर उन्हें पूर्णतया सहयोग किया। भारत के बौद्धिक समाज ने बड़े पैमाने पर आंबेडकर के 'जन' के लिए कितना सहयोग हो रहा है, कितना नहीं, इस पर कदाचित टिप्पणी की, आवाज़ उठाई, प्रतिरोध के साथ समाधान सुझाया लेकिन आज भी देखा जाए तो उनकी स्थिति दमित व वंचित में ही शामिल है।

सबसे बड़ा सवाल

भारत में एक बार पुनः चुनाव हो रहा है तो कोई न कोई अपनी बहुमत से सत्ता पाएगा और सत्ताधीश होकर देश को नेतृत्व प्रदान करेगा लेकिन जन-मन के आंबेडकर का जनतंत्र में जन की स्थिति क्या होगी? क्या वह अपने किसी नेतृत्वकर्ता के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएगा या फिर जो खुद तक सिमट जाने की एक भ्रामक सी रेस है, वही उसकी नियति है, यह बड़ा सवाल है। आंबेडकर का जन इतना कमजोर यदि हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा? कॉर्पोरेट घराने अपनी किसी भी सुविधा व साधन के करीब नहीं आने देंगे। जब चुनाव कार्पोरेट लड़ेंगे, सत्ता भी कार्पोरेट चलाएगी और नीति व नियति भी देश का कार्पोरेट ही तय करेंगे तो बेवजह की बहस किस बात के लिए है? देखा जाए तो भारत में चुनाव का व्याकरण ही अलग हो गया है। जिस मायावती के सहारे दमितों व वंचितों को बल मिलता था, जिस मायावती में आंबेडकर के जन अपने अस्तित्व को देख रहे थे,वे तो मिट गए हैं। कार्पोरेट का साजिश भरा लोकतंत्र अब जाति को टूल्स की भांति प्रयोग कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से मायावती इतना कमजोर नहीं होतीं।

समतामूलक समाज की संकल्पना

डॉ. आंबेडकर ने जिस समतामूलक समाज की संकल्पना की थी उसकी इस लोकतंत्र उपस्थिति कैसे बनेगी? डॉ. आंबेडकर ने जिस सत्ता की कल्पना कि थी, उसकी कोई संभावना है क्या? यदि है तो वह कैसे हमारे लोकतंत्र में आएगी? यदि आंबेडकर के जन के नेतृत्व ही सवालों के घेरे में हैं तो अब विकल्प क्या है? चुनाव जब आते हैं तो दरअसल, उस बड़े समाज की यह परीक्षा की घड़ी होती है जिस धड़े में ज्यादा से ज्यादा लोग जरूरतमंद हैं। अपने संघर्ष के समय में व्यावहारिक स्तर पर ही इस संवेदना को डॉ. आंबेडकर सबके चेतना का हिस्सा बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि देश की मुख्यधारा में घृणास्पद जिंदगी जीने वाले लोग गरिमा से जिएं।

सामर्थ्य कैसे सशक्त होगी

सवाल यह है कि जब आज जन-मन के आंबेडकर का लोकतंत्र में जन दुखी है तो उसकी सामर्थ्य कैसे सशक्त होगी? एक वैकल्पिक नेतृत्व व शक्ति की खोज में लगी भारत की बड़ी आबादी अपने आज के लिए भले न ज्यादा चिंतित हो, लेकिन कल के लिए जरूर उसे फिक्र है। इसका समाधान भारत में निरंतर होने वाले चुनाव यदि नहीं दे पाए तो खुद के लिए जीने वाली कौमें आंबेडकर के जन को कभी उभरने नहीं देंगी। डॉ. आंबेडकर का जन्मोत्सव ऐसे समाधानों की मांग करता है और एक ऐसे विकल्प की खोज में है जो उसे गरिमा प्रदान कर सकें। भारत में सत्ता की डोर से चिपकी ताकतें कभी यह नहीं चाहतीं कि सब सुखभोग करें। डॉ. आंबेडकर के सपनों को साकार करने वाले यदि आज उनको चिह्नित करके नहीं प्रतिरोधी स्वर बुलंद करेंगे तो चुनाव होते रहेंगे, सत्ताएं आती रहेंगी और आंबेडकर का जन दुःख की गगरी में डूबा रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम डॉ. आंबेडकर की मंशा को समझें व जन-मन के आंबेडकर का जनतंत्र में जन के सुख का आधार बनें, क्योंकि सबकी उन्नति में ही भारत की उन्नति निहित है।